चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 16 नवंबर–22 नवंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

दो महानायक

बिहार चुनाव संपूर्ण देश के लिए आंख खोलने वाला चुनाव है. बिहार चुनाव यह बताता है कि सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करने या नरेंद्र मोदी एवं अरूण जेटली वाला मॉडल बताने से विकास नहीं होता. हमारे देश में कितना पैसा एफडीआई में आया, कितना पैसा मेक इन इंडिया में आया, कौन-सी कंपनियां आईं, सफाई हुई या नहीं, स्वच्छ भारत अभियान सहित जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने घोषित की थीं, उनकी प्रगति क्या हुई आदि बातों ने बिहार के ग़रीबों को, मध्यम वर्ग को, यहां तक कि उच्च-मध्यम वर्ग को भी सशंकित कर दिया और उन्हें लगा कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बन गई, तो वह बड़े पुलों एवं बड़ी सड़कों की तो बात करेगी, लेकिन गांव, सड़क, किसानों की फसल, लड़कियों की शिक्षा की बात नहीं करेगी. बिहार में सड़कों का जाल नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, उसे सुशील मोदी के खाते में डालने की भाजपा की कोशिश बिहार की जनता ने नकार दी.

संतोष भारतीय

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आठ नवंबर को सामने आए, जिन्होंने बहुत सारी चीजें साफ़ कीं. चुनाव परिणामों ने यह बताया कि जनता के सामने चाहे जितना भ्रम खड़ा किया जाए, जनता को चाहे जितना बहकाने की कोशिश की जाए, जनता बहकती नहीं है और बातों के बीच में से अर्थ समझ लेती है और उस अर्थ को समझ कर निर्णायक वोट देती है. बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के महा–गठबंधन को निर्णायक जीत मिली और दो तिहाई से ज़्यादा सीटें उनके खाते में आ गईं. आठ नवंबर को टेलीविजन चैनल पर हुई चर्चा में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्वीकार करने में बहुत तकलीफ हो रही है. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर दुर्भाग्यपूर्ण फ़ैसला करार दिया. यह मानसिकता बताती है कि जनता के निर्णय के प्रति कैसे सम्मान कम होता है. बिहार का फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, पर देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, यह सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रवक्ता ही सोच सकते हैं. वैसे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा एवं संबित पात्रा सहित जो चेहरे टेलीविजन पर आते थे, उनका गुरूर, उनका अहंकार, उनका अभिमान और उनकी भाषा की कठोरता देखकर डर लगता था. शायद बिहार की जनता को भी यह डर लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को पूरी तरह बेनकाब भी कर दिया और ठुकरा भी दिया. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नेताओं को दरकिनार करके पूरा चुनावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर चलाया. उसे यह लगा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर भरोसा कर वैसा ही समर्थन देगी, जैसा उसने हरियाणा में दिया. भारतीय जनता पार्टी यह भूल गई कि हरियाणा के साथ ही झारखंड का चुनाव हुआ, जहां उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला. उसे सहयोग से या जोड़–तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी. भारतीय जनता पार्टी यह भी भूल गई कि दिल्ली में रहने वाले लोग सारे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने जब आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनवाई, तो वह बहुमत असामान्य बहुमत था. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ़ तीन सीटें मिली थीं और उस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि यह तो नगर निगम का चुनाव था, जिसमें जीत या हार का कोई मतलब नहीं होता, लोगों के फ़ैसले के प्रति उसके असम्मान को दर्शाता है. अब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को औसत रूप में वहीं पहुंचा दिया है, जहां वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में थी. भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ग़लती इस पूरे चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार बना देना था. उसे लगा कि अगर वह बिहार के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने रखेगी, तो बिहार की जनता आसानी से नीतीश कुमार को जिता देगी, लेकिन वह भूल गई कि बिहार की जनता देश के उन लोगों में से है, जहां सबसे ज़्यादा राजनीतिक संवाद होते हैं. देश के अधिकांश हिंदी–अंग्रेजी पत्र–पत्रिकाओं का 50 प्रतिशत बिहार में बिकता है और बिहार में हर गली, नुक्कड़, चौराहे और चाय की दुकानों पर राजनीति को लेकर बहस होती है. भाजपा ने यह मान लिया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर वह बिहार के लोगों के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

किसे कितनी सीटें मिलीं

पार्टी	सीट
भाजपा	53
कांग्रेस	27
जनता दल (यूनाइटेड)	71
राष्ट्रीय जनता दल	80
लोक जनशक्ति पार्टी	02
रालोसपा	02
भाकपा (माले-लिबरेशन)	03
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा	01
निर्दलीय	04
कुल	243

किसे कितने वोट मिले

पार्टी	वोट (प्रतिशत)
भाजपा	24.4
राजद	18.4
जद (यू)	16.8
निर्दलीय	9.4
कांग्रेस	6.77
लोजपा	4.87
हम	2.37
बसपा	2.17
भाकपा-माले (एल)	1.57
एआईएमआईएम	0.27
नोटा	2.57

“इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार में बदला, उसी दिन यह तय हो गया था कि बिहार चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो वह निरंकुश हो जाएगी और अगर नीतीश कुमार जीतते हैं, तो देश को एक राजनीतिक विकल्प मिल जाएगा. और, इस तथ्य ने बिहार की जनता को खड़ा कर दिया. तिस पर प्रधानमंत्री के बयान, जैसे कि नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाना. कुछ शब्दों का इस्तेमाल किसी भी राजनेता को बहुत सोच-समझ कर करना चाहिए, जैसे कि डीएनए. क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नीतीश की पैदाइश के बारे में आपको संदेह है कि उनके कौन पिता हैं, कौन माता हैं? यही भाव बिहार की जनता के बीच में गया और नीतीश ने उसे बिहारियों के आत्म-सम्मान के साथ जोड़ दिया.”

26 जगहों पर मोदी की रैली 11 जगहों पर मिली हार | P-4

भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी | P-5

सहयोगी दलों ने किया बेड़ा ग़र्क | P-7

दो महानायक

पृष्ठ 1 का शेष

वोट ले लेगी. और, इस चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले जब नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया, तो कुछ इस अंदाज़ में किया, जैसे वह बिहार के लोगों को दान दे रहे हों और उन्हें लगा कि बिहार के लोग इस एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये के झांसे में आ जाएंगे. अगले ही दिन जब नीतीश कुमार का बयान अख़बारों में आया कि यह एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये का वायदा कितना खोखला है और इसमें उन सारी योजनाओं को भी शामिल किया गया है, जो बिहार में पहले से चल रही हैं. तब भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगा कि इसका उसे नुक़सान होने वाला है. लेकिन, बिहार के लोगों की समझ में आ गया कि सच्चाई दोनों बयानों में किसके साथ है.

चुनाव शुरू हुए और बिहार के सारे लोग चुनाव संचालन से बाहर रहे. राजस्थान के एक व्यक्ति भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बना दिया गया, जिन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ अपनेपन की जगह बॉस की तरह व्यवहार करना शुरू किया. प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ लाने के लिए साधनों की बौछार कर दी गई. जब हमने कोशिश की, तो पता चला कि एक सभा आठ से दस करोड़ रुपये के बीच आंकी गई. कहां से आया यह पैसा? क्या यह पैसा व्हाइट मनी था? नहीं, यह पैसा व्हाइट मनी नहीं था, एकाउंटेड मनी नहीं था, बल्कि यह पैसा अन–एकाउंटेड मनी था. अब तो लोग बता रहे हैं कि आने वाले लोगों को बहुत अच्छा खाना भी दिया गया. इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री की आंखों में खुद उनकी पार्टी ने धूल झोंकी और उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये जितने लोग आपको सुनने आ रहे हैं, ये आपके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास से भरे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे. प्रधानमंत्री ने हर सभा में कुछ ऐसा व्यवहार किया, जैसे वह इस देश के छत्रपति हों और बाकी सारे लोग भुनगे और मच्छर हों. प्रधानमंत्री की सभा में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसने पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्षोभ पैदा किया. वे लोग प्रधानमंत्री द्वारा ज़्यादा सम्मान पाते देखे गए, जो उग्र भाषा, असंयमित भाषा और सत्य से परे बोलने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे. भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले वोटरों को भी इन सारे क्रियाकलापों की सच्चाई ने कहीं पसोपेश में डाल दिया. मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं थे, न उन्हें संबोधित किया गया, न उन्हें प्रधानमंत्री के मंच पर कहीं जगह मिली. और, जिस व्यक्ति को कहीं जगह मिली (शाहनवाज हुसैन को), वह भी अनाथ की तरह मंच पर खड़े दिखाई दिए.

इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार में बदला, उसी दिन यह तय हो गया था कि बिहार चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो वह निरंकुश हो जाएगी और अगर नीतीश कुमार जीतते हैं, तो देश को एक राजनीतिक विकल्प मिल जाएगा. और, इस तथ्य ने बिहार की जनता को खड़ा कर दिया. तिस पर प्रधानमंत्री के बयान, जैसे कि नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाना. कुछ शब्दों का इस्तेमाल किसी भी राजनेता को बहुत सोच–समझ कर करना चाहिए, जैसे कि डीएनए. क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नीतीश की पैदाइश के बारे में आपको संदेह है कि उनके कौन पिता हैं, कौन माता हैं? यही भाव बिहार की जनता के बीच में गया और नीतीश ने उसे बिहारियों के आत्म–सम्मान के साथ जोड़ दिया. इसकी लीपापोती के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सफाइयां आने लगीं कि नरेंद्र मोदी का मतलब नीतीश के पॉलिटिकल डीएनए से था. कई लोगों ने फिर डीएनए शब्द का इस्तेमाल शुरू किया. भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं द्वारा डीएनए शब्द का इस्तेमाल करने से बिहार की जनता को लगा कि यह तो अत्यंत असम्मानजनक भाषा है कि आप किसी की पैदाइश की सत्यता जानना चाहें. बिहार या देश में कहीं भी डीएनए की जांच कराने का मतलब पैदाइश की सत्यता की जांच से ही जोड़ा जाता है. प्रधानमंत्री का यह कहना भी लोगों को नागवार गुज़रा कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को सेट करना चाहते हैं. ऐसी भाषा तो गिरिराज सिंह भी नहीं बोल रहे थे. लेकिन, प्रधानमंत्री ने इस भाषा का इस्तेमाल करके अपने सभी नेताओं को कुछ भी बोलने, कुछ भी माहौल बनाने की खुली छूट दे दी. इस पर लालू यादव की बेटी मीसा ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी तो गली के गुंडे की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री किसी की बेटी के ऊपर भी हमला कर सकता है, तो शायद उनका मन फ़ैसला लेने लगा.

इस चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी ने अपने मुक़ाबले देश में नीतीश कुमार का चेहरा दे दिया, वहीं उन्होंने पहली बार राजनीतिक शालीनता की सीमा भी लांघ दी. नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान 26 सभाएं कीं, उसके पहले भी चार सभाएं कीं और उनमें बड़े–बड़े दावे, बड़े–बड़े वायदे किए तथा अपनी शारीरिक भाषा के ज़रिये जनता में यह संदेश भेजा कि उनमें सहिष्णुता की भी कमी है, उनमें कहीं पर समझ की भी कमी है और उन्हें लोगों की इज्जत करनी नहीं आती. अब तक बिहार या देश के लोगों ने किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा और शैली का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा. लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री के बजाय किसी तानाशाह की तरह बोलने वाले प्रधानमंत्री का दर्शन लोगों को कहीं न कहीं चौंका गया. बटोर कर लाई गई भीड़ ताली बजा रही थी और प्रधानमंत्री को लग रहा था कि उनके वोटर उन्हें क्लीन स्वीप दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां–जहां गए,

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
www.chauthiduniya.com
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
1986 से प्रकाशित
30 मार्च –05 अप्रैल 2015
बिहार विधानसभा चुनाव पर चौथी दुनिया का पहला सर्वे
नीतीश सबसे आगे
बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है. इस वजह से यहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं थी. लेकिन इस बार नीतीश का सीधा मुकाबला भाजपा से ही है. मतलब कल के दोस्त आज राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं और कल के दुश्मन आज के राजनीतिक हमसफर. सही कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई रिश्ता स्थाई नहीं होता. इसका जीता–जागता उदाहरण बिहार की मौजूदा परिस्थिति के रूप में सभी के सामने है, जहां लालू और नीतीश ने भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा ली है, लेकिन जनता–जनार्दन का फैसला सर्वोपरी होता है. ऐसे में चौथी दुनिया ने जनता के रुख को भांपने की कोशिश की, जहां नीतीश शुरुआती बढ़त लेते दिखाई दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी पहली पसंद कौन?
नीतीश कुमार 61 %
अराजकता और अनियमितता का अड्डा पेज–05
कहीं खुशी कहीं गम पेज–07
साई की महिमा पेज–12
रिकॉर्डों का विश्वकप पेज–15

ग़लती से सीख नहीं कार्रवाई की धमकी

बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही आरा से भाजपा सांसद आरके सिंह इस बात को उठाते रहे कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने कहा था कि पार्टी ने वर्तमान विधायकों एवं जिताऊ उम्मीदवारों के बजाय अपराधियों को टिकट बेचे. पैसे लेकर टिकट बांटने की बात भी उन्होंने कही, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया. दूसरी तरफ़ पटना साहिब से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने महंगाई की बात की. उन्होंने खुद को जानबूझ कर चुनाव प्रचार से दूर रखे जाने की भी बात कही, लेकिन उनकी बातों पर शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया. चुनाव परिणाम आने के बाद सिन्हा ने ट्वीट करके कहा कि बिहारी बनाम बाहरी का झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी को हार के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए. सिन्हा ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, वह सिद्धांतवादी एवं अच्छे व्यक्ति हैं. आरके सिंह ने भी कहा कि चुनाव नतीजों का विश्लेषण होना चाहिए और ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए. इसके बाद भाजपा महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए. राव ने कहा कि इन नेताओं ने पार्टी को क्या दिया, यह वे भी जानते हैं और हम भी. ज़ाहिर है, ये दोनों नेता अपनी साफ़गोई की वजह से पार्टी की आंख की किरकिरी बन गए हैं. श्री सिन्हा और श्री सिंह ने जो बातें कही थीं, यदि उन पर भाजपा समय रहते विचार करती, तो शायद कुछ फ़ायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके विपरीत भाजपा खुद को आईना दिखाने और सच बताने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का डंडा चलाने की धमकी दे रही है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 37
दिल्ली, 16 नवंबर–22 नवंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

दिल्ली किसकी, अदालत तय करेगी

दिल्ली में शासन चलाने का अधिकार किसे है, यह अब अदालत द्वारा तय होगा. आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद से ही उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर उलझ गई थी. उसने अब केंद्र के उस नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती दी है, जिसके तहत दिल्ली सरकार में नौकरशाहों की नियुक्ति का पूरा अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट इस तरह के सात मामलों की सुनवाई कर रहा है, जिनमें उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद है. अरविंद केजरीवाल की दलील यह है कि जैसे ही केंद्र एक नौकरशाह को कैडर आवंटित कर देता है, तो उसकी पोस्टिंग और ट्रांसफर का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास आ जाता है. अब केंद्र को इस मामले पर अपना जवाब देना है. इस बीच आप ने केंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी चुनौती दी है, जो जंग और केजरीवाल के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है. ■

आईएएस बनाम आईपीएस

सातवां वेतन आयोग, जो शीघ्र ही आने वाला है, ऐसा माना जा रहा है कि आईएएस अधिकारियों के वेतन एवं अन्य सेवाओं जैसे आईपीएस एवं आईआरएस के वेतन में समानता लाने की सिफारिश कर सकता है. क़रीब दो सौ आईएएस अधिकारियों, जिनका नेतृत्व केंद्रीय आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुखिया संजय भूसरेड्डी कर रहे हैं, ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को विरोध में पत्र लिखा है और सोशल मीडिया नेटवर्क कैंपेन के ज़रिये इस संभावित क़दम का विरोध करना शुरू कर दिया है. उनका मानना है कि वेतन समानता से बुद्धिशीलता को ख़तरा पहुंचेगा. उनका मानना है कि प्रतिद्वंद्वी सेवाओं वाले लोग इसे आसानी से नहीं ले रहे हैं. उन्हें डर है कि आईएएस बिरादरी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ऐसा नहीं होने देगी. हालांकि, यह सब वेतन आयोग की सिफारिशें आने के साथ स्पष्ट हो जाएगा. ■

एक अनार सौ बीमार

मोदी सरकार में अवकाश प्राप्त बाबुओं के लिए नौकरियों की कमी हो गई है. राजनेता अब गवर्नर बनाए जा रहे हैं. योजना आयोग का स्वरूप बदल गया है और कमेटियों की संख्या बहुत कम रह गई है. ऐसे में इन बाबुओं की आख़िरी उम्मीद सिर्फ़ नियामक संस्थाएं रह गई हैं. सूत्र बताते हैं कि यही वजह है कि नियामक संस्थाओं में निकलने वाली नौकरियों के लिए आवेदन की भरमार हो गई है और इस तरह की नियुक्तियों में देरी हो रही है. आरएस शर्मा को ट्राई का चेयरमैन नियुक्त करने में महीनों लग गए. शर्मा को 77 उम्मीदवारों के बीच से चुना गया. दिलचस्प रूप से उनके पूर्ववर्ती राहुल खुल्लर को 2012 में जब ट्राई का मुखिया नियुक्त किया गया था, उस समय केवल 10 उम्मीदवार ही दौड़ में थे. अभी अवकाश प्राप्त बाबू तीन प्रतिष्ठित पदों के लिए हाय–तौबा मचाए हुए हैं. कॉम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक चावला के जाने के बाद कथित तौर पर इस पद के लिए सौ आवेदन आए. इसी तरह सेबी के मुखिया पद के लिए 55 आवेदन आए. मुक़ाबला सख्त है. आशा की जानी चाहिए कि नियुक्ति में देरी नहीं होनी चाहिए. ■

TRAI
Telecom Regulatory Authority of India

dilipcherian@gmail.com

मतदान के पहले दौर के बाद हमने चौथी दुनिया में यह लिखा कि नीतीश को इस चुनाव में बढ़त है, क्योंकि हमें ज़मीन पर साफ़–साफ़ दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार और उनका गठबंधन आगे बढ़ रहा है. वहीं दूसरे पत्रकारों को, वे चाहे प्रिंट के हों या टेलीविजन के, भारतीय जनता पार्टी बढ़ती दिखाई दे रही थी. हमारे ऊपर आरोप लगने लगे कि हमें चुनाव की एक पैसे भर समझ नहीं है और हम यूं ही लिख रहे हैं. आज हम कह सकते हैं कि हम सही थे और बाकी सारे अख़बार–टेलीविजन चैनल ग़लत थे, जिन्होंने नीतीश कुमार की बढ़त को नहीं भांपा. एक्जिट पोल के बाद भी वे चैनल, जिन्होंने नीतीश कुमार की बढ़त को नहीं माना या नहीं जांचा, पत्रकारिता नहीं, बल्कि मन से कहीं न कहीं एक पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे थे.

दो महानायक

पृष्ठ 2 का शेष

उनमें से करीब आधे स्थानों पर उनके उम्मीदवार हार गए और यह चीज भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि क्यों वहां से उसका उम्मीदवार हारा, जहां पर उसकी अभूतपूर्व एक लाख से लेकर दस लाख लोगों तक की सभा हुई. यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बताई संख्या के आधार पर मैं कह रहा हूं. इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़बोलेपन ने बिहार में सांप्रदायिक माहौल बनाने में योगदान किया. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का लगातार पटना के एक फाइव स्टार होटल में रहना, वहीं आना, वहीं से जाना जनता को यह संदेश दे गया कि उनके मन में पार्टी के स्थानीय नेताओं के लिए भी कोई इज्जत नहीं है. और, फिर ख़बरें धीरे–धीरे कमरों से बाहर आने लगीं कि आज यह नेता डांटा गया, आज वह नेता डांटा गया. आज इससे सफाई मांगी गई और कल उससे सफाई मांगी गई. इन ख़बरों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मनोबल लगभग तोड़ दिया. अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता पूरे मन से चुनाव में नहीं लगे. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या प्रवक्ताओं का यह कहना उन कार्यकर्ताओं का अपमान है, जिन्होंने जी–जान लगाकर बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ मोड़ने की कोशिश की. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की हार इसलिए नहीं हुई कि कार्यकर्ता चुनाव में नहीं लगे. भारतीय जनता पार्टी की हार इसलिए हुई कि कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व अपने से बहुत दूर लगा. बिहार की जनता को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी न उन्हें विकास दे पाएगी, न रोज़गार दे पाएगी और न भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला पाएगी. वजह, जहां पर इतना काला धन खर्च हो रहा हो, वहां लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होता है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी ईमानदारी के साथ उनके विकास का काम करेगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है, पहले वह उन पैसों की भरपाई उन्हीं को लूटकर करता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोटो पूरे बिहार में चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र माने गए. दिल्ली में अधिकांश टेलीविजन चैनलों को प्रभावित किया गया. अधिकांश पत्रकारों से अपने पक्ष में लिखवाने की कोशिश की गई. मैं यह नहीं कहता कि इसमें पैसे का कोई रोल था, लेकिन इसमें संबंधों का रोल ज़रूर था. नहीं तो क्यों ऐसा होता कि इतना बड़ा जनादेश आने वाला हो, दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत से महा–गठबंधन जीतने वाला हो और किसी पत्रकार को इसकी हवा भी न लगे? सबसे महत्वपूर्ण काम चाणक्य ने किया, जिसने वोट पड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत दिला दिया. यह बताता है कि पूरा चुनाव कहीं न कहीं नकली अनुमानों और नकली परिणामों से भरा पड़ा है. चुनाव की घोषणा से पहले चौथी दुनिया ने एक सर्वे किया था, जिसे आज सारे राजनेताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए. मैं जानता हूं कि वे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वे अपनी असलियत शीशे में नहीं देखना चाहेंगे. हमारे उसी चुनाव सर्वेक्षण की नकल तीन दिनों के बाद होने वाले सभी सर्वेक्षणों ने की. लेकिन, उसके बाद जितने सर्वेक्षण आए, उन सबने अचानक अपने ही एक हफ्ते पहले किए गए सर्वे से उलट नतीजे दिखाने शुरू कर दिए. इसका साफ़ मतलब है कि उनके सर्वे के विज्ञान के ऊपर कुछ दूसरी चीजें भारी पड़ गईं. मतदान के पहले दौर के बाद हमने चौथी दुनिया में यह लिखा कि नीतीश को इस चुनाव में बढ़त है, क्योंकि हमें ज़मीन पर साफ़–साफ़ दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार और उनका गठबंधन आगे बढ़ रहा है. वहीं दूसरे पत्रकारों को, वे चाहे प्रिंट के हों या टेलीविजन के, भारतीय जनता पार्टी बढ़ती दिखाई दे रही थी. हमारे ऊपर आरोप लगने लगे कि हमें चुनाव की एक पैसे भर समझ नहीं है और हम यूं ही लिख रहे हैं. आज हम कह सकते हैं कि हम सही थे और बाकी सारे अख़बार–टेलीविजन चैनल ग़लत थे, जिन्होंने नीतीश कुमार की बढ़त को नहीं भांपा. एक्जिट पोल के बाद भी वे चैनल, जिन्होंने नीतीश कुमार की बढ़त को नहीं माना या नहीं जांचा, पत्रकारिता नहीं, बल्कि मन से कहीं न कहीं एक पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे थे. हम यह बहुत अदब के साथ कह रहे हैं कि बिहार चुनाव ने जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचार शैली, चुनाव संयोजन और उसकी खामियों को पूरी तरह उजागर किया, वहीं संपूर्ण मीडिया जगत को भी नंगा करके रख दिया.

इस चुनाव में मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान कि आरक्षण के ऊपर फिर से विचार होना चाहिए, ने बिहार में बड़े पैमाने पर उन वर्गों, जो कमज़ोर हैं और आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, को सोचने पर विवश कर दिया. इस बयान ने नरेंद्र मोदी के अति पिछड़ा होने की घोषणा से उनके पक्ष में जाने वाले अति पिछड़ों को महा–गठबंधन की तरफ़ भेज दिया. इतना ही नहीं, इसने दलितों को भी भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर महा–गठबंधन के पास भेज दिया, क्योंकि दलितों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उनका भी आरक्षण छीन लेगी. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह श्री मोहन भागवत का सोचा–समझा बयान था और इस बयान के बाद भी अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत जाता, तो अवश्य संपूर्ण आरक्षण के सिद्धांत पर विचार करने के लिए नई समिति बन जाती. नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले उनकी जान चली जाए, वह आरक्षण नहीं जाने देंगे, वह लड़ेंगे. जान जाने का सवाल ही नहीं था प्रधानमंत्री जी, आपको सिर्फ़ एक बात कहनी थी कि हम मोहन भागवत जी के बयान से सहमत नहीं हैं. वह वाक्य भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा. इसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया भ्रम पैदा किया कि लालू यादव और नीतीश कुमार की योजना है कि वे पिछड़ों एवं दलितों के आरक्षण का पांच प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों को दे दें. बल्कि उन्होंने कुछ यूं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण इन सारे तबकों से छीनकर दे दिया जाएगा. अगर लालू यादव और नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो इसने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मन में मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा संदेह है. वह मुसलमानों को इस देश का नागरिक ही नहीं मानती. अगर वह नागरिक मानती होती, तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का जिक्र ज़रूर करते. इस पूरे चुनाव के दौरान उनके भाषण में मुसलमानों का जिक्र सिर्फ़ एक बार तब आया, जब उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे दलितों–पिछड़ों के आरक्षण में कटौती करके उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं.

बिहार चुनाव संपूर्ण देश के लिए आंख खोलने वाला चुनाव है. बिहार चुनाव यह बताता है कि सिर्फ़ बड़ी–बड़ी बातें करने या नरेंद्र मोदी एवं अरुण जेटली वाला मॉडल बताने से विकास नहीं होता. हमारे देश में कितना पैसा एफडीआई में आया, कितना पैसा मेक इन इंडिया में आया, कौन–सी कंपनियां आईं, सफाई हुई या नहीं, जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने घोषित की थीं स्वच्छ भारत अभियान सहित, उनकी प्रगति क्या हुई आदि बातों ने बिहार के ग़रीबों को, मध्यम वर्ग को, यहां तक कि उच्च–मध्यम वर्ग को भी सशंकित कर दिया और उन्हें लगा कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बन गई, तो वह बड़े पुलों एवं बड़ी सड़कों की तो बात करेगी, लेकिन गांव, सड़क, किसानों की फसल, लड़कियों की शिक्षा की बात नहीं करेगी. बिहार में सड़कों का जाल नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, उसे सुशील मोदी के खाते में डालने की भाजपा की कोशिश बिहार की जनता ने नकार दी. लड़कियों को साइकिल देकर स्कूल भेजने की योजना लोगों को ज़्यादा समझ आई, न कि इसके मुक़ाबले हर छात्रा को स्कूटी और स्कूटी में पेट्रोल देने की बात. नीतीश कुमार ने बिहार को बिजली दी और वायदा किया कि हर गांव को आगे भी बिजली देंगे. लोगों ने उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, न कि प्रधानमंत्री के इस बयान पर कि बिहार के हर घर में अब तक रोशनी क्यों नहीं आई. लोगों ने नीतीश कुमार की इस बात पर ज़्यादा भरोसा किया कि हम बिहार का विकास गांवों को आधार बनाकर, ग़रीबों को आधार बनाकर करेंगे. लोगों ने सोचा कि उस विकास में वे कहां होंगे, जहां सिर्फ़ बिल्डर हैं, बड़े उद्योगपति हैं और पूंजीपति हैं. और, बिहार के लोगों ने एक सोचा–समझा निश्चित फ़ैसला ले लिया.

देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था सवालिया दायरे में आ गई है. न अमीर खुश हैं, न छात्र खुश हैं, न नौजवान खुश हैं और भाजपा द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट पर चलाया हुआ घृणा का अभियान लोगों को डरा गया. हम जब भी फेसबुक देखते हैं, ट्वीटर देखते हैं, तो उन पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में दूसरे लोगों को तबाह करने, काटने, मारने और गाली देने की एक बाढ़–सी आई हुई है, उसने भी बिहार के लोगों को डराया. सिर्फ़ बिहार के लोगों को नहीं डराया, उसने देश के लोगों को डराया. इसलिए देश के लोगों ने बिहार के इस फ़ैसले के ऊपर उम्मीद ज़ाहिर की है और यह राय देनी शुरू की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनका मंत्रिमंडल अब ज़िम्मेदारी से काम करेगा और प्रधानमंत्री शायद अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी काम करने की ज़िम्मेदारी सौंपेंगे, क्योंकि उनके उस मॉडल को बिहार के लोगों ने नकार दिया, जिसमें सचिव और प्रधानमंत्री के बीच में कोई नहीं. भाजपा इन कमियों पर ग़ौर नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है. भाजपा की सोच तब सामने आ गई, जब उसके प्रवक्ता ने कहा कि यह फ़ैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. जनता का फ़ैसला कभी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता. जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का फ़ैसला लिया था, तब वह भी सही फ़ैसला था और आज जब बिहार में उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फ़ैसला लिया और प्रधानमंत्री के सारे वायदों, सारे दावों की अनदेखी कर दी, तो यह भी एक सही फ़ैसला है. वरना ऐसा कैसे होता कि उन 14 या 16 जगहों से भाजपा के उम्मीदवार हार जाते, जहां–जहां प्रधानमंत्री ने सभाएं की थीं. अमित शाह का बिहार में ज़्यादा बने रहना इस चुनाव का दूसरा बड़ा नुक़सान था. अमित शाह की भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज छोटे नरेंद्र मोदी की भाषा और बॉडी लैंग्वेज है. दोनों ने मिलकर बिहार के लोगों को डरा दिया, जिससे उन्हें लगा कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, जो हमारी बात समझने की जगह हमें डांटे–डपटे, डंडा दिखाकर शांति सिखाए और कोई भी अब बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहता. देश में अब कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहता. न हिंदू चाहता है और न मुसलमान. मैं यहां श्री मोहन भागवत, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह के ध्यानार्थ एक बात लिख रहा हूं कि बिहार का फ़ैसला मुसलमानों का फ़ैसला नहीं है. बिहार का फ़ैसला बिहार के हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय का फ़ैसला है. भाजपा के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 20 प्रतिशत मुसलमान चूंकि एकतरफ़ा महा–गठबंधन की तरफ़ हो गए, इसलिए यह नतीजा आया. यह जनता द्वारा दिए गए फ़ैसले का सांप्रदायिक स्पष्टीकरण है, सांप्रदायिक विश्लेषण है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसा विश्लेषण भाजपा करेगी, तो उसे सारे देश में एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा. भाजपा को समझ लेना चाहिए कि कुछ नौजवानों द्वारा उसके पक्ष में उठाई जाने वाली आवाज़ देश के सभी नौजवानों या महिलाओं की आवाज़ नहीं है. महिलाओं ने नीतीश कुमार द्वारा दिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में वोट दिया, न कि नरेंद्र मोदी के भावनात्मक एवं अतार्किक विकास को. यह जीत बिहार की जनता की स्पष्ट जीत है और उसने नीतीश कुमार और लालू यादव के नेतृत्व में बने महा–गठबंधन को दो तिहाई बहुमत देकर एक नई राजनीतिक तस्वीर बना दी है. ■

editor@chauthiduniya.com

पाकिस्तान, पटाखे, छोटा राजन जैसे चुनावी हथकंडे फेल

ग़लती से अगर बिहार में, ग़लती से भी भाजपा चुनाव हार गई, तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के चुनाव प्रचार में जब उक्त शब्द बोले थे, तब भले ही उनकी निगाहें पाकिस्तान पर रही होंगी, लेकिन निशाना बिहार के मतदाता थे. यानी पाकिस्तान का भय दिखाकर पूरी तरह से धार्मिक गोलबंदी करने का प्रयास, जो सफल नहीं हुआ. इसी तरह बीच चुनाव में छोटा राजन को बाली से भारत लाकर मतदाताओं को अपने सख्त शासन–प्रशासन के संकेत देने के प्रयास हुए. ऐसी भूमिका बांधी गई, मानो छोटा राजन के पकड़े जाते ही दाऊद इब्राहिम को पकड़ लिया जाएगा. इस सबका मकसद भी कहीं न कहीं मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को लुभाना था, लेकिन यह प्रयास भी भाजपा को बिहार चुनाव में करारी शिकस्त से बचा नहीं सका. ■

बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए पांच चरणों में हुए मतदान में कुल 3450 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें से 1038 यानी 30 फीसद उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं. साल 2010 में हुए विधानसभा चुनावों में 3058 उम्मीदवार मैदान में थे. जिनमें से 986 दागी थे. इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बार प्रत्येक दल ने दागी उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा ने 39 फीसद, जदयू ने 41 फीसद, आरजेडी ने 29 फीसद और कांग्रेस ने 41 फीसद दागी उम्मीदवारों को अपने टिकट दिए.

बिहार विधानसभा चुनाव

26 जगहों पर मोदी की रैली

11 जगहों पर मिली हार

मनोज कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में 26 चुनावी सभाएं की थीं. इससे पहले 4 परिवर्तन रैलियां भी हुईं. कुल मिलाकर राजनीतिक सभाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री ने बिहार में 30 रैलियां की थीं, लेकिन इन रैलियों में जुटी भीड़ वोट में नहीं बदल सकी. चुनाव की तारीखों के एलान के बाद पीएम ने जिन 26 जगहों में प्रचार किया था, उनमें से 11 सीटें बीजेपी हार गई है.

पहले दौर में पीएम के प्रचार का हाल

पहले दौर के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को बांका से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी. बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं. एक बांका सीट को छोड़कर बाकी 4 सीटें महागठबंधन के खाते में गई हैं. 8 अक्टूबर को मुंगेर की सभा में प्रधानमंत्री ने शैतान वाले बयान को लेकर लालू पर हमला बोला था. मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं. इन तीनों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. मुंगेर सीट राजद के और जिले की दो अन्य सीटें (तारापुर और जमालपुर) जेडीयू के खाते में गई हैं. 8 तारीख को ही पीएम ने बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में भी सभाएं की थीं. बेगूसराय में एनडीए का खाता भी नहीं खुल सका. यहां की सातों सीटें महागठबंधन के खाते में गई हैं. इसके अलावा समस्तीपुर में भी भाजपा का यही हाल रहा, यहां की भी सभी 10 सीटें महागठबंधन के खाते में गई हैं. भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है. नवादा की रैली में प्रधानमंत्री ने दादरी कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. नवादा की पांच विधानसभा सीटों में से केवल दो पर भाजपा जीत दर्ज कर सकी, बाकी तीन सीटें महागठबंधन के खाते में गईं. कुल मिलाकर यदि पहले दौर की बात करें तो बेगूसराय और समस्तीपुर जैसे बड़े जिलों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया. पहले दौर में प्रधानमंत्री ने 5 सभाएं की थीं जिनमे से 2 जगह पार्टी जीती और 3 जगह हार गई.

रोहतास (सासाराम) जिले की बात करें तो यहां की एक सीट एनडीए गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) जीतने में सफल हुई, जबकि इस जिले के दिग्गज भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया हार गए. जिले की 7 में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में गईं. इसके बाद पीएम ने कैमूर और जहानाबाद में रैली की थी. कैमूर जिले की 4 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गईं.

दूसरे दौर में पीएम के प्रचार का हाल

दूसरे दौर के चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम ने 9 अक्टूबर को औरंगाबाद से की थी. उस दिन पीएम औरंगाबाद और सासाराम गए थे. औरंगाबाद सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. औरंगाबाद सीट से भाजपा के रामाधार सिंह विधायक हुआ करते थे. इस बार नीतीश और लालू की लहर का कहर उनपर भी टूटा. रोहतास (सासाराम) जिले की बात करें तो यहां की एक सीट एनडीए गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) जीतने में सफल हुई, जबकि इस जिले के दिग्गज भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया हार गए. जिले की 7 में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में गईं. इसके बाद पीएम ने कैमूर और जहानाबाद में रैली की थी. कैमूर जिले की 4 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, लेकिन जहानाबाद की सभी तीन सीटें महागठबंधन के खाते में चली गईं. यहां की मखदूमपुर सीट पर जीतन राम मांझी को हार का सामना करना पड़ा. दूसरे दौर में पीएम ने 4 सभाएं कीं, इस दौर में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा.

तीसरे दौर में पीएम के प्रचार का हाल

28 अक्टूबर को तीसरे दौर की वोटिंग हुई थी. 25 तारीख को पीएम ने 4 सभाएं की थीं. इस दिन उनकी पहली सभा छपरा के मढौरा में आयोजित हुई थी. मढौरा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा जबकि हाजीपुर शहर की सीट बीजेपी जीतने में सफल रही. पीएम ने यहां सभा की थी. इसके अलावा पटना में पीएम ने रैली की थी, वहां पार्टी को जीत मिली. नालंदा के बिहारशरीफ में भी पीएम ने सभा की थी. यहां की 7 सीटों में से 6 भाजपा हार गई. 26 अक्टूबर को पीएम ने बक्सर में सभा की थी. बक्सर में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली.

चौथे दौर में पीएम के प्रचार का हाल

चौथे दौर के चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम ने सीवान से की थी. सीवान शहर की सीट को छोड़कर भाजपा जिले की अन्य सीटें हार गई. सीवान जिले में कुल 8 सीटें हैं. 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी में रैलियों को संबोधित किया था. बेतिया शहर सीट पर पिछले 15 सालों से भाजपा का क़ब्जा था. लेकिन उसे यहां भी मुंह की खानी पड़ी. सीतामढ़ी सीट पर साल 2003 से भाजपा का क़ब्जा था. लेकिन इस बार यहां से भाजपा उमीदवार सुनील पिंटू को हार का सामना करना पड़ा. मोतिहारी से भाजपा के प्रमोद कुमार जीत गए. 30 अक्टूबर को गोपालगंज और मुज़फ्फरपुर में पीएम की रैली थी. इन दोनों सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई. लेकिन इन जिलों में भाजपा के सहयोगी दलों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. कुल मिलाकर चौथे दौर में 6 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुईं. यहां की चार सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई.

पांचवें दौर में पीएम के प्रचार का हाल

पांचवें दौर के चुनाव के लिए पीएम ने 1 और 2 नवंबर को तीन–तीन सभाएं की थीं. 1 नवंबर को मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार में उनकी सभायें हुईं, मधेपुरा सीट भाजपा हार गई. 2 नवंबर को दरभंगा, पूर्णिया और फारबिसगंज में पीएम ने 3 सभाएं की थीं. इन तीनों शहरों में बीजेपी ने जीत हासिल की लेकिन इन जिलों की अन्य सीटों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा. ■

(लेखक एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधानसभा में बाहुबलियों की बहार

राज्य की कई सीटों पर भले ही बाहुबली स्वयं चुनाव मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी या अन्य रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा था. दरौंधा सीट से बाहुबली अजय सिंह की पत्नी और निवर्तमान विधायक कविता सिंह चुनाव मैदान में थीं. उन्होंने भाजपा के जितेंद्र स्वामी को 13,222 मतों के अंतर से मात दी. जदयू ने रणवीर यादव की पत्नी पूनम देवी को खगड़िया सीट से उम्मीदवार बनाया था. रणवीर यादव और उनकी पत्नी दोनों ही विधायक रह चुके हैं. रणबीर यादव के खिलाफ हत्या के कई केस दर्ज हैं. उन्होंने हम उम्मीदवार राजेश कुमार को 25,565 मतों के अंतर से हराया.

नवीन चौहान

बिहार में राजनीति और अपराध का बहुत पुराना नाता रहा है. पहले यहां राजनेता बाहुबलियों के बल पर राजनीति करते थे, लेकिन समय के साथ बाहुबली भी राजनीति में आ गए. आज भी यहां बाहुबलियों को जीत की गारंटी समझा जाता है, इसलिए इस बार भी सभी दलों ने अपनी–अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बाहुबलियों को टिकट देने में किसी तरह का गुरेज नहीं किया. एनडीए हो या महागठबंधन या अन्य दल, सभी ने दिल खोलकर बाहुबलियों को टिकट दिए. सभी ने बाहुबलियों पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था. जहां बाहुबली स्वयं चुनावी मैदान में नहीं उतर सके, वहां उनकी पत्नी या करीबी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाकर चुनावी समर में उतारा गया.

इस बार बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए पांच चरणों में हुए मतदान में कुल 3450 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें से 1038 यानी 30 फीसद उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं. साल 2010 में हुए विधानसभा चुनावों में 3058 उम्मीदवार मैदान में थे. जिनमें से 986 दागी थे. इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बार प्रत्येक दल ने दागी उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा ने 39 फीसद, जदयू ने 41 फीसद, आरजेडी ने 29 फीसद और कांग्रेस ने 41 फीसद दागी उम्मीदवारों को अपना टिकट दिए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने वाले 18 फीसद उम्मीदवार दागी थे.

पांच चरण में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में सबसे ज्यादा बाहुबली चुनावी मैदान में थे. इनमें मनोरजंन सिंह, अनंत सिंह, कन्हैया सिंह, ददन यादव और विश्वेश्वर ओझा प्रमुख हैं. अन्य बाहुबलियों में काली प्रसाद पांडे, चितरंजन सिंह, राजू तिवारी, केदारनाथ

सिंह आदि शामिल हैं. अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले दंबग–बाहुबली नेता अनंत सिंह को इस बार जदयू ने टिकट नहीं दिया, इसलिए अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया. साल 2005 में पहली बार मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह को इस इलाके में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है. निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के नीरज कुमार को 18,848 वोटों के अंतर से हराया है. बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई और लोजपा उम्मीदवार कन्हैया सिंह इसी सीट पर चौथे स्थान पर रहे.

एकमा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे एक समय के मोस्ट वांटेड मनोरंजन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कामेश्वर प्रसाद सिंह को 8,126 वोटों से हराया. उनके खिलाफ 9 आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं. वहीं डुमराव सीट से जदयू उम्मीदवार के रूप में उतरे ददन यादव ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राम बिहारी सिंह को 30,339 वोटों से हराया. उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं. बक्सर के ददन, राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. अंडरवर्ल्ड सरगना और पूर्व विधायक राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी ने लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गोविंदगंज सीट से जीत हासिल की है. उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार को 27,920 मतों के अंतर से हराया. जदयू के टिकट से मटिहानी विधानसभा सीट से उम्मीदवार नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश कुमार को 22688 मतों के अंतर से हराया. नरेंद्र के खिलाफ हत्या सहित 15 अन्य गंभीर मामलों में अपराध पंजिबद्ध हैं.

राज्य की कई सीटों पर भले ही बाहुबली स्वयं चुनाव मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी या अन्य रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा था. दरौंधा सीट से बाहुबली अजय सिंह की पत्नी और निवर्तमान विधायक कविता सिंह चुनाव मैदान में थीं. उन्होंने भाजपा के जितेंद्र स्वामी को 13,222 मतों के अंतर से मात दी. जदयू ने रणवीर यादव की पत्नी पूनम देवी को खगड़िया सीट से उम्मीदवार बनाया था. रणवीर यादव और उनकी पत्नी दोनों ही विधायक रह चुके हैं. रणबीर यादव के खिलाफ हत्या के कई केस दर्ज हैं. उन्होंने हम उम्मीदवार राजेश कुमार को 25,565 मतों के अंतर से हराया. भाजपा ने नवादा के कुख्यात अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को वारिसालीगंज से अपना उम्मीदवार बनाया था. अरुणा ने 2010 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस बार भाजपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जदयू उम्मीदवार प्रदीप कुमार को 19,527 मतों के अंतर से हराया. फैजान गिरोह के सरगना रह चुके अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती रूपौली सीट से चुनावी मैदान में थीं. बीमा पहले भी विधायक और मंत्री रह चुकी हैं. अवधेश मंडल का यहां अब भी दबदबा है. यह बात उनकी पत्नी की जीत से एक बार फिर साबित हो गई है. बीमा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश मंडल को 9,672 मतों से हराया. ■

किस चरण में कितने दागी उम्मीदवार खड़े हुए

	कुल उम्मीदवार	अपराधी	भाजपा	जदयू	आरजेडी
प्रथम चरण	583	174	10	09	06
द्वितीय चरण	456	142	11	09	09
तृतीय चरण	808	215	21	10	17
चतुर्थ चरण	776	253	20	12	10
पांचवां चरण	827	254	15	07	06
कुल	3450	1038	77	47	48

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय जनता पार्टी की हार के कारणों में उसकी आंतरिक समस्याओं का भी योगदान रहा. इस चुनाव में बिहार के स्थानीय नेताओं की स्थिति निर्णायक के बजाय कार्यवाहक की हो गई. चुनाव का पूरा नियंत्रण अमित शाह के पास था. अमित शाह फ़ैसला लेते थे और उसे लागू कराने की ज़िम्मेदारी भी दिल्ली से तैनात किए गए ग़ैर–बिहारी नेताओं की थी. स्थानीय नेताओं का रोल सिर्फ़ आदेश पालक का था. इस पहलू को नीतीश कुमार एवं लालू यादव ने बड़ी कुशलता से बाहरी और बिहारी का मुद्दा बना दिया. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ गई.

भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी

बिहार में नीतीश कुमार की भारी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे शर्मनाक हार है. शर्मनाक इसलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया था. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को राजनीतिक सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरी थी. यही वजह है कि पार्टी ने बिहार में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया. पहली बार कोई प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की तरह विधानसभा चुनाव में कैंपेन करता नज़र आया. कहते हैं कि जो लोग जोश में होश गंवाते हैं, वे कभी विजयी नहीं होते. भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने अहंकार में चूर होकर होश गंवा बैठी. बिहार की राजनीति एक जटिल पहेली है, जिसे समझना आसान नहीं है. दिल्ली की हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी को खुद को दोष देना होगा. उसने वो सारी ग़लतियां कीं, जो किसी जीती हुई पार्टी को हार की ओर ले जाती है.

मनीष कुमार

जीत की खूबी यह है कि उसके कई प्रणेता एवं रचयिता होते हैं और हार का दुर्भाग्य यह है कि वह लावारिस होता है. बिहार की जनता ने अपने फ़ैसले से यह तय कर दिया कि उसका नायक कौन है और बिहार की राजनीति में कौन यतीम हो गया. बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा. देश के राजनेता, राजनीतिक दल एवं बिहार के लोग इस चुनाव के महत्व से भलीभांति वाकिफ थे. सबको यह भी पता था कि इस चुनाव से भारत की भविष्य की राजनीति तय होगी. बिहार की जनता का फ़ैसला आ चुका है. उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और अपने चहेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से सिंहासन पर बैठाने का फ़ैसला किया. बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करने के बजाय नीतीश कुमार के कामकाज पर मुहर लगाई. अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या चूक हुई, जिसकी वजह से लोगों ने उसे नकार दिया. बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही लोग नीतीश कुमार को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मान रहे थे. लोग उनके कामकाज से खुश थे, साथ ही लालू यादव के साथ आने से यादवों एवं मुसलमानों का वोट भी लालू–नीतीश गठबंधन के साथ एकजुट होना तय था. क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं था कि चुनावी समीकरण लालू–नीतीश के पक्ष में है? आख़िर भारतीय जनता पार्टी से क्या चूक हुई, इसे समझना ज़रूरी है.

बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार, दिशाहीनता, सांप्रदायिकता, आर्थिक नीति और चुनाव प्रचार की वजह से डूब गई. लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई. लालू यादव एवं नीतीश कुमार ने उस हार से सबक लिया. उन्हें समझ में आ गया कि अलग–अलग रहकर भाजपा को नहीं हराया जा सकता है. इसलिए कई सारी बाधाएं दरकिनार कर वे एकजुट हुए. भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के वोट बैंक का तोड़ नहीं निकाल सकी. यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार से लालू–नीतीश के महा–गठबंधन का वोट बैंक न सिर्फ़ मजबूत किया, बल्कि उसमें इजाफा भी किया. भारतीय जनता पार्टी न तो यादवों के वोटों में सेंध मार सकी और न कुर्मी–कुशवाहा वोटों को पाने में सफल रही. इसके अलावा उसने अपने बयानों से मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह से महा–गठबंधन के पक्ष में कर दिया. भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की सबसे बड़ी भूल यह रही कि वे बिहार की जटिल राजनीति समझ नहीं सके. उन्हें लगा कि सिर्फ़ पैकेज देकर, वायदे और विकास की बातें करके वे बिहार में चुनाव जीत जाएंगे. लेकिन, हक़ीक़त यह है कि बिहार के लोग जब वोट देते हैं, तो उनके दिमाग़ में कई तरह की बातें होती हैं. सामाजिक न्याय बिहार की राजनीति की सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के पास सामाजिक न्याय के नाम पर जनता को देने के लिए कुछ नहीं था. यही वजह है कि लोगों ने विकास के महज वायदे को खारिज करते हुए सामाजिक न्याय की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया.

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के विभिन्न कारणों में मोदी सरकार की आर्थिक नीति भी शामिल है. लोग केंद्र सरकार की आर्थिक नीति से निराश हैं. इसकी वजह यह है कि किसी भी नीति का फ़ायदा ग़रीबों तक नहीं पहुंच रहा है. लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार सिर्फ़ अमीरों के लिए नीतियां बना रही है, चंद औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है और महंगाई रोकने में नाकाम रही है. चुनाव के दौरान अरहर की दाल की क़ीमत 200 रुपये प्रति किलो पार कर गई. यह इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा था. भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यह बात समझ में नहीं आई कि बिहार में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने बाहर इसलिए निकल रही हैं, क्योंकि वे महंगाई से परेशान हैं. यही नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं, लड़कियों एवं छात्राओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसका फ़ायदा महा–गठबंधन को उनके समर्थन के रूप में मिला. केंद्र सरकार की आर्थिक नीति और महंगाई का जनता पर क्या असर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका सही आकलन नहीं कर सकी.

लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को काफी उम्मीदें एवं आशाएं थीं, लेकिन पिछले डेढ़ सालों में नरेंद्र मोदी पर से लोगों का भरोसा डिगा है. देश की जनता सरकार की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ज़मीन पर कोई बदलाव होता नहीं दिखा. बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उसे दिशाहीन ही कहा जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से ऐसे कई मुद्दों को हवा दी गई, जिनसे सिर्फ़ नुक़सान हुआ. सबसे बड़ा नुक़सान आरक्षण के मुद्दे पर हुआ. मोहन भागवत का आरक्षण की समीक्षा वाला बयान आत्मघाती साबित हुआ. इस चुनाव में जीत–हार की चाबी अति पिछड़ा वर्ग के पास थी. मोहन भागवत के बयान से अति पिछड़ा वर्ग महा–गठबंधन के पक्ष में चला गया. इसके अलावा दादरी एवं हरियाणा की घटनाओं और लेखकों, कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं के विरोध के चलते भी भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ माहौल बना. ऐसी बातें हर चुनाव के दौरान होती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन मुद्दों को निपटाने के बजाय इन्हें और उलझा दिया. इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान प्रतिक्रियावादी थे, जिन्हें बिहार की जनता ने खारिज कर दिया. भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देकर, भावनाएं भड़का कर और हर मुद्दे पर पाकिस्तान का हवाला देकर आम जनता का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता है. ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक तो खुश हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बयानों से निष्पक्ष एवं संवेदनशील मतदाता दूर हो जाते हैं. भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में इसलिए हारी, क्योंकि वह निष्पक्ष एवं संवेदनशील मतदाताओं का समर्थन हासिल नहीं कर सकी.

भारतीय जनता पार्टी की हार के कारणों में उसकी आंतरिक समस्याओं का भी योगदान रहा. इस चुनाव में बिहार के स्थानीय नेताओं की स्थिति निर्णायक के बजाय कार्यवाहक की हो गई. चुनाव का पूरा नियंत्रण अमित शाह के पास था. अमित शाह फ़ैसला लेते थे और उसे लागू कराने की ज़िम्मेदारी भी दिल्ली से तैनात किए गए ग़ैर–बिहारी नेताओं की थी. स्थानीय नेताओं का रोल सिर्फ़ आदेश पालक का था. इस पहलू को नीतीश कुमार एवं लालू यादव ने बड़ी कुशलता से बाहरी और बिहारी का मुद्दा बना दिया. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ गई. चुनाव के दौरान अरुण शौरी एवं शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों को लालू–नीतीश गठबंधन मुद्दा बनाने में सफल रहा. भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतर्कलह के चलते मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर सकी. पार्टी में ऐसे कई नेता थे, जो मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे. ऐसी स्थिति में किसी का नाम घोषित करने का मतलब चुनाव से पहले ही आंतरिक लड़ाई को सार्वजनिक करना होता. लेकिन, नाम घोषित न करने से कहीं ज़्यादा नुक़सान हुआ. एक तरफ़ नीतीश कुमार थे, वहीं दूसरी तरफ़ कोई नेता नहीं था. जिस दिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, उसी दिन यह तय हो गया था कि बिहार में अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच होगा. भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के मुक़ाबले एक नेता विकसित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. चुनाव के समय जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का मुद्दा उठा, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तरविहीन हो गई. इसी समस्या से भारतीय जनता पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में भी जूझना पड़ेगा.

बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार, दिशाहीनता, सांप्रदायिकता, आर्थिक नीति और चुनाव प्रचार की वजह से डूब गई. लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई. लालू यादव एवं नीतीश कुमार ने उस हार से सबक लिया. उन्हें समझ में आ गया कि अलग-अलग रहकर भाजपा को नहीं हराया जा सकता है. इसलिए कई सारी बाधाएं दरकिनार कर वे एकजुट हुए. भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के वोट बैंक का तोड़ नहीं निकाल सकी.

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से जिन मुद्दों को प्रमुखता दी गई, उन्हें जनता ने नकार दिया. भारतीय जनता पार्टी ने जंगलराज को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था. मजेदार बात यह है कि बिहार के लिए जंगलराज वाकई में बड़ा मुद्दा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह भूल गई कि जिस जंगलराज से बिहार की जनता परेशान थी, उस पर नीतीश कुमार ने ही नियंत्रण किया था. बिहार की जनता ने यह महसूस किया कि नीतीश कुमार के शासन में जंगलराज का पूरी तरह से ख़ात्मा हुआ था. भारतीय जनता पार्टी लालू यादव का डर दिखाकर वोट पाना चाहती थी, लेकिन उसकी यह रणनीति इसलिए असफल हो गई, क्योंकि लोगों को नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ज़्यादा भरोसा था. भारतीय जनता पार्टी गोमांस का मुद्दा उछाल कर फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन उसका यह दांव भी उल्टा पड़ गया. भारतीय जनता पार्टी ने राम विलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टियों को 80 सीटें देकर भी ग़लती की. भारतीय जनता पार्टी की यह सोच थी कि इससे उसके गठबंधन का जातीय समीकरण मजबूत हो जाएगा. नतीजों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन पार्टियों के बीच वोटों का आदान–प्रदान नहीं हुआ. भाजपा गठबंधन इन 80 सीटों में से सिर्फ़ छह–सात सीटें जीत सका. इतना ही नहीं, सहयोगी पार्टियों के अंदर भी बगावत हुई और उनके नेताओं ने स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर भाजपा को नुक़सान पहुंचाया.

जिस तरह क्रिकेट में आख़िरी गेंद तक जीत और हार का फ़ैसला नहीं होता, वही हाल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का रहा. बिहार विधानसभा चुनाव की अनिश्चितता का आलम यह था कि किसी चुनावी सर्वे, एक्जिट पोल, राजनीतिक विशेषज्ञ और पत्रकार ने ऐसे नतीजे की कल्पना नहीं की थी. भारतीय जनता पार्टी ने डेढ़ साल पहले लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें और सबसे ज़्यादा वोट पाकर सबको चौंका दिया था, लेकिन इस चुनाव में वह पूरी तरह से धराशायी हो गई. भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल अपने कैंपेन में किया, उससे यह चुनाव केंद्र सरकार के डेढ़ साल के कामकाज पर जनमत संग्रह बन गया. बिहार की जनता का फ़ैसला मोदी सरकार के डेढ़ साल के कामकाज पर दिया गया फ़ैसला है. प्रजातंत्र में हर चुनाव राजनीतिक दलों और जनता को सबक देता है. बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सबक लेकर आया है. आशा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव नतीजों और अपनी ग़लतियों का सही ढंग से विश्लेषण करेगी तथा उससे सबक लेगी. ■

manishbph244@gmail.com

1952 से लेकर अब तक केवल 242 महिलाएं राज्य विधानसभा में पहुंच सकीं. हर राजनीतिक दल ने महिला मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं की मदद ली, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, लेकिन टिकट देने में सबने उनकी अनदेखी की. सबसे अधिक 34 महिलाएं वर्ष 1957 में राज्य विधानसभा पहुंची थीं. उस इतिहास को दोहराने में 53 वर्ष का समय लगा. दोबारा इतनी संख्या में महिलाओं का विधानसभा पहुंच पाना पिछले चुनाव यानी 2010 में संभव हो सका. हालांकि, महिला विधायकों की यह संख्या भी 2010 के विधानभा की कुल सदस्य संख्या का महज 14 फ़ीसदी है. वर्ष 2005 के चुनाव में 234 महिलाएं मैदान में थीं, लेकिन विधानसभा पहुंचने में केवल तीन को सफलता मिली. राज्य में महिला विधायकों की यह सबसे कम संख्या थी.

महिलाएं वोट देने में आगे, हिस्सेदारी में पीछे

महागठबंधन की महिला उम्मीदवारों की बात करें, तो उसने 25 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिनमें से 21 ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है. 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन मिला था और इस बार भी नीतीश की सत्ता में वापसी महिला मतदाताओं के अपार समर्थन के बिना संभव नहीं थी. पर सवाल एक बार फिर से वही उठता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी सभी राजनीतिक दलों के उन खोखले वादों की पोल खोलती है, जिनमें वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं.

आदित्य नारायण पांडेय

बिहार की महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के मामले में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. अगर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 2010 की तुलना में इस बार की मतदाता सूची में 50 लाख महिलाएं और शामिल हुई हैं और इस बार वोटिंग में भी बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है, पर इन सबके बावजूद बिहार विधानसभा में पिछली बार के मुकाबले इस बार महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में सभी राजनीतिक दलों ने कंजूसी दिखाई. जहां पिछले विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 14 प्रतिशत थी, वहीं इस बार घटकर 10 प्रतिशत रह गई है. वर्तमान विधानसभा में 14 फ़ीसदी महिला विधायक हैं. वहीं इस बार प्रमुख दलों ने सिर्फ 10 फ़ीसदी महिलाओं को टिकट दिया है. अगर बिहार में राजनीतिक दलों के हिसाब से महिला उम्मीदवारों को देखें, तो एनडीए ने 23 और महागठबंधन के कोटे से 25 महिलाओं को टिकट मिला है. एनडीए में भाजपा ने 160 में 14, हम ने 20 में से 4, लोजपा ने 32 में से 4 और रालोसपा ने अपने कोटे की 23 सीटों में से एक महिला को टिकट दिया है. वहीं महागठबंधन के कोटे में जदयू ने 101 में 10, राजद 101 में 10 और कांग्रेस ने 41 में पांच महिलाओं को टिकट दिया है. अभी तक सबसे अधिक हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) ने 20 प्रतिशत और रालोसपा ने सबसे कम लगभग 4 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है. अगर 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, तो एनडीए की 23 महिला उम्मीदवारों में से मात्र चार को ही जीत हासिल हुई है, जिसमें बीजेपी की भगीरथी देवी, आशा देवी, गायत्री देवी और भाजपा की ही उम्मीदवार अरुणा देवी ने जीत दर्ज की है. महागठबंधन की महिला उम्मीदवारों की बात करें, तो उसने 25 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिनमें से 21 ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है. 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन मिला था और इस बार भी नीतीश की सत्ता में वापसी महिला मतदाताओं के अपार समर्थन के बिना संभव नहीं थी. पर सवाल एक बार फिर से वही उठता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी सभी राजनीतिक दलों के उन खोखले वादों की पोल खोलती है, जिनमें वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं. अगर बिहार में महिलाओं की स्थिति और नीति नियामक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व की बात करें, तो अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1952 से लेकर अब तक केवल 242 महिलाएं राज्य विधानसभा पहुंच सकीं. हर राजनीतिक दल ने महिला मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं की मदद ली, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, लेकिन टिकट देने में सबने उनकी अनदेखी की. सबसे अधिक 34 महिलाएं वर्ष 1957 में राज्य विधानसभा पहुंची थीं. उस इतिहास को दोहराने में 53 वर्ष का समय लगा. दोबारा इतनी संख्या में महिलाओं का विधानसभा पहुंच पाना पिछले चुनाव यानी 2010 में संभव हो सका. हालांकि, महिला विधायकों की यह संख्या भी 2010 के विधानभा की कुल सदस्य संख्या का महज 14 फ़ीसदी है. वर्ष 2005 के चुनाव में 234 महिलाएं मैदान में थीं, लेकिन विधानसभा पहुंचने में केवल तीन को सफलता मिली. राज्य में महिला विधायकों की यह सबसे कम संख्या थी.

बिहार में महिलाओं को मताधिकार देने में भी बिहार पीछे था. बिहार विधान परिषद ने क़रीब आठ वर्षों के संघर्ष के बाद 1929 में यह अधिकार प्रदान किया, जबकि मुंबई एवं संयुक्त प्रांत में 1923, असम में 1924 और पश्चिम बंगाल में 1925 में ही महिलाओं को यह अधिकार मिल चुका था. हां, यह ज़रूर है कि बिहार में राबड़ी देवी के रूप में किसी महिला को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन वह भी किन परिस्थितियों में संभव हुआ, यह सभी जानते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

वामपंथ किस राह जा रहा है

पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए, तो यह साफ़ हो जाएगा कि राज्य में वामपंथ का बड़ा आधार था, लेकिन चुनाव में किसी भी वामपंथी दल को कोई सीट नहीं मिली थी. यहां तक कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए चल रही सहानुभूति लहर में भी वामपंथी पार्टियों को 13 सीटें मिली थीं. लेकिन साल 2000 तक बिहार में वामपंथी पार्टियों की हालत खराब होती चली गई. वैसे तो पूरे देश में वाम दलों के आधार में कमी आती नजर आ रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

वामपंथ की धारा तभी सूखने लगी थी, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों उसे करारी शिकस्त मिली थी. फिर भी, एक विचारधारा के तौर पर क्या वामपंथ का अस्तित्व अभी भी बचा हुआ है या खत्म होने की कगार पर है? यह सवाल बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर और भी प्रासंगिक हो जाता है. बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार छह वामपंथी दलों भाकपा, माकपा, भाकपा (माले), फारवर्ड ब्लॉक, आरएसपी एवं एसयूसीआई (सी) ने मिलकर चुनाव लड़ा. लेकिन यह एकता वामपंथी दलों को वो सफलता नहीं दिला पाई, जिसकी उन्हें तलाश थी. हालांकि, इस चुनाव में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन को तीन सीटों पर जरूर सफलता मिली है, लेकिन बाकी के वामपंथी दलों का खाता भी नहीं खुला. 2010 के बिहार विधान सभा चुनाव में केवल भाकपा एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी. अन्य वामदलों का खाता भी नहीं खुल पाया था. 2015 के चुनाव में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन को दरौली, तरारी और बलरामपुर सीट पर जीत हासिल हुई है. गौरतलब है कि 2005 के चुनाव में जहां इसे सात सीटें मिली थीं, वहीं 2010 में ये अपना खाता भी नहीं खोल पाई. 2015 में भाकपा (माले) लिबरेशन को करीब 1.5 फीसदी वोट मिले हैं.

दूसरी तरफ, भाकपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी, जबकि एक वक्त था, जब 1967 से लेकर 1995 तक इस पार्टी के विधायक अच्छी-खासी संख्या में जीतते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिहार की उस धरती से वामपंथ का लगभग सफाया हो गया, जहां कभी बेगुसराय को पूरब का मास्को और चंपारण को लेनिनग्राद के नाम से लोग जानते थे. यदि पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो यह साफ़ हो जाएगा कि राज्य में वामपंथ का बड़ा आधार था, लेकिन चुनाव में किसी भी वामपंथी दल को कोई सीट नहीं मिली थी. यहां तक की 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए चल रही सहानुभूति लहर में भी वामपंथी पार्टियों को 13 सीटें मिली थीं. लेकिन साल 2000 तक बिहार में वामपंथी पार्टियों की हालत खराब होती चली गई. वैसे तो पूरे देश से ही वाम दलों के आधार में कमी आती नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल, केरल से वे सत्ता से बाहर हो चुके हैं. त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में जरूर अभी भी उनकी सरकार है. 2014 के लोकसभा चुनाव में भी लेफ्ट को मुंह की खानी पड़ी. वैसे राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि वाम दलों के खस्ताहालत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं. खुद इन दलों ने अपने से विपरीत वैचारिक दृष्टिकोण वाली पार्टियों के साथ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गठबंधन कर अपने आधार को धीरे-धीरे खिसकने दिया और दूसरी तरफ उनके साथ आए दल मजबूत होते चले गए.

बिहार में वामपंथी दलों के अस्तित्व के बारे में सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का मानना है कि पार्टी के आंदोलन में कोई ठहराव नहीं हुआ है, उसमें विस्तार ही हो रहा हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिहार के वामपंथी जनाधार में कमी आई है. उन्होंने कुछ मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई. वैसे कहा ये भी जा रहा है कि पूरी दुनिया से वामपंथ के कमजोर होने का असर भारत में भी दिखा है और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में भी दिख रहा है, तो इसमें कोई आशचर्य की बात नहीं होनी चाहिए. बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला है कि छह वामपंथी पार्टियों का गठबंधन भी बिहार में अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करने में सफल नहीं हो पाया. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में वामपंथी दलों का अब तक का चुनावी नफा-नुकसान

वर्ष	भाकपा	माकपा	भाकपा (माले)
1952	0	--	--
1962	12	--	--
1967	24	04	--
1969	25	03	--
1972	35	00	--
1977	21	04	--
1980	23	06	--
1985	12	01	--
1990	23	06	--
1995	26	06	06
2000	05	02	06
2005	03	01	07
2010	01	00	00
2015	00	00	03

जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, तो चुनाव से पहले उनके नाम की बहुत चर्चा थी, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वह लालू यादव के माय समीकरण को बिगाड़ सकते हैं. एआईएमआईएम मुख्य रूप से हैदराबाद और तेलंगाना की पार्टी है और यह आम तौर पर हैदराबाद के आस–पास के क्षेत्र तक सीमित है. लेकिन पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतकर पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि ओवैसी यहां भी अपने उम्मीदवार उतार कर महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं. वह टीवी न्यूज शो में दिखने भी लगे थे.

सहयोगी दलों ने किया बेड़ा ग़र्क

सरोज सिंह

जब मंजिल तक पहुंचाने के लिए साथ आए दोस्त ही बोझ बन जाएं, तो रास्ता तय करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसकी बानगी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में खुलकर देखने को मिली. मिशन बिहार में जुटी भाजपा ने जब अपने सहयोगी दलों के बीच 85 सीटें बांट दीं, तो सवाल उठने लगा था कि कहीं उसने ग़लती तो नहीं कर दी. सवाल भाजपा के अंदर भी उठे, पर केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में स्थानीय नेताओं ने ज़्यादा मुंह नहीं खोला. पर अंदरखाने यह बात होने लगी थी कि सहयोगी दलों को उनकी हैसियत से ज़्यादा सीटें बांट दी गईं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. आख़िरकार यह आशंका सही साबित हुई और चुनाव नतीजों से साफ़ हो गया कि सहयोगी दल भाजपा के लिए बोझ ही बन गए. 85 सीटों में से केवल छह सीटें जीतकर सहयोगी दलों ने बिहार में महा–गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता बेहद आसान कर दिया. इसके उलट सहयोगी दल खुलकर तो नहीं, पर अंदरखाने कहने लगे हैं कि भाजपा अगर सहयोगी दलों को उचित सम्मान देती, तो नतीजे कुछ और ही होते. विज्ञापनों से लेकर भाषणों तक केवल एक ही नारा गूंजा, भाजपा सरकार और केवल भाजपा सरकार. सहयोगी दलों ने अंदरूनी बैठकों में कई बार कहा कि इससे जनता के बीच सही संदेश नहीं जा रहा है. इसके बाद कुछ पोस्टरों में जीतन राम मांझी, राम विलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे चमके, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी.

वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि सहयोगी दलों ने पार्टी की संभावनाओं को चौपट कर दिया. पहले तो सीटों के बंटवारे में सहयोगी दलों के कारण काफी देर हुई और कुछ खास इलाकों में सहयोगी दलों के दबाव के चलते भाजपा सही प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई. भाजपा नेता कहते हैं कि पार्टी बोचहा में बेबी कुमारी को लड़ाना चाहती थी, पर लोजपा के दबाव के चलते यह सीट उसे देनी पड़ी. बेबी कुमारी को लोजपा का उम्मीदवार बनाया गया, पर राम विलास पासवान के दामाद के दबाव के चलते बेबी कुमारी का टिकट काट दिया गया. हालात ऐसे हो गए कि बेबी कुमारी को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वह चुनाव जीत गईं. लोजपा ने अगर बेबी कुमारी का टिकट न काटा होता, तो यह सीट एनडीए के खाते में आ जाती. इसी तरह जमुई ज़िले की चारों सीटों को लेकर स्थानीय सांसद चिराग पासवान के अड़ियल रवैये के कारण वहां तीन सीटों का नुक़सान हो गया. चकाई सीट को लेकर चिराग इतने अड़े कि निवर्तमान विधायक सुमित कुमार को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा. हद तो यह हो गई कि वहां से लोजपा प्रत्याशी विजय सिंह मुक़ाबले में भी नहीं रहे और निर्दलीय लड़ रहे सुमित कुमार को लगभग 12 हज़ार वोटों से चुनाव हारना पड़ा. विजय सिंह 22 हज़ार वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे. अगर वहां से सुमित एनडीए के टिकट पर लड़ते, तो राजद की जीत संभव नहीं थी. इसी तरह लोजपा ने जमुई से एनडीए प्रत्याशी अजय प्रताप को मदद नहीं की. गठबंधन में रहते हुए भी चिराग अपनी जिद पर अड़े रहे और ज़िले में एनडीए को खासा नुक़सान हो गया. लोजपा ने जिस तरह से सगे–संबंधियों को टिकट दिए, उससे भी जनता के बीच सही संदेश नहीं गया. जनता की प्रतिक्रिया इतनी सख्त रही कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस बुरी तरह चुनाव हार गए. राम विलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज और दोनों दामाद भी चुनाव हार गए. हाल यह रहा कि 42 सीटों पर लड़ी लोजपा केवल तीन सीटें जीत सकी. इसी तरह जनता ने जीतन राम मांझी के बड़बोलेपन को भी नकार दिया. जीतन राम मांझी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बार–बार स्वयं को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते रहे. जनता को आभास हो गया कि अगर जीतन राम को ज़्यादा सीटें मिलीं, तो वह नई सरकार में विघ्न–बाधा ही पैदा करेंगे. हाल यह हुआ कि जीतन राम मांझी पूरे बिहार में तो छोड़िए, मगध में ही अपने वोट एनडीए को नहीं दिला पाए. मांझी से भाजपा ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध रखी थी, लेकिन उनके खराब प्रदर्शन ने एनडीए की संभावनाओं पर ग्रहण लगा दिया. हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी और उनके पुत्र चुनाव हार गए. घोसी से कभी न हारने वाले जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा भी चुनाव हार गए. हम से जुड़े नरेंद्र सिंह के दोनों बेटों को भी जनता ने नकार दिया. इसी तरह रालोसपा से भाजपा को भारी निराशा हाथ लगी. कुशवाहा वोटों को लेकर भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा पर अपना दांव खेला, लेकिन कुशवाहा वोटों का झुकाव महा–गठबंधन की तरफ़ रहा. उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, उसी से साफ़ हो गया था कि उनसे ज़्यादा उम्मीद करना बेमानी है. पार्टी हित में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए, पर चुनावी रणनीति के लिहाज से उनका यह फ़ैसला सही साबित नहीं हुआ. रालोसपा केवल दो सीटों पर ही विजय हासिल कर सकी. जानकार बताते हैं कि अब चूंकि एनडीए चुनाव हार गया है, इसलिए भाजपा हर हाल में चाहेगी कि हार का ठीकरा सहयोगी दलों के सिर पर फोड़ दिया जाए. पहली नज़र में यह सही भी दिखता है कि 85 में से अगर सहयोगी दल सिर्फ़ छह सीटें जीतते हैं, तो वे बोझ ही कहे जाएंगे. लेकिन, ग़लती सिर्फ़ एक तरफ़ से ही नहीं हुई है. यह साफ़ है कि भाजपा ने भी बहुत सारी ग़लतियां कीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश और लालू के लिए रास्ता आसान हो गया. राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को लेकर पुनर्विचार कर सकती है. पटना और दिल्ली में उनकी भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को लेकर क्या सोचती है और यह साथ लंबा खिंचता भी है या नहीं. ■

भाजपा नेताओं का कहना है कि सहयोगी दलों ने पार्टी की संभावनाओं को चौपट कर दिया. पहले तो सीटों के बंटवारे में सहयोगी दलों के कारण काफी देर हुई और कुछ खास इलाकों में सहयोगी दलों के दबाव के चलते भाजपा सही प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई.

feedback@chauthiduniya.com

पप्पू यादव, ओवैसी और तारिक अनवर बेअसर साबित हुए

शफीक आलम

बिहार चुनाव चुनाव से पहले मुस्लिम–यादव (माय) समीकरण के टूटने या उसमें सेंध लगने की बातें कही जा रही थीं. इस सन्दर्भ में तीन नाम लिए जा रहे थे. ये नाम थे– पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी (लो), असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) और तारिक अनवर की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी). ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि ये तीनों महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं. वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल भी ये इशारा कर रहे थे कि शायद इन तीनों ने माय समीकरण में कुछ न कुछ सेंध ज़रूर लगाया है. एनडीए के चुनाव जीतने और न जीतने में भी इन तीनों की कुछ न कुछ भूमिका रहने वाली थी. बहरहाल, चुनाव के आखिरी नतीजे इस लिहाज से अप्रत्याशित थे कि लगभग सभी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण या एग्जिट पोल कांटे की लड़ाई की उम्मीद लगाये हुए थे. लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि न तो पप्पू यादव या ओवैसी या फिर तारिक अनवर बिहार के मतदाताओं को प्रभावित कर पाए.

जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है तो चुनाव से पहले उनके नाम की बहुत चर्चा थी, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वह लालू यादव के माय समीकरण को बिगाड़ सकते हैं. एआईएमआईएम मुख्य रूप से हैदराबाद और तेलंगाना की पार्टी है और यह आम तौर पर हैदराबाद के आस–पास के क्षेत्र तक सीमित है. लेकिन पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतकर पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि ओवैसी यहां भी अपने उम्मीदवार उतार कर महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं. वह टीवी न्यूज शो में दिखने भी लगे थे. शुरू में यह खबर आई कि उनकी पार्टी राज्य के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सीमांचल की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. लेकिन फिर यह खबर आई कि वह एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में आ रहे हैं. अंत में उन्होंने केवल छह उम्मीदवार मैदान में उतारे लेकिन अगर चुनाव के नतीजों पर नज़र डाली जाए तो उनका खाता भी नहीं खुला. एक दो सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़ाई में दिखे लेकिन उनकी पार्टी का कोई खास असर नहीं हुआ. अगर वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो उनकी पार्टी को केवल 0.2 प्रतिशत वोट मिले. किशनगंज के कोचाधामन से अख्तरुल ईमान दूसरा स्थान हासिल कर सके. बाकी के किसी भी एआईएमआईएम उम्मीदवार का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा.

ओवैसी द्वारा केवल छह उम्मीदवार मैदान में उतारने पर ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह इतने कम उम्मीदवारों के साथ भारतीय मुसलमानों के नेतृव का दावा कैसे पेश कर सकते हैं? दरअसल उन्हें एहसास था कि सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव महागठबंधन की तरफ़ है और वे उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे. इसलिए उन्होंने मतदाताओं का मिजाज़ भांपते हुए केवल छह उम्मीदवार मैदान में उतारे. जैसा ख़बरों में भी आया कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर अपनी निगाह टिका रखी है. लेकिन बिहार विधान सभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए जो नतीजे आये हैं, वह किसी भी तरह से उत्साह जनक नहीं हैं. और उत्तर प्रदेश की उनकी राह आसान होती हुई नहीं दिख रही है.

लालू यादव के माय समीकरण का खेल बिगाड़ने के सिलसिले में जो दूसरा नाम लिया जा रहा था वह नाम पप्पू यादव का. चुनाव अभियान के दौरान उनकी कई सभाओं में अच्छी–खासी भीड़ भी दिखी जिससे लग रहा था कि वह कम से कम कोसी–मधेपुरा के यादव बहुल क्षेत्र में लालू और महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. लेकिन यहां के मतदाताओं ने पूरी तरह से लालू और महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया और पप्पू यादव को पूरी तरह से नकार दिया.

ओवैसी द्वारा केवल छह उम्मीदवार मैदान में उतारने पर ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह इतने कम उम्मीदवारों के साथ भारतीय मुसलमानों के नेतृव का दावा कैसे पेश कर सकते हैं? दरअसल उन्हें एहसास था कि सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव महागठबंधन की तरफ़ है और वे उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे.

शायद ओवैसी की तरह यह बात उनके विरुद्ध गई कि वह जीतने के लिए नहीं बल्कि केवल महागठबंधन को हराने के लिए मैदान में हैं. इसलिए उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी (लो) के उम्मीदवार मधेपुरा और कोसी क्षेत्र की सीटों पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. उनकी पार्टी को कुल वोट का केवल 1.4 प्रतिशत वोट मिल सका, और सहरसा, मधेपुर, सुपौल और पूर्णिया जहां पप्पू यादव की एक अच्छे नेता की छवि है, की किसी भी सीट पर कोई चुनौती पेश करते हुए नहीं देखे और न ही उनके उम्मीदवार महागठबंधन का खेल बिगाड़ते नज़र आये. जब समाजवादी पार्टी और एनसीपी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया तो पप्पू यादव ने उनके साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास किया लेकिन फिर वह प्रयास सफल नहीं हो पाया और उन्हें अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ा.

हालांकि एनसीपी का बिहार में कोई खास आधार नहीं है लेकिन तारिक अनवर इस पार्टी के बड़े नेता हैं और वह कटिहार से कई बार लोक सभा के लिए चुने गए हैं. शुरू में उनकी पार्टी राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली थी लेकिन एनसीपी ने छह सीटों के साथ महागठबंधन में शामिल होने से इंकार कर दिया था. इसलिए पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी और आशा के अनुरूप कटिहार की तीन सीटों पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा. कहिटार के प्राणपुर विधान सभा से उनकी उम्मीदवार इशरत प्रवीण दूसरे स्थान पर रहीं, तीसरा स्थान कांग्रेस को मिला. इस सीट से भाजपा के विनोद कुमार सिंह विजयी हुए. अगर एनसीपी महागठबंधन में शामिल हुई होती तो यह सीट वे जीत सकते थे. इसके इलावा एनसीपी, महागठबंधन को कोई नुकसान पहुंचाती नज़र नहीं आती. एनसीपी को बिहार के कुल वोट का केवल 0.5 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ.

कुल मिला कर देखा जाए तो तीनों पार्टियां लालू यादव के माय समीकरण को तोड़ने में नाकाम रहीं. इसकी एक वजह तो यह थी कि पप्पू यादव और ओवैसी पर यह आरोप लगा के वे चुनाव जीतने के बजाये एनडीए को फायेदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरे हैं. इसलिए न तो पप्पू यादव अपने वर्चस्व वाले यादव बहुल क्षेत्र में बेअसर दिखे वहीं ओवैसी और तारिक अनवर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

यह चुनाव परिणाम एक बेहतर राजनीतिक वातावरण बनाएगा

समाज के हर वर्ग की यह धारणा है कि नरेन्द्र मोदी परिणाम देने में असफल रहे हैं. यह एक उचित आकलन नहीं है. क्योंकि, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया था, जिन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं था. निष्पक्ष विश्लेषक यह समझते थे कि नरेन्द्र मोदी अपनी सभाओं में जो वादे कर रहे हैं, वे कभी पूरे नहीं किए जा सकते. लेकिन यदि आप ऐसी उम्मीदें जगाएंगे, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते तो आपको उसके परिणाम भुगतने के तैयार रहना होगा. हालांकि राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में न तो देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है और न ही महंगाई दर को काबू में करने की कोशिश की गई.

बिहार चुनाव परिणाम आ चुके हैं और जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भाजपा से आगे हैं, यह सच साबित हुआ. लेकिन यहां कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर विचार करना होगा. ज्यादातर एक्जिट पोल्स ने महागठबंधन को साधारण तौर पर जीतता दिखाया था. किसी ने भी महागठबंधन की इस तरह की बड़ी जीत और भाजपा की करारी हार की भविष्यवाणी नहीं की थी, न ही किसी ने इस तरह का कोई अनुमान लगाया था. इसके उलट, चाणक्य ने अपने एक्जिट पोल में भाजपा की बड़ी जीत की संभावना जताई थी, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन उसके एक्जिट पोल की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह गलत साबित हुआ था. लेकिन यह जरूर है कि उसका 2014 के लोकसभा चुनाव का अनुमान बिलकुल सही साबित हुआ था. कुल मिलाकर यह चुनाव परिणाम हमें कुछ सीख देता है. पहला, बिहार का मतदाता अलग तरह का मतदाता है. यूं ही लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने बिहार से अपने आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, यूं ही साल 1977 में केंद्र की सत्ता में आई जनता पार्टी की बुनियाद बिहार में नहीं रखी गई थी. यूं ही मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे कद्दावर समाजवादी विचारकों ने बिहार को अपनी कर्मभूमि नहीं बनाया था, वे वहां से चुनकर लोकसभा पहुंचे. बिहार की संस्कृति में यह शामिल है कि उसने हमेशा दूसरे प्रदेश के लोगों को खुले दिल से अपनाया.

भाजपा विकास की बात करके, बड़े-बड़े आर्थिक पैकेज और योजनाओं की घोषणा करके बिहार में एक अलग तरह का वातावरण तैयार करना चाहती थी, दरअसल यह बिहार के मतदाताओं का मज़ाक उड़ाना था. यह भाजपा के पक्ष में नहीं गया. इसके विपरीत मतदाताओं का असली चरित्र,आत्म-सम्मान, समावेशी धार्मिक समानता और सबके साथ एक समान व्यवहार में समाहित है जो कि इन नतीजों में भी जाहिर हुआ. भाजपा की तरफ से मतदाताओं को पिछड़े, अति-पिछड़े में बांटने की बहुत कोशिशें हुईं. उसने जीतन राम मांझी को जरूरत से ज्यादा सीटें और अहमियत दी. एक अति-पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया. उसकी इन सभी कवायदों का कोई नतीजा नहीं निकला. मैंने पहले भी कहा था कि मुलायम सिंह द्वारा बिहार में सौ या उससे अधिक उम्मीदवार खड़े करने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बिहार के यादव मतदाता यह बात अच्छी तरह जानते थे कि यह एक चाल है, जिससे यादव हार जाएं और भाजपा जीत जाए. इसी तरह ओवैसी भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सके, क्योंकि यहां का एक आम मुसलमान भी यह जानता है कि वह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं.

अब आगे की ओर देखते हैं बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की वापसी हुई है. लालू जी ने बिलकुल ठीक कहा है कि जनता ने हमें चुना है, यदि हम उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी. यह एक अच्छा संकेत है और इससे यह जाहिर होता है कि वह सहयोग के मूड में हैं. भाजपा के शुभचिंतकों और लालू के आलोचकों की यह सोच है कि लालू और नीतीश कभी एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन इसके विपरीत लालू जी के मौजूदा रुख से ऐसा नहीं लगता.

पूरे भारत के परिपेक्ष्य में अब जो तस्वीर उभरी है वह यह है कि अगले एक साल में तमिलनाडु, पुद्दूचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम आदि राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. केवल असम में भाजपा को जीत की उम्मीद है क्योंकि वहां उसका मुक़ाबला कांग्रेस से है. जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जहां भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुक़ाबला होता है वहां भाजपा को बढ़त मिल जाती है. कांग्रेस के खिलाफ सरकार विरोधी लहर (एंटी-इनकम्बेंसी) का भाजपा को फायदा मिल जाता है. पूर्व में सीएजी (कैग) द्वारा सामने लाए गए घोटाले भी कांग्रेस के ख़िलाफ जाते हैं. हालांकि, यदि मतदाताओं के पास अन्य कोई विकल्प होता है तो वे भाजपा को वोट नहीं देते हैं, अपवाद स्वरूप हरियाणा में भाजपा एक साधारण बहुमत हासिल करने में क़ामयाब रही, वह भी इसलिए क्योंकि वहां उसका मुक़ाबला कांग्रेस से था. महाराष्ट्र और झारखंड में उसे साधारण बहुमत भी हासिल नहीं हो सका. बिहार में एक बात पूरी तरह जाहिर हो गई कि यहां उसका मुख्य मुक़ाबला कांग्रेस से नहीं, बल्कि तीसरी ताकत से था. यहां तीसरी ताकत की साख बरकरार थी. जबकि दूसरी तरफ 2014 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा की साख बेहतर नहीं हुई थी.

समाज के हर वर्ग की यह धारणा है कि नरेन्द्र मोदी परिणाम देने में असफल रहे हैं. यह एक उचित आकलन नहीं है. क्योंकि, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया था, जिन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं था. निष्पक्ष विश्लेषक यह समझते थे कि नरेन्द्र मोदी अपनी सभाओं में जो वादे कर रहे हैं, वे कभी पूरे नहीं किए जा सकते. लेकिन यदि आप ऐसी उम्मीदें जगाएंगे, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते तो आपको उसके परिणाम भुगतने के तैयार रहना होगा. हालांकि राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में न तो देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है और न ही महंगाई दर को काबू में करने की कोशिश की गई. ऊपर से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत का समावेशी चरित्र बरकरार रह पाएगा? ये बेकार के सवाल हैं, जो संघ के लोगों के बेवकूफाना बयानों की वजह से उठते हैं. उन्होंने गाय, बीफ अथवा मांस खाने की आदत को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया. मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि महाराष्ट्र के गैर-राजनीतिक नौजवान, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को वोट किया, उन्होंने मुझे एसएमएस करके बताया कि वे खाने-पीने, टीवी देखने, किताबें पढ़ने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से निराश और दुखी हैं. उन्होंने लिखा कि अब उन्हें इस बात से हैरानी नहीं होती है कि कांग्रेस ने क्यों इस देश पर साठ साल तक राज किया. कांग्रेस सरकार चाहे जितनी भी भ्रष्ट और सुस्त क्यों न हो, लेकिन उसने कभी भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया. कांग्रेस के शासन में अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता थी. मुझे खुशी है कि अदालत ने कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता है. मिसाल के तौर पर अरून्धती रॉय, जिन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए. ये ऐसे विचार हैं, जिनसे आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन यह राष्ट्रद्रोह नहीं है. आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह उस वक्त बनता है, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो.

बदकिस्मती से इस सरकार में, पार्टी में और परिवार में (संघ परिवार में) सहनशक्ति की कमी है. वे छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं और अनुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं. ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें आप भले ही पसंद करें या नापसंद, लेकिन इसका असर बिहार के आम मतदाता पर पड़ा है. एक पत्रकार, जो बिहार के अंदरूनी इलाके में गईं थीं, उन्होंने मुझे बताया कि वह कुंए से पानी भर रही बिहार की एक निरक्षर औरत की चतुराई और समझ देखकर हैरान रह गईं. मैं समझता हूं कि इन सभी बातों की झलक बिहार चुनाव के नतीजों में दिखाई दी. लालू जी ने कहा है कि वह अब दिल्ली की गद्दी पर हमला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें धीमी गति से आगे बढ़ना चाहिए. बिहार सरकार को एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि किस तरह एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है. नीतीश जी ने सही कहा कि वे बिहार के विपक्ष का सम्मान करेंगे. उस भाजपा के लिए उन्होंने ऐसा कहा, जिसने लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के भीतर विपक्ष का सम्मान नहीं किया. बिहार विधानसभा में विपक्ष को उचित महत्व मिलना चाहिए. एक बार फिर, हम लोकतंत्र की जड़ों की तरफ चलते हैं. लोकतंत्र के संस्थापकों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, क़ानून मंत्री बी आर अंबेडकर ने ऐसे उदाहरण पेश किए कि किस तरह सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने तथ्यों को जोरदार व असरदार तरीके से रखा जा सकता है. बदकिस्मती से आजकल ऐसा नहीं हो रहा है.

मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है. भाजपा सत्ता में है. उसे कांग्रेस के साथ बैठना चाहिए और सदन को द्विपक्षीय कार्यशील सदन बनाकर अपने बिल पास करवाने चाहिए. जाहिर है कि मतभेद तो बने ही रहेंगे. जिस तरह अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच होते हैं, जैसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव-लेबर पार्टी के बीच मतभेद होते हैं. उनके बीच मतभेद होते हैं, लेकिन वे अपने आचरण का ख्याल रखते हैं. वे एक-दूसरे के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते. हमें आशा करनी चाहिए कि बिहार चुनाव के नतीजे देश में एक अच्छा राजनीतिक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होंगे, जो कि नीतीश कुमार और लालू यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. हमें आशा करनी चाहिए कि आने वाले दिन हमें सही राह दिखाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राजेश और उनके जैसे लोगों को सलाम

बेंगलुरु में गाय के ऊपर आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने गया था. छह तारीख की शाम मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलना था. मुझे मुख्यमंत्री के पास ले जाने के लिए बीआर पाटिल अपनी गाड़ी में आए और ले गए. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था. जब मुख्यमंत्री से मिलकर मैं वापस लौटा, तो इतनी भीड़ थी कि बीआर पाटिल की गाड़ी ने समय से मुझे होटल पहुंचाने से इंकार कर दिया और तब मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया. उस ऑटो रिक्शा के चालक का नाम राजेश था. थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वह दाएं-बाएं से निकलने वाले लोगों को गुस्से से घूरकर देख रहा है और कन्नड़ में कुछ कह रहा है. मैंने उससे पूछा, तुम पास से गुज़रने वालों, कार या मोटर साइकिल चलाने वालों से क्या कह रहे हो? उसने मुझसे कहा, मैं ऑटो चलाता हूं, सड़क ही मेरी ज़िंदगी है और मेरा दिमाग़ भन्ना जाता है, जब मैं बिना मतलब लोगों को हॉर्न बजाते हुए निकलते देखता हूं. उसने कहा कि इतना ध्वनि प्रदूषण इस हॉर्न की वजह से होता है और इसकी रोक का कोई उपाय हम लोग नहीं कर रहे हैं. मेरी रुचि जगी. मैंने उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ़ बताओ.

बेंगलुरु के उस ऑटो रिक्शा चालक राजेश ने मुझसे कहा कि आप इस सड़क को देख रहे हैं. यह वन-वे सड़क है. दूर-दूर तक इस पर नज़र जाती है. जहां रेड लाइट है, वह दूर से नज़र आती है. इसके बावजूद मोटर साइकिल पर चलने वाले लोग हों या कार में चलने वाले लोग हों, जबरदस्ती हॉर्न बजाते हैं और उस आवाज़ के शोर से शिराएं फटने लगती हैं. उसने कहा, मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक ऑटो चलाऊंगा, तब तक हॉर्न नहीं बजाऊंगा. और, सचमुच उसने हॉर्न नहीं बजाया. उसने मुझसे कहा, यही बात मैं अड़ोस-पड़ोस से निकलने वाले कार चालकों एवं मोटर साइकिल चालकों से कहता हूं कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो? जब तुम देख रहे हो कि सड़क खाली है, तब भी तुम हॉर्न बजाते हो. जब तुम देखते हो कि सड़क भरी हुई है और आगे जाने का रास्ता नहीं है, तब भी तुम हॉर्न बजाते हो. ऑटो रिक्शा चालक राजेश की बात सुनकर मुझमें कौतुहल जागा कि एक ऑटो चलाने वाला ध्वनि प्रदूषण के बारे में इतनी गंभीरता से सोच रहा है! इसके बाद उसने कहा, आप नहीं समझते, ये जो कार चलाने वाले हैं और मोटर साइकिल चलाने वाले हैं, ये सब पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं. इन्हें पता है कि प्रदूषण क्या होता है, खासकर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है. ध्वनि प्रदूषण लोगों के शरीर को उत्तेजना में ले आता है और उनमें असहनशीलता पैदा करता है. इसके बावजूद ये सारे पढ़े-लिखे समझदार लोग हॉर्न बजाते हुए चलते हैं. मैं इनसे यही कहता हूं कि हॉर्न मत बजाओ.

उस ऑटो रिक्शा चालक राजेश की बात सुनकर मुझमें और कौतुहल जागा और मैंने उससे पूछा, तुम इसके बारे में कबसे सोचने लगे? उसने कहा, मैं सन् 92 से इसके बारे में सोच रहा हूं और मैं लगातार सन् 92 से हॉर्न नहीं बजाता हूं तथा हर एक को समझाता हूं कि चलते हुए हॉर्न मत बजाओ. इसके बाद उस ऑटो रिक्शा चालक ने एक और कमाल की बात बताई. उसने कहा कि जब राष्ट्रपति जी की गाड़ी चलती है या प्रधानमंत्री जी की गाड़ी चलती है या गवर्नर साहब की गाड़ी चलती है या मुख्यमंत्री जी की गाड़ी चलती है, तो सड़क सिग्नल फ्री होती है. सड़क पर कोई सवारी नहीं होती. इसके बावजूद उनकी गाड़ी सायरन बजाते हुए निकलती है. क्या यह ध्वनि प्रदूषण नहीं है? जब आप खाली सड़क पर जहां कोई नहीं होता, रेड लाइट भी नहीं होती, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता, तब आप सायरन बजाते हुए निकलते हैं! इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों को ध्वनि प्रदूषण के लिए आमंत्रण देते हैं. मुझे उसकी बात में काफी तर्क नज़र आया और मुझे लगा कि इतना साधारण व्यक्ति जब इतनी गंभीरता से सोच रहा है, तो यह बात देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और किसी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सोचनी चाहिए और क्यों नहीं अमल करना चाहिए?

ऑटो रिक्शा चालक राजेश की बात सुनकर मुझमें और कौतुहल जागा और मैंने उससे पूछा, तुम इसके बारे में कबसे सोचने लगे? उसने कहा, मैं सन् 92 से इसके बारे में सोच रहा हूं और मैं लगातार सन् 92 से हॉर्न नहीं बजाता हूं तथा हर एक को समझाता हूं कि चलते हुए हॉर्न मत बजाओ.

ऑटो रिक्शा चालक राजेश मुझसे कहने लगा, सर, मैं इसे लेकर एक कैंपेन करना चाहता हूं. आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं पत्रकार हूं, तो उसने कहा, आप मुझे एक राय दीजिए. मैं अपने ऑटो रिक्शा के पीछे लिखवाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बाद आप हैं, जो इस देश में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं. और, हा..हा..हा (हंसी की आवाज़) लिखवाना चाहता हूं. मैंने कहा कि इससे क्या होगा? राजेश बोला, सर, इससे जो लोग मेरे पीछे ऑटो को देखेंगे, वे सोचेंगे कि क्या वे ध्वनि प्रदूषण के क्रम में इन चारों के बाद पांचवें हैं? हो सकता है कि वे ध्वनि प्रदूषण न करें. मैं उस ऑटो रिक्शा चालक राजेश की बात सुनकर चकित रह गया. उसने मुझसे इतना और पूछा, सर, मैं ग़रीब आदमी हूं, ऑटो चलाता हूं और अपने बच्चों का पेट पालता हूं. क्या इससे मुझे कोई नुक़सान तो नहीं होगा? मैंने उससे कहा, राजेश, तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं होगा और अगर कोई नुक़सान हो, तो तुम मुझे ख़बर करो. हम इसके बारे में तुम्हारे पक्ष में देश का जनमत बनाएंगे.

राजेश, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, जो निम्न-मध्यम वर्ग का भी नहीं है, वह अगर इतनी गंभीरता से ध्वनि प्रदूषण के बारे में सोच रहा है, तो क्यों बेंगलुरु या देश के पढ़े-लिखे लोग, जो कार और मोटर साइकिल रखने की हैसियत रखते हैं, जो उच्च वर्ग और उच्च-मध्यम वर्ग से आते हैं, वे इसके बारे में नहीं सोच सकते? और, जब तक बहुत आवश्यक न हो, तब तक गाड़ी का हॉर्न न बजाएं, क्या इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं ले सकते? बस वाले चलते हैं, तो प्रेशर हॉर्न बजाते हैं. टैक्सी वाले चलते हैं, तो हॉर्न बजाते हैं. किसी भी शहर का यह किस्सा है और इससे कितने लोगों के मन में एक असंवेदनशील किस्म की प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसे लोग नहीं समझ रहे हैं. मैंने पूछा, राजेश, तुम सड़क पर ऑटो चलाते हो, बेंगलुरु में ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, क्या इसका कोई हल नहीं है? उसने कहा कि हल है. आठ साल पहले बेंगलुरु में मेट्रो बननी शुरू हुई थी, जो पांच साल में पूरी होनी थी. अगले पांच साल भी वह पूरी नहीं होगी और फिर उसके बाद अगले पांच साल भी वह पूरी नहीं होगी. बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या का हल मेट्रो नहीं है. मेट्रो उनके लिए है, जो पैसे खाना चाहते हैं. उसने कहा कि बहुत कम पैसा यानी मेट्रो के बजट का 15 प्रतिशत अगर सरकार सिर्फ़ बेंगलुरु शहर में कुछ अंडरपास और कुछ फ्लाईओवर बनाने में खर्च कर दे, तो ट्रैफिक समस्या सुधर सकती है, पर सरकार यह नहीं सोचेगी.

तब मुझे लगा कि हम समस्याओं के बारे में उनसे कभी राय नहीं लेते, जो उन समस्याओं से वर्षों से रूबरू हो रहे हैं, वह चाहे बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या हो, देश में स्वच्छता अभियान की विफलता हो, गंदगी की समस्या हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो. किसी चीज के बारे में हम खुद तो कुछ सोचते ही नहीं और सरकार उन लोगों से भी सुझाव नहीं मंगाती, जो भुक्तभोगी हैं. अगर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जनता से समस्याओं के निदान मांगें, तो शायद उन्हें ऐसे-ऐसे निदान मिल जाएंगे, जिनके ऊपर न खर्च होगा और जिन्हें अमल में लाने से लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी. हां, इतना ज़रूर है कि भ्रष्टाचार कम होने से बहुत सारे लोगों की जेब में पैसा जाने से बच जाएगा और शायद हर नए उपक्रम में लगने वाले पैसे की लूट रुक जाए. यह बात भला लोगों को कहां बर्दाश्त होती है?

मैं उस ऑटो रिक्शा चालक राजेश को सचमुच तहेदिल से सलाम करना चाहता हूं, जिसने इस समस्या के बारे में सिर्फ़ सोचा ही नहीं, बल्कि सन् 92 से हॉर्न न बजाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. क्या उस ऑटो रिक्शा चालक राजेश का अनुकरण पढ़े-लिखे, सोचने-समझने वाले, कार और मोटर साइकिल रखने वाले लोग कर पाएंगे? अगर नहीं अनुसरण करते हैं, तो फिर मेरी समझ से उनकी समझदारी एक ऑटो रिक्शा चालक से बहुत कम है. लेकिन, खुशी की बात यह है कि राजेश जैसे और भी लोग होंगे, जो इस तरह से सोचते होंगे. उन सारे लोगों को मैं अपने इस संपादकीय में प्रणाम करता हूं. ■

editor@chauthiduniya.com

सदफ जरीन

असुरक्षित आधी आबादी

वर्ष 2013 में जब दिल्ली की एक विशेष अदालत ने निर्भया के गुनहगारों को सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया, तो देश की जनता के बीच एक उम्मीद-सी बंधी थी, एक सार्थक संदेश पहुंचा था कि महिलाओं, युवतियों, किशोरियों एवं बच्चियों की अस्मत से खेलने वाले दरिंदे अब ऐसा कुछ करने से डरेंगे. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014 में देश भर में सामूहिक दुष्कर्म के 2,300 मामले सामने आए, जिनमें से 570 मामले उत्तर प्रदेश के हैं.

बीते 24 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई. इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगतिशील क़दम भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं के मद्देनज़र उठाया जा रहा है, ताकि उन्हें अपनी क्षमता साबित करने का समान अवसर मिले. स्पष्ट है कि रक्षा मंत्रालय को भी देश की बेटियों के साहस एवं योग्यता पर पूर्ण विश्वास है. जहां एक ओर भारतीय वायुसेना एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में महिलाओं को मौक़े दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में सरकार के सारे प्रयास विफल साबित होते नज़र आ रहे हैं. कहने को तो बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके हम खुद के लिए एक सवाल बनकर रह गए हैं कि हमने लड़की होने का सौभाग्य पाया है या शाप? हम खुद पर गर्व करें या बेटी होने का मातम मनाएं? हमारा समाज कितना भी आगे क्यों न चला गया हो, पर सोच आज भी वही पुरानी है. लड़कियां चांद तक पहुंच गईं, लेकिन वे उस समाज को नहीं बदल सकीं, जिसमें उनका जन्म हुआ.

देश में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटनाएं नित्य अख़बारों की सुर्खियां बनती हैं. यही नहीं, जब कोई लड़की अथवा महिला ऐसे किसी हादसे की शिकार बनती है, तो समाज और उसके सगे-संबंधी उसकी पीड़ा समझने के बजाय उसे ही दोषी ठहराते हैं. कई बार तो पीड़िता को घर से निकाल दिया जाता है, ताकि परिवार की इज्जत बरकरार रहे. अधिकतर मामलों में पीड़िता के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. चंद मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, जिनमें वे घर वालों के सहयोग से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाती हैं. ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले का एक परिवार है, जिसकी एक नाबालिग बच्ची दुष्कर्म की शिकार होने से गर्भवती हो गई, लेकिन समाज की परवाह किए बिना पूरी हिम्मत के साथ उसने बच्चे को जन्म दिया और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुट गई. उस मासूम के साथ जो हुआ, उसे वह भुला नहीं सकती, लेकिन माता-पिता से मिले समर्थन के बाद उसने खुद को संभाला. अगर हर माता-पिता इसी तरह अपनी बेटियों की ताकत बन जाएं, तो समाज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि ऐसे हादसों के बाद अधिकतर माता-पिता अपनी पीड़ित बेटी से मुंह मोड़ लेते हैं. कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों के पीछे ऐसे हादसों की आशंका भी एक वजह है. दुष्कर्म के अधिकतर मामले बदनामी के डर से अभिभावकों द्वारा दबा दिए जाते हैं और जो मामले

बमुश्किल पुलिस तक पहुंचते भी हैं, उनमें न्याय पीड़िता के मरने के बाद ही मिलता है या फिर समाज में पूरी तरह बदनाम होने के बाद.

दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं और आधी आबादी की सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय हैं. वर्ष 2013 में जब दिल्ली की एक विशेष अदालत ने निर्भया के गुनहगारों को सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया, तो देश की जनता के बीच एक उम्मीद-सी बंधी थी, एक सार्थक संदेश पहुंचा था कि महिलाओं, युवतियों, किशोरियों एवं बच्चियों की अस्मत से खेलने वाले दरिंदे अब ऐसा कुछ करने से डरेंगे. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014 में देश भर में सामूहिक दुष्कर्म के 2,300 मामले सामने आए, जिनमें से 570 मामले उत्तर प्रदेश के हैं. एनसीआरबी के मुताबिक, पूरे देश में दुष्कर्म के लगभग 37,000 मामले प्रकाश में आए, जिनमें 197 मामले पुलिस हिरासत में अंजाम दिए गए और उनमें भी 90 फ़ीसद यानी 189 मामले उत्तर प्रदेश के हैं. दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल रहा, जबकि राजस्थान दूसरे पायदान पर. निर्भया प्रकरण के बाद एक नया क़ानून बना, वह अमल में भी आया, लेकिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं. पार्कों, सार्वजनिक शौचालयों एवं बाज़ारों में भी महिलाएं, युवतियां, किशोरियां और बच्चियां आएदिन वहशियों का शिकार बन जाती हैं. कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं को हर पल ख़तरा महसूस होता रहता है.

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने बंगलुरू में आयोजित महिला अधिवक्ताओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि महज सख्त क़ानून बना देने से महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा रोकना असंभव है. इसे रोकने के लिए एक समग्र प्रक्रिया विकसित करने के साथ-साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि यह केवल क़ानून का मसला नहीं है. दरअसल, हमारे देश एवं समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह समस्या के समाधान के लिए क़ानून को अंतिम विकल्प मानता है, जबकि क़ानून समाधान का अंतिम विकल्प नहीं है. समस्याओं का समाधान समाज के स्तर पर भी हो सकता है, बशर्ते वह न्यायपरक हो. महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है, वह चाहे यौन हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो अथवा समाज के स्तर पर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा. ■ (चरखा)

feedback@chauthiduniya.com

खादी अब ग़रीबों को लूटने के लिए है-2

मज़दूरों के पसीने पर मैनेजरों की मौज

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिताः नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

सन् 1972 तक मगहर खादी आश्रम का काम बहुत बढ़ गया था. उस समय यहां तीन सौ पचास के क़रीब मज़दूर थे, हालांकि उनमें से सौ को ही नियुक्ति-पत्र मिला. किसी को 55 रुपये, किसी को 60 और किसी को 70 रुपये पर नेट कार्यकर्ता बनाया गया. किसको कितना मिलेगा, यह व्यवस्थापकों की मर्जी पर था. जो उनके घर बेगार करता था, उसे अधिक मिलता था. बहरहाल, कुल मज़दूरों में साधारण कार्यकर्ता केवल पचास-साठ थे, बाकी सभी नेट थे. सन् 1971 के बाद भी बिना नियुक्ति-पत्र दिए मज़दूरों की भर्ती होती रही. उनकी दैनिक मज़दूरी थी डेढ़ रुपये, दो रुपये तथा अधिकतम ढाई रुपये. नियुक्ति-पत्र प्राप्त नेट कार्यकर्ता को पांच रुपये वार्षिक वेतनवृद्धि मिलती थी. महंगाई भत्ता बढ़ाने की कोई निश्चित दर नहीं थी. जब जैसा मन में आया, भत्ता देने लगे. सन् 1981 आते-आते मगहर के गांधी आश्रम में 450 मज़दूर हो गए. उनमें लगभग 50 साधारण कार्यकर्ता, 200 नेट एवं 200 दैनिक मज़दूरी पर काम करने वाले थे. सन् 1981 में नेट मज़दूरों में सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाला मज़दूर 195 रुपये महीना पाता था तथा साधारण कार्यकर्ता 231 रुपये और कार्यकर्ता पाता था 300 रुपये.

राम खेलावन हरिजन है. सन् 1955 में दस आना रोज़ पर उसकी भर्ती हुई थी. जब आश्रम बन रहा था, तो उसे दो मील से रोड़ा ढोकर लाने के लिए प्रति बोरी दो आना मिलता था. बाद में वह सरंजाम विभाग में काम करने लगा, जहां आरा मशीन पर उससे दिन भर कभी नौ, कभी दस घंटे काम लिया जाता था, रात में उससे पहरा भी दिलवाया जाता था, जिसकी मज़दूरी चार आना प्रति रात दी जाती थी. सन् 1958 में उसे नेट कार्यकर्ता का नियुक्ति-पत्र दिया गया तथा वेतन निश्चित हुआ 45 रुपये महीना. सन् 1981 में उसे 250 रुपये महीना मिल रहा था. पिछले कुछ सालों से रात की मज़दूरी बढ़कर 50 पैसा हो गई थी. राम खेलावन की स्थिति यह थी कि वह खुद लकड़ी ढोकर लाता था तथा चीरता था. दिन में 10 घंटे की मेहनत करने के बाद यदि कभी ग़लती से रात में सो जाता था, तो कभी पैसा कट जाता था, कभी उसे निलंबित कर दिया जाता था. व्यवस्थापकों के यहां बेगार अलग से करनी पड़ती थी. उनके पैर दबाने पड़ते थे, गाय का चारा लाना पड़ता था. कभी ऐतराज करने पर या बहुत थका होने के कारण कोई बताया गया बेगार करने में असमर्थता व्यक्त करने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती थी. ऐसे मौक़ों पर, जहां आरा मशीन चलती थी, वहां उसे बंद कर बाहर से ताला लगा दिया जाता था. टट्टी-पेशाब तक बंद.

श्रीपत भी हरिजन है. वह भी दस आना रोज़ पर सन् 1955 में भर्ती हुआ था और रोड़ा ढोता था. बाद में उसे घानी पर तेल पेरने के काम पर लगा दिया गया. आठ सेर की घानी लगती थी, पर केवल दो बैल थे. तीन बजे रात से दिन के दस बजे तक और फिर दो बजे दिन से शाम छह बजे तक घानी चलानी पड़ती थी. 12 घंटे की इस कठोर मेहनत का पारिश्रमिक मिलता था एक रुपये रोज़. सन् 1981 आते-आते खादी आश्रम, मगहर में छह कोल्हू हो गए. दो आदमी कोल्हू पर रहते थे तथा एक बैलों को चारा-पानी देता था. काम के घंटे वही बने रहे. कभी सरसों से तेल कम निकलता, तो उन्हें अपनी जेब से उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती. रात में पहरा भी देना पड़ता था. अगर कभी छुट्टी पर जाना पड़े, तो अपनी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति देकर जाना होता था. सन् 1981 में श्रीपत तथा उसके सहकर्मियों को कुल मिलाकर 195 रुपये महीना मिल रहा था.

रामबली धोबी को सन् 1957 में एक रुपये रोज़ देने की बात कहकर भर्ती किया गया था, पर दिया जाता था सिर्फ़ 14 आना. वह कपड़ों को तेजाब के पानी से खंगालता था, फिर उनकी पिटाई-धुलाई करता था. उसके बाद साबुन-सोडे के पानी से पुन: धोकर, सुखाकर कपड़ों को तह करना पड़ता था. वह सबेरे आठ बजे आता था तथा रात आठ बजे जाता था. नियमित काम करने के अलावा उसे गाय के लिए घास छीलनी पड़ती, व्यवस्थापकों के परिवार के कपड़े धोने पड़ते. रात में पहरा तो देना ही पड़ता था. तेजाब व सोडे से उसकी तथा उसके साथियों की देह जल जाती थी और सड़ने लगती थी, तब भी उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाती थी. भर्ती होने के आठ वर्ष बाद उसे नियुक्ति-पत्र मिला. सन् 1981 में उसका वेतन था 150 रुपये महीना. तीरथ सिंह सन् 1962 में भर्ती हुआ, पर उसकी बाकायदा नियुक्ति हुई सन् 1971 में, वह भी बीस आना रोज़ पर. सबसे पहले उसे गायों के लिए घास छीलकर लाना पड़ता था. बाद में सूत को भिगोकर पकाने और रंगने का काम मिला. वह सुबह आठ बजे आता था और रात आठ बजे जाता था. काम के दौरान अक्सर उसके हाथ जल जाया करते थे, लेकिन दवा का कोई इंतजाम नहीं था. तीरथ सिंह के अनुसार, कास्टिक सोडा पड़ने से कुछ लोगों की तो आंखें तक चली गईं.

यह सूची बहुत लंबी है. वस्तुतः श्री गांधी आश्रम के अंतर्गत काम करने वाले हज़ारों कार्यकर्ता आज भी बंधुआ मज़दूरों की तरह अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं. जब खादी का काम शुरू हुआ, तब गांधी जी ने श्रीकृष्ण दास जाजू के एक सवाल के जवाब में कहा था, आज हम सच्चे अर्थ में देहातियों की मदद नहीं करते. कातने वालों को हम तीन आना से आठ आना तक दे पाते हैं और संतोष मानते हैं कि हमने उनको रोज़ी दी. सच्चे अर्थ में मैं उनको भिक्षा देता हूं. उस समय तो कम पैसा देना मजबूरी थी, लेकिन आज जब गांधी आश्रम लाभ कमाने वाली संस्था बन गया है, तब कार्यकर्ताओं को उचित वेतन न देना, उनसे जानवरों की तरह काम कराना न मानवता की दृष्टि से उचित है और न क़ानूनी दृष्टि से. कम से कम खादी की चेतना तो यह नहीं ही है. जिस पर सिफत यह कि एक तरफ़ तो कार्यकर्ताओं की ऐसी दयनीय हालत है और दूसरी तरफ़ व्यवस्थापक आश्रम का अधिकांश काम ठेकेदारी पर कराते हैं. ठेका भी उन्हीं को दिया जाता है, जिनसे आश्रम व्यवस्थापकों को अतिरिक्त आमदनी की आशा हो.

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

अतीस के पौधे 30-60 सेमी ऊंचे, बहुवर्षीय शाकीय होते हैं. इसका काण्ड सीधा, सरल और आधार पर शाखान्वित तथा अरोमिल गोल, ऊपर की ओर सूक्ष्म रोमिल, विभिन्न आकार की पत्तियों से घिरा हुआ होता है. इसके पत्र 5-10 सेमी लंबे, विभिन्न आकार की, लट्वाकार, हृदयाकार,तीक्ष्णाग्र या गोलाग्र, नीचे के पत्ते बड़े, प्राय: पांच पालियों युक्त ऊपर के पत्र छोटे अखण्ड, स्तम्भलिंगी और तीक्ष्ण दन्तुर होते हैं.

अतीस

यह पौधा भारत में हिमाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में 2000-5000 मी. की ऊंचाई तक उच्च पर्वतीय शिखरों पर पाया जाता है. इस वनौषधि का ज्ञान हमारे आचार्यों को प्राचीनकाल से था. प्राय: समस्त रोगों को दूर करने वाला यह पौधा विश्वा या अतिविश्वा के नाम से वेदों में प्रसिद्ध है.

यह पौधा भारत में हिमाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में 2000-5000 मी की ऊंचाई तक उच्च पर्वतीय शिखरों पर पाया जाता है. इस वनौषधि का ज्ञान हमारे आचार्यों को प्राचीनकाल से था. प्राय: समस्त रोग को दूर करने वाली होने से यह विश्वा या अतिविश्वा के नाम स वेदों में प्रसिद्ध है.

बाह्यस्वरूप : अतीस के 30-60 सेमी ऊंचे, बहुवर्षीय शाकीय पौधे होते हैं. इसका काण्ड सीधा, सरल और आधार पर शाखान्वित तथा अरोमिल गोल, ऊपर की ओर सूक्ष्म रोमिल, विभिन्न आकार की पत्तियों से घिरा हुआ होता है. इसके पत्र 5-10 सेमी लंबे, विभिन्न आकार की, लट्वाकार, हृदयाकार,तीक्ष्णाग्र या गोलाग्र, नीचे के पत्ते बड़े, प्राय: पांच पालियों युक्त ऊपर के पत्र छोटे अखण्ड, स्तम्भलिंगी और तीक्ष्ण दन्तुर होते हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- अतीस दीपन, पाचन ग्राही, ज्वरातिसारनाशक, कृमिघ्न, काम नाशक एवं अर्शोघ्न, बालकों के छर्दि, कास आदि रोगों में विशेष रूप से उपयोगी है.
- अतीस की मूल वाजीकारक, पाचक, ज्वरघ्न, कटु, बलकारक, कफनि:सारक, आमाशयक्रियावर्धक, चतुर्थक ज्वर, कृमिरोग, अर्श, आभ्यंतर रक्तस्राव, आभ्यन्तर शोथ तथा सामान्य शोथ तथा सामान्य दौर्बल्य में हितकर है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

वक्ष रोग:

1 श्वास-कास-5 ग्राम अतीस मूल के चूर्ण में 2 चम्मच मधु मिलाकर चटाने से खांसी मिटती है.

2 2 ग्राम अतीस और 1 ग्राम पोहक मूल (पुष्कर मूल) के चूर्ण में 2 चम्मच मधु मिलाकर चटाने से श्वास-कास रोग में लाभ होता है.(प्राय: हिमालय के उच्च क्षेत्रों में अतीस और कुटकी ही अनेक रोगों में प्रयोग किया जाता है.)

3 कास-श्वास-सोंठ, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कटश्रृंगी तथा यवक्षार से बनाए चूर्ण (1-2 ग्राम) में मधु मिलाकर सेवन करने से कास रोग का शमन होता है.

उदर रोग:

1. वमन-2 ग्राम नागकेशर और 1 ग्राम अतीस के चूर्ण को खाने से वमन बंद होती है.
2. पाचनशक्तिवर्धनार्थ- 2 ग्राम अतीस मूल के चूर्ण को 1 ग्राम सोंठ या 1 ग्राम पीपल के चूर्ण के साथ मिलाकर मधु के साथ चटाने से पाचन शक्ति बढ़ती है.
3. पित्तोदर-20 मिली गोमूत्र के साथ लगभग दो ग्राम अतीस चूर्ण को पिलाने से पित्तोदर में लाभ होता है.
4. अतिसार- अतिसार और रक्तपित्त में 3 ग्राम अतीस के चूर्ण को, 3 ग्राम इन्द्रजौ की छाल के चूर्ण और 2 चम्मच शहद के साथ देने से अतिसार और रक्तपित्त में लाभ होता है.
5. संग्रहणी- अतिसार पतला, श्वेत, दुर्गन्ध युक्त हो तो अतीस और शुंठी 10-10 ग्राम दोनों को कूटकर, 2 ली पानी मे पकाएं, जब आधा शेष रह जाए तब छौंककर, फिर इसमें थोड़ा अनार का रस और लवण मिलाकर थोड़ा-थोड़ा करके दिन में 3-4 बार पिलाने से संग्रहणी और आमातिसार में लाभ होता है.
6. अतिसार- अतिविषावलेह- (बेल की गिरी, मोचरस, लोध्र, धाय का फूल, आम की गुठली की मींगी, अतिविषा तथा शहद) को मात्रानुसार सेवन करने से तीव्र अतिसार में लाभ होता है.
7. ग्रहणी- सोंठ अतिविषा तथा नामरमोथा से बनाए क्वाथ या कल्क को गुनगुने जल के साथ सेवन करने से ग्रहणी रोग में आमदोष का पाचन होता है.
8. अंकोल मूल त्वक चूर्ण (3 भाग) तथा अतीस चूर्ण (1 भाग) को मिलाकर 1-3 ग्राम की मात्रा में तण्डुलोदक के साथ पीने से ग्रहणी आदि उदर व्याधि का शमन होता है.
9. उदर रोग- लाल चंदन, खस, नेत्रवाला, कुटज त्वक, पाठा, कमल , धनिया, गिलोय, चिरायता, नागरमोथा, कच्चाबेल, अतीस तथा सोंठ इन औषधियों से बनाए क्वाथ में मधु मिलाकर पीने से छर्दि, तृष्णा, दाह, अरुचि तथा जवरातिसार में लाभ होता है.
10 सोंठ, गुडूची, अतीस तथा नागरमोथा इन चारों द्रव्यों से बनाए क्वाथ का प्रयोग करने से मंदाग्नि-जन्य, आमयुक्त ग्रहणी रोग में लाभ होता है.
11. अतीस के दो ग्राम चूर्ण को हरड़ के मुरब्बे के साथ खिलाने से आमातिसार मिटता है.

गुदा रोग:

1. रक्तार्श- अतीस में राल और कपूर मिलाकर इसका धुआं देने से रक्तार्शजन्य रक्तस्राव में लाभ होता है.

प्रजनन संस्थान रोग:

1. इन्द्रजौ, अतीस, कटुत्रिक, बिल्व, नागरमोथा तथा धाय के फूल, इनका चूर्ण बनाकर 1-2 ग्राम चूर्ण में शहद मिलाकर खिलाने से रक्तप्रदर में लाभ होता है.

त्वचा रोग:

1. फोड़े-फुन्सी-अतीस के 5 ग्राम चूर्ण को फांककर (खाने से) ऊपर से चिरायते का अर्क पीने से फोड़े फुन्सी मिटते हैं.

सर्वशरीर रोग:

1. रोगप्रतिरोधक क्षमतावर्धनार्थ- नागरमोथा, अतीस, काकड़ा सिंगी और करंज के भुने हुए बीज, चारों द्रव्यों को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर, इन्द्रयव की छाल के क्वाथ में 12 घंटे खरलकर 65 मिग्रा की गोलियां बना लें, दिन में दो बार सुबह-शाम 1-2 गोली देने से बच्चों के सब विकार शांत हो जाते हैं. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है.
2. बलवर्धनार्थ- छोटी इलायची और वंशलोचन, इन दोनों के साथ अतीस के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को मिलाकर मिश्री युक्त दुग्ध के साथ लेने से बल बढ़ता है एवं यह पौष्टिक व रोगनाशक है.
3. ज्वरजन्य दौर्बल्य- 3 ग्राम अतीस चूर्ण तथा 125 मिग्रा लौहभस्म को 500 मिग्रा शुंठी चूर्ण के साथ मिलाकर देने से ज्वर के पश्चात होने वाली निर्बलता मिटती है.
4. ज्वर- 1-1 ग्राम अतीस चूर्ण को दिन में 4-5 बार गर्म जल के साथ देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है और मूत्र भी साफ होता है.
5. ज्वर आने के पहले अतीस के 2-2 ग्राम चूर्ण को 2-2 घंटे के अंतर से देने पर ज्वर उतर जाता है.
6. अतीस के 625 मिग्रा चूर्ण को देने से ज्वरजन्य दाह का शमन होता है.
7. ज्वर छुड़ाने के लिए अतीस के 625 मिग्रा चूर्ण में 200 मिग्रा हरा कासीस भस्म मिलाकर देना चाहिए.
8. विषम-ज्वर छुड़ाने के लिए इसके एक ग्राम चूर्ण में 75 मिग्रा कुनैन मिलाकर, दिन में इतनी मात्रा दो-तीन बार खिलाने से विषम-ज्वर में लाभ होता है.

बाल रोग:

1. अतीस के कन्द को पीसकर चूर्ण कर शीशी में भर कर रख लें. बालकों के तमाम रोगों में (उदरशूल, ज्वर, अतिसार आदि) यह लाभकारी है. बालक की उम्र के अनुसार 250 से 500 मिग्रा तक शहद के साथ दिन में दो-तीन बार चटाने से बालकों के सभी रोगों में लाभ होता है.
2. अतिसार और आम अतिसार में 2 ग्राम अतीस के चूर्ण को देकर 8 घंटे तक पानी में भिगोई हुई 2 ग्राम सोंठ को पीसकर पिलाने से लाभ होता है. जब तक अतिसार नहीं मिटे, तब तक नित्य देना चाहिए.
3. अतीस मूल को कूटकर रात्रि में दस गुने जल में भिगो दें, प्रात:काल पकाएं, जब शहद जैसा गाढ़ा हो जाये या गोलियां बनाने लायक हो जाए तो 500-500 मिग्रा की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें. हैजे में 3-3 गोली 1-1 घंटे के अंतर से तथा प्लेग में 3-3 गोली दिन में बार-बार खिलायें.
4. 2 ग्राम अतीस और 2 ग्राम वायविडंग का चूर्ण लेकर 1-1 ग्राम शहद के साथ चटाने से बच्चों के कृमि नष्ट हो जाते हैं.
5. 1 ग्राम से 10 ग्राम तक अतीस को पानी में पीसकर दिन में 2-3 बार, बल और आयु के अनुसार देने से अतिसार मिटता है.

रसायन वाजीकरण:

1. वाजीकरणार्थ- 5 ग्राम अतीस के चूर्ण को शक्कर और दूध के साथ देने से वाजीकरण गुणों की वृद्धि होती है.

प्रयोज्या: मूल (कन्द)

मात्रा: चूर्ण 1-2 ग्राम चिकित्सक के परामर्शानुसार ■

आचार्य बालकृष्ण

आरटीआई से करें सरकारी कार्यों का निरीक्षण

अगर आप किसी सरकारी कार्य का निरीक्षण करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में संपन्न कार्यों की सूचना चाहते हैं, उन कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार का पता लगाना चाहते हैं, अगर आपको किसी सूचना की दरकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इस योजना से सम्बंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाये:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-2(जे)(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है. इसके तहत मैं निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे तिथि, समय व स्थान बतायें, जब मैं आकर इस कार्य की जांच कर सकूं.

(कार्य का विवरण)

2. मैं निरीक्षण के समय इस कार्य से सम्बंधित निम्नलिखित दस्तावेजों का भी निरीक्षण करना चाहूंगा, इसलिए निरीक्षण के समय ये दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं:

क. मेज़रमेंट बुक
ख. खर्चों का विवरण
ग. रेखाचित्र

इन दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो कानून के तहत निर्धारित फीस लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं.

3. धारा-2(जे)(3) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री का प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है. इसके तहत

मैं उपरोक्त कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं. नमूना मेरे द्वारा तय स्थान से मेरी उपस्थिति में विभाग द्वारा एकत्र किया जाए और यह सीलबन्द हो तथा विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सीलबन्द नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है. कृपया मुझे स्थान समय तथा तिथि सूचित करें, जब मैं प्रमाणित नमूने के लिए आ सकूं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक (यदि कुछ हो) :

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड के पास सीलैंड नाम का एक ऐसा देश है, जहां राजा से लेकर प्रजा तक कुल 27 लोग ही रहते हैं. यह छोटा देश इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है. इस देश का नाम सीलैंड है. दरअसल, यह देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए समुद्री किले पर स्थित है, जो अब खंडहर होने की कगार पर है.

क्या नेपाल का चीनीकरण हो रहा है

नेपाल के बीरगंज में पुलिस फ़ायरिंग में एक भारतीय की मौत और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उस घटना की निंदा के बाद भारत और नेपाल तनाव के दौर से गुजर रहे हैं. दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. भारत नेपाल के बीच ये कड़वाहट किस हद तक पहुंचेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारत को इस समय उचित कूटनीति का परिचय देते हुए नेपाल को विश्वास में लेना जरूरी है, क्योंकि चीन भी दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों की इस आग में घी डालने का काम करने लगा है. पड़ोसी देश होने के कारण नेपाल का चीनीकरण होना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है.

नेपाल की भारत से बढ़ती दूरियां भारत के लिए चिन्ता का विषय हो सकती है, लेकिन उससे कहीं अधिक नेपाल के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए. अगर भारत का नेपाल पर प्रभाव कम हो रहा है तो स्पष्ट है कि चीन का नेपाल पर प्रभाव बढ़ रहा है. नेपाल की चीन से नजदीकियों से नेपाल की स्थिति चाइनीज समान की तरह हो जाएगी, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती. सवाल यह भी है कि क्या नेपाल का चीनीकरण हो रहा है? क्या चीन का पूर्ण समर्थन और भारत की उपेक्षा कर ओली नए नेपाल का निर्माण कर पाएंगे?

राजीव रंजन

करीब महीना भर पहले भारत और नेपाल में जमकर तनातनी हुई थी. उस समय नेपाल ने भारत से कहा था कि अगर वह नेपाल को समानों की आपूर्ति में बाधा पहुंचाएगा तो वह चीन की ओर झुकने को विवश हो जाएगा. नेपाल के इस धमकी के जवाब में भारत ने यह साफ किया था कि उसका नेपाल के सामानों की आपूर्ति में बाधा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है. भारत का कहना था कि बाधा उस देश में प्रदर्शन एवं अशांति की वजह से पहुंची है, क्योंकि भारतीय कंपनियों एवं ट्रांसपोर्टरों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है. हालांकि नेपाल यह स्वीकार भी करता है कि सामान भेजने संबंधी परेशानियां हैं, लेकिन वह भारत को धमकी देने से बाज भी नहीं आता और कहता है कि अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो नेपाल चीन सहित अन्य देशों से संपर्क करेगा. यह तो है एक महीना पहले की बात, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या नेपाल की इच्छा चीन के करीब जाने की है? क्या नेपाल भारत से दूर होना चाहता है? क्या नेपाल और चीन में कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या इसीलिए सप्ताह भर पहले चीन नेपाल के पक्ष में खेमेबाजी कर रहा था? ये सवाल अनायास नहीं हैं, बल्कि उन परिस्थितियों ने इन सवालों को जन्म दिया है, जो नेपाल के हावभाव में पिछले कुछ अर्से से देखने को मिल रहा है. पिछले दिनों चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया था कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन समर्थक हैं. वे चीन के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करना चाहते हैं. नेपाल में नई सरकार बनने के महज पांच दिन बाद इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में नेपाली कांग्रेस की पूर्व सरकार को पारंपरिक तौर पर भारत समर्थक कहा गया है. साथ ही लिखा गया है कि नेपाल के नागरिक भी बीजिंग के साथ नजदीकी संबंध चाहते हैं.

खैर, मामला चाहे जो भी हो, उसे कूटनीति से हल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों देश शांति और संयम से काम लें. लेकिन वर्तमान हालात में कुछ बनता दिख नहीं रहा है. अब चर्चा करते हैं वर्तमान हालात की. नेपाल के बीरगंज में पुलिस फ़ायरिंग में एक भारतीय की मौत और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उस घटना की निंदा के बाद भारत और नेपाल तनाव का सामना कर रहे हैं. मधेशियों के मुद्दे पर भारत ने पहले ही स्पष्ट रूप से अपनी धारणा व्यक्त कर दी है कि अगर संविधान मधेश और अन्य असंतुष्ट पक्ष को लेकर नहीं लाया जाता है तो आगामी दिनों में दो देशों के बीच के सम्बन्धों पर असर पड़ सकता है.

दूसरी तरफ भारत ने मधेशी नेताओं को यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांग जायज है और भारत उनके साथ है. कहीं न कहीं भारत के इसी रुख को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ओली यह तो नहीं कह रहे हैं कि भारत दोनों देशों की सीमा पर मधेसी समर्थित पार्टियों को उकसा रहा है. ओली ने आरोप लगाया कि भारत मधेसी दलों को 1751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल की खुली सीमा पर नाकेबंदी के लिए उकसा रहा है. ओली ने कहा कि आखिर भारत क्यों चार मधेसी दलों के ही पीछे खड़ा नजर आ रहा है? उन्होंने कहा कि यह नेपाल सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के सभी समुदायों की बातों को सुने और उनकी शिकायतों को दूर करे. ओली भारत को लेकर इतना उग्र हो गए कि उन्होंने भारत द्वारा हमेशा से दी जा रही सहायता की तनिक भी परवाह नहीं की और उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने की चेतावनी भी भारत को दे डाली. इसके बाद से दोनों ओर से स्पष्टीकरण और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. एक तरफ जहां भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उन्होंने नेपाल के नेताओं से अपील की है कि समस्या राजनीतिक है और इसे बल से नहीं सुलझाया जा सकता. मोदी ने कहा कि संघर्ष की वजहों पर नेपाल सरकार को विश्वसनीय और प्रभावी तरीक़े से विचार करना चाहिए. वहीं नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मी ढकाल के मुताबिक़, दो भारतीय नागरिकों को पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले नेपाल की पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा के एक अहम नाके से प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए बीरगंज-रक्सौल सीमा चौकी को खोल दिया और नेपाल में एक महीने से फंसे 200 ट्रक भारत आ रहे हैं. नेपाल के तराई इलाक़े के मधेसी प्रदर्शनकारी भारत की सीमा से लगे दो अहम नाकों पर कई हफ़्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रकों की आवाजाही बाधित हुई है. मधेसी समूह सितंबर में अपनाए गए नए संविधान का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह संविधान उनके हितों के ख़िलाफ़ है.

अगर नेपाल भारत से दूरियां बढ़ा रहा है तो नेपाल की स्थिति भारत के लिए चिन्ता का विषय हो सकती है, लेकिन उससे कहीं अधिक नेपाल के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए. कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत का नेपाल पर प्रभाव कम हो रहा है तो स्पष्ट है कि चीन का नेपाल पर प्रभाव बढ़ रहा है. लेकिन नेपाल यह भूल गया है कि चीन से उसकी नजदीकियों से नेपाल की स्थिति चाइनीज समान की तरह हो जाएगी, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती. सवाल यह भी है कि क्या नेपाल का चीनीकरण हो रहा है? सवाल यह भी है कि क्या चीन का पूर्ण समर्थन और भारत की उपेक्षा कर ओली नए नेपाल का निर्माण कर पाएंगे? मामला चाहे जो भी हो, हमें नेपाल से अपने संबंधों का गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

सीरियल किलर रोडने एलकाला

31 सालों से जेल में बंद पेशे से फोटोग्राफर 66 साल का रोडने एलकाला को अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता था. रोडने कम उम्र की लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था. रोडने मॉडल बनाने का लालच देकर लड़कियों को अपने जाल में फसाया करता था और फिर शुरू होता था रोडने का गंदा खेल. ग्लैमर और पैसे की चाह में लड़कियां आसानी से रोडने के जाल में फंस जाती थी. उसके बाद वो मासूम लड़कियों से दुष्कर्म करता था. इतने से उसका मन नहीं भरता, तब वो उन लड़कियों का गला दबाता, जब लड़की बेहोश होने लगती, तो वो उसे छोड़ देता. लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारकर फिर होश में लाता. फिर गला दबा कर वह उन लड़कियों को मौत के घाट उतारता था. जांचकर्ताओं ने बताया कि रोडने को लड़कियों को प्रताड़ित कर मारने में मजा आता था. रोडने ने मॉडल बनाने का लालच देकर करीब 130 लड़कियों और औरतों की हत्या की थी. पुलिस को रोडने के घर से उन लड़कियों की तस्वीरें मिलीं, जो कई साल से लापता थीं. जांचकर्ताओं के मुताबिक, रोडने एक साइको किलर था. रोडने अमेरिका के मशहूर टीवी रियलिटी शो THE BLIND DTE का विनर भी रह चुका है, लेकिन इस गेम शो में जिस लड़की ने रोडने को डेट पर जाने के लिए चुना, उसने बाद में अपनी ये डेट कैंसिल कर दी. उसके मुताबिक, जब उसने रोडने से बात की तो वो बेहद डरावना और अजीब सा लगा.

रोडने के लॉकर से कई लड़कियों की न्यूड तस्वीरें भी बरामद हुईं. उसके शिकारों में स्कूली लड़कियों से लेकर 40 साल तक की महिलाएं शामिल थीं. ये सभी फोटोग्राफ 1977 से 1979 के बीच खींचे गए. रोडने ने कई महिलाओं की तस्वीरें उनकी हत्या करने के बाद खींची. पुलिस के मुताबिक, उसने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लॉस एंजिल्स के औरतों को अपना निशाना बनाया. 1979 से जेल में बंद इस शख्स को 2010 में मौत की सजा सुनाई गई.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

दुनिया का 7वां सबसे मूल्यवान ब्रांड है भारत

दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड वाले देशों की लिस्ट में भारत एक स्थान ऊपर उठते हुए सातवें स्थान पर पहुंच गया. इस लिस्ट में शामिल टॉप-20 देशों में भारत के ब्रांड वैल्यू में सर्वाधिक 2.1 अरब डॉलर यानी 32 फीसदी का इजाफा हुआ है. वैश्विक कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा तैयार किए गए सर्वाधिक मूल्यावान ब्रांड वाले देशों की इस लिस्ट के अनुसार, ब्रिक्स देशों में भारत एकमात्र देश है, जिसके ब्रांड मूल्य में इजाफा हुआ है. ब्रिक्स के अन्य देशों में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका को अपने-अपने पदक्रम में एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. ब्रिक्स देशों में चीन के बाद भारत दूसरा सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाला देश है. इसके बाद ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के नंबर आते हैं. 19.7 अरब डॉलर मूल्य के साथ अमेरिका टॉप पर बरकरार है. चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है. ब्रांड फाइनेंस के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाला देश है. इसका अधिकांश मूल्य देश के अर्थतंत्र से आता है. इसके अलावा सर्वोच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था और सॉफ्टवेयर उद्यम के अलावा मनोरंजन उद्योग का भी इसमें अहम योगदान है. किसी देश का ब्रांड वैल्यू उस देश में अगले पांच वर्षों में सभी ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री के अनुमान के आधार पर तय होता है. देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को कुल राजस्व के प्रतिनिधि के तौर पर लिया जाता है.■

इस देश की आबादी एक भारतीय परिवार से भी कम है

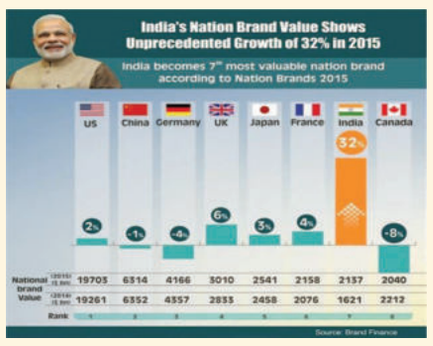

भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में जहां अकेले एक संयुक्त परिवार में ही 50 से अधिक लोग एक छत के नीचे रहते हैं, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां की कुल आबादी को आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी की इंग्लैंड के पास सीलैंड नाम का एक ऐसा देश है, जहां राजा से लेकर प्रजा तक कुल 27 लोग ही रहते हैं.

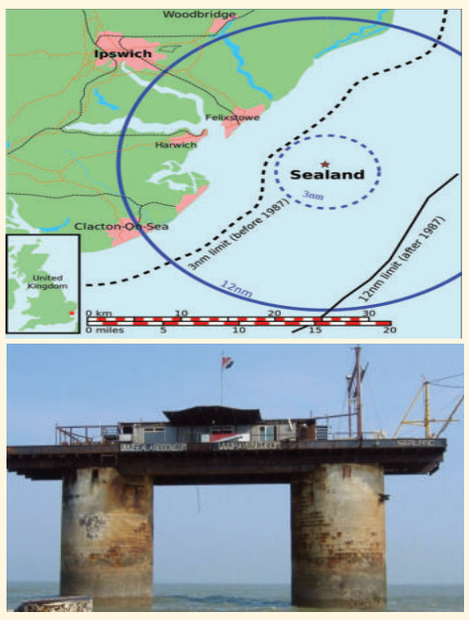

यह छोटा देश इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है. इस देश का नाम सीलैंड है. दरअसल, यह देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए समुद्री किले पर स्थित है, जो अब खंडहर होने की कगार पर है. इस जगह पर अलग-अलग लोगों का कब्जा रहा है, लेकिन साल 2012 में रॉय बेट्स नामक एक व्यक्ति ने खुद को यहां का प्रिंस घोषित कर दिया था. उसके बाद से वंश परंपरा के तहत अब उसका बेटा यहां शासन कर रहा है. इतनी कम आबादी वाले देश को माइक्रो नेशन कहा जाता है. माइक्रो नेशन उन देशों को कहते हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली होती है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

मंकणक को पत्नी का सुझाव पसंद आया और उन्होंने भगवान सदाशिव की आराधना आरंभ कर दी. धीरे-धीरे कालक्रम के अनुसार आराधना की निरंतरता से उनका मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में एकाग्र होने लगा. आखिरकार वैशाख शुक्ल द्वितीया के चंद्रोदय के साथ भगवान शिव मंकणक के सामने प्रकट हुए. उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि वर मांगो वत्स! मंकणक ने उनके सामने पुत्र की कामना प्रकट की और साथ ही अपने लिए धन व यश भी मांगा.

साईं वंदना

सद्गुरु की मानस पूजा

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

गायत्री मंत्र कब, कहां और कैसे करना चाहिए?

गायत्री मंत्र प्रधान मंत्र है, जिसको हर हिंदू को याद रखना चाहिए. यह मंत्र ईश्वर-ध्यान का मंत्र है तथा जगत-कल्याण के लिए ही है. यह मंत्र भी है और प्रार्थना भी. अत: इसका पाठ या जप अत्यंत सहज रूप से किया जा सकता है. सूरज की ओर मुख करके इसका जप या ध्यान करना चाहिए. प्रात: काल में पूरब की ओर तथा सायंकाल में दक्षिण की ओर किसी निर्जन स्थान में या कमरे के कोने में बैठकर गुरु-प्रार्थना के बाद यह मंत्र जपना चाहिए.

क्या गायत्री-मंत्र का जप गुरु से बिना दीक्षा लिए किया जा सकता है?

हां इसमें भी उसका प्रभाव होता है, पर गुरु-दत्त गायत्री का विशेष महत्व होता है.

यदि व्यक्ति परिस्थितियों के कारण कोई रात्रि में ही गायत्री-मंत्र का जप कर पाए, तो क्या उसे रात्रि में गायत्री-मंत्र का जप करना चाहिए?

गायत्री-मंत्र का जप रात्रि की अपेक्षा, सुबह, दोपहर और संध्या को करना अधिक श्रेयस्कर है. मध्य रात्रि में गायत्री काली-शक्ति को आकर्षित करने के लिए है.

साईं बाबा की पूजा करना और गायत्री-माता की मूर्ति के समक्ष गायत्री-मंत्र का जप करना, क्या आध्यात्मिक दृष्टि से उचित है?

मैंने पहले भी कहा है कि बाबा किसी भी रूप में पूजित हैं. शिरडी में बाबा के सामने लोग गायत्री-मंत्र का जप करते थे. बाबा के सामने किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं.

क्या बाबा का भोग लगाने के लिए अलग से कुछ तैयार करना आवश्यक है? भोग के लिए क्या कोई विशेष पदार्थ उचित है?

अपने खाने के लिए घर में जो कुछ भी बने, बाबा को उसी का भोग लगाना चाहिए और लोगों में बांटना चाहिए. शुद्ध भावों से बाबा को जो कुछ भी अर्पित किया जाएगा, वह उन्हें स्वीकार्य होगा. यह कहना कि मांसाहारी भोजन भोग में चढ़ाना उचित नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या यह है कि मुसलमान लोग ईश्वर को भोग स्वरूप जो मांसाहारी भोजन चढ़ाते हैं, वह ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होता? ईसामसीह ने अपने जीवन के अंतिम भोज में निरामिष भोजन ग्रहण किया था. वह तो केवल हमारे भाव हैं, जो बाबा तक पहुंचते हैं.

बाबा की पूजा की विधि

घर में बाबा की पूजा किस विधि से करनी चाहिए?

घर में की जाने वाली बाबा की पूजा और मंदिर में की जाने वाली पूजा में मूलभूत अंतर हैं. घर में रखी मूर्ति अथवा फोटो की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हुई है. अत: किसी भी प्रकार से बाबा का पूजन किया जा सकता है. पूजा-विधि को सरल बनाना आवश्यक है. सभी बाह्य अनुष्ठान, कर्मकाण्ड आदि कृत्रिम हैं. वास्तविक पूजा तो सद्गुरु में अखंड विश्वास रखते हुए थोड़ी-सी विभूति से भावों के द्वारा कहीं भी हो सकती है. यदि हम किसी कार्यवश घर से बाहर हैं, तो वहां भी हम बाबा की पूजा उसी प्रकार कर सकते हैं, जिस प्रकार घर में करते हैं. घर में पूजा के लिए किसी को भी यह कार्य सौंपा जा सकता है. बाबा किसी भी धर्म, जात-पात, ऊंच-नीच जाति, छोटे-बड़े, धनी-निर्धन, आदि के भेद से परे हैं.

वेदों में कहा गया है कि सद्गुरु-रूप नें सभी इष्ट समाहित हैं. अत: सभी इष्टों को छोड़कर भी यदि सद्गुरु की पूजा की जाएगी, तो उसमें कोई दोष नहीं है. सिक्ख भक्तों ने अपने गुरुओं के प्रति सहर्ष अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गुरु अनश्वर हैं और सदा उनके साथ हैं. सद्गुरु के प्रति अगाध विश्वास की स्थिरता परम आवश्यक है.

मानस-पूजा क्या है? क्या हम बाबा की मानस-पूजा कर सकते हैं?

मानस पूजा का वास्तविक अर्थ यह है कि बाबा की मूर्ति के समक्ष बैठकर समस्त पूजा-पद्धति को मानसिक प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करना, जैसा कि हम श्री साईनाथ की मूर्ति के समक्ष करते हैं. उदाहरणार्थ जब हम सामान्य पूजा करते हैं, तब हम बाबा की मूर्ति की ओर देखते हैं, उन्हें नेवैद्य अपर्ति करते हैं और हाथ में दीप लेकर उनकी आरती भी करते हैं. ऐसा करते समय हम उनको एवं आसपास की सभी वस्तुओं को देखते हैं और इन सभी प्रक्रियाओं को चरण दर चरण पूर्ण करते हैं. मानस पूजन में भी ये मानसिक रूप से उन्हीं पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए चरणवार उतने ही समय में पूर्ण करते हैं. भक्त की आंखे बंद होती हैं, वह अपने अंतर्मन में मूर्ति को उसी रूप में देखता है. वह पूजा के प्रत्येक चरण को-जैसे स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, सुसज्जित करना, नैवेद्य अर्पित करना और आरती करना आदि को ऐसे पूर्ण करता है जैसे कि सामान्य पूजा के दौरान किया जाता है. ऐसा करते समय भक्त असली पूजा में लगाए गए समय में कटौती नहीं करता है. प्रारंभ में ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन मानस-पूजा के निरंतर अभ्यास के बाद यह आसान हो जाता है. ऐसी पूजा-पद्धति का लाभ यह है कि यह कभी भी और कहीं भी की जा सकती है. उपयुक्त यह होगा कि यदि कोई घर से बाहर हो तो, ऐसी मानस पूजा सामान्य पूजा की तरह करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

कर्म ही सहायक है

मंकणक की आस्था भगवान सदाशिव में थी. तपस्वी होने के बावजूद उनके मन से संसार व सांसारिकता अभी गई नहीं थी. धन, यश, पुत्र आदि की कामना उनके मन को जब-तब घेर लेती थी. क्या करें? इसी उधेड़बुन में वह उलझे रहते थे. उनकी इस मन:स्थिति को देख एक दिन उनकी धर्मपत्नी स्वयंप्रभा ने उनसे कहा कि आपकी समस्या का समाधान आपके आराध्य आशुतोष अवश्य करेंगे. उन्हीं की कृपा से आपको प्रबोध मिलेगा.

मंकणक को पत्नी का सुझाव पसंद आया और उन्होंने भगवान सदाशिव की आराधना आरंभ कर दी. धीरे-धीरे कालक्रम के अनुसार आराधना की निरंतरता से उनका मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में एकाग्र होने लगा. आखिरकार वैशाख शुक्ल द्वितीया के चंद्रोदय के साथ भगवान शिव मंकणक के सामने प्रकट हुए. उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि वर मांगो वत्स! मंकणक ने उनके सामने पुत्र की कामना प्रकट की और साथ ही अपने लिए धन व यश भी मांगा. इस पर भगवान सदाशिव ने कहा कि वत्स, तुमने तपस्या पूर्ण की है, वर प्राप्त करना तुम्हारा नैसर्गिक अधिकार है. लेकिन तुम्हारे अंत:करण में भक्ति का अंकुर है. बस, इसी कारण मैं पूछना चाहता हूं कि पुत्र किसलिए? पुत्री क्यों नहीं? मंकणक बोले कि प्रभु, आगे चलकर पुत्र सहायक बनता है, जबकि

पुत्री तो विदा होकर ससुराल चली जाती है. यह सुनकर भगवान हंसे और बोले कि वत्स, तुमने शास्त्रों का खुद अध्ययन किया है. तुम्हें यह बोध तो होना ही चाहिए कि सहायक तो मनुष्य के कर्म होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष किसी की सहायता नहीं करता. पुत्र हो या पुत्री, उसे संस्कार व शिक्षा प्रदान कर, उसे समाज को अर्पित करना माता-पिता का दायित्व है. अपने बच्चों से प्रतिदान की आशा तो पशु-पक्षी भी नहीं करते. भगवान सदाशिव की बातों से मंकणक के जीवन को नई दिशा मिल गई. ■

धर्म

बज्रेश्वरी शक्तिपीठ

भक्तों के दुःख हर लेती हैं मां

हिमाचल प्रदेश में कई शक्तिपीठ और प्राचीन मंदिर स्थित हैं. माता के शक्तिपीठों में से तीन शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनके महत्व और चमत्कारों के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है. उनमें से कांगड़ा का बज्रेश्वरी शक्ति पीठ मां का एक ऐसा धाम है, जहां पहुंच कर भक्तों का हर दुख और उनकी तकलीफ मां की एक झलक पाने से दूर हो जाती है. हिमाचल प्रदेश में कागंड़ा नाम के स्थान पर माता का यह शक्ति पीठ है. यहां पर माता शती के वक्ष(स्तन) गिरे थे. यहां माता की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है. बज्रेश्वरी देवी को दशमहाविद्याओं में भी गिना जाता है. माता का यह शक्तिपीठ अनूठा और विशेष है, क्योंकि यहां सभी धर्मों के लोग आकर शीश झूकाते हैं. यहां भैरव की चमत्कारी मूर्ति भी है. भैरव प्रतिमा की यह विशेषता है कि जब भी इस क्षेत्र में कोई भयानक संकट, आपत्ति या रोग संक्रमण आदि की आशंका होती है, तब इस मूर्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है या पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है. आसूं तब तक बहता रहता है, जब तक वह विपत्ति खत्म न हो जाए. इसे देखकर मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर मां से आने वाली आपदा को टालने का निवेदन करते हैं और यह बज्रेश्वरी शक्तिपीठ का चमत्कार और महिमा ही है. आने वाली हर आपदा मां के आशीष से टल जाती है. बज्रेश्वरी देवी के मंदिर में यज्ञ कराने से दस हजार यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है. मंदिर के गर्भगृह में प्रतिख़्ति मुख्य पिंडी मां ब्रजेश्वरी की है. दूसरी मां भद्रकाली और तीसरी और सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी की है. मां के इस शक्तिपीठ में माता के परम भक्त ध्यानु ने माता को अपना शीश अर्पित किया था. इसलिए मां के वो भक्त जो ध्यानु के अनुयायी भी हैं वह पीले रंग के वस्त्र धारण कर मंदिर में आते हैं और मां का दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य मानते हैं. मां बज्रेश्वरी देवी मां की प्रतिदिन पांच बार आरती होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

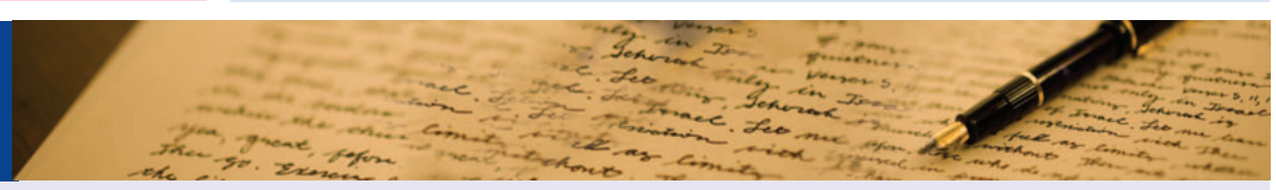

क्या विकास सिर्फ एक प्रलोभन मात्र है!

पटना शहर के चौराहों पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग्स, उन पर छपी आकर्षक तस्वीरें और लुभावने वाक्य विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. देश के अधिकतर राज्यों की हकीकत यही है कि चुनाव में कोई भी पार्टी जीते विकास मात्र वादों तक सिमट कर रह जाता है. देश में गरीबी, बेरोजगारी, आरक्षण, साम्प्रदायिक हिंसा जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को सोचना चाहिए . लेकिन होता ये है कि जो पार्टी विजयश्री हासिल करती है वो पहले अपना घर भरने में लग जाती है, फिर हुक्मरानों का और उसके बाद अगर कुछ बचा तो जनता का नंबर आता है. चुनाव के समय सभी नेता रैलियों के माध्यम से देश को बांटने में जुट जाते हैं. चाहे वो जातिगत आधार हो या आर्थिक आधार पर. वोटबैंक की राजनीति करने में माहिर हमारे देश के कई बड़े चहरे यह नहीं सोचते हैं कि उनकी इसी भद्दी राजनीति के चलते देश का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा.

एक गरीब हर सुबह यह उम्मीद लेकर जागता है कि वह पूरे दिन जी तोड़ मेहनत कर के किसी तरह अपने परिवार का पेट भर लेगा. उसके माथे पर परेशानी की लकीरें ये साफ दर्शाती हैं कि वह आम जरूरतों के पूरा न हो पाने के चलते किस कदर तनाव में है. बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. राजद, जदयू, भाजपा समेत सभी पार्टियों ने जी जान लगा दिया था. कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके लिए राजनीति ही उनका ओढना-बिछौना है. ऐसे में कोई भी साधारण व्यक्ति उनके झांसे में आकर उन्हीं को वोट दे सकता है.

-रत्नाकर पाण्डेय, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगे

इन दिनों इलेक्ट्रानिक मीडिया में मैनफोर्स ब्राण्ड के कंडोम का विज्ञापन छाया हुआ है, जिसे समुद्र तट पर पोर्न स्टार सनी लियोन द्वारा संभोग की बात को बहुत बेहुदगी के साथ कहलाव कर दर्शकों को अधिकाधिक उत्तेजित करने का प्रयास किया गया है. ऐसे विज्ञापनों से ही औरतों के प्रति होने वाले कदाचार बढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं वही करना चाहते हैं. इसीलिए बच्चों के लिए अश्लील और हिंसक फिल्में देखना वर्जित है. यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता रहीं सुषमा स्वराज ने ऐसे विज्ञापनों का घोर विरोध किया था. लेकिन जब उनकी सरकार है, तो वह चुप हैं. दुष्कर्म की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, जिसमें स्त्री सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु(सेक्स सिंबल) बनाकर पेश की जाती है, जिससे कि वह अधिक से अधिक पुरुष ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके.

-सत्य प्रकाश शिक्षक,
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

लोकप्रिय समाचार-पत्र चौथी दुनिया

इधर कुछ दिनों से बड़े ही बेबाक ढंग से आपके कुछ लेख देश के प्रमुख सवालों पर चैलेंजिंग और विश्वसनीय तरीके से आ रहे हैं. (अगर यह गलत है, तो मुझे बताएं सही क्या है.) आदि. 28 सितंबर-04 अक्टूबर के अंक में-'सबको शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए' आलेख पढ़ा. आपने गांवों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के तरीके पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है. मैं भी चाहता हूं कि सबको शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए.

-सुदर्शन पाठक, बक्सर, बिहार.

चुनावी चक्रम

वोट, इलेक्शन, चुनाव, मतदान
देख देख जनता होती हैरान
पार्टी, दल, कैंडिडेट, अभ्यर्थी
निकालते जनमत की अर्थी
वादे-इरादे, नारे, घोषणा पत्र
जैसे कुड़ा-कर्कट, गंदगी सर्वत्र
दलबदल, गठबंधन, तालमेल
कुर्सी के वास्ते कड़वा घालमेल
जात-पात, ऊंच-नीच, ध्रुवीकरण
जनमत का चुनावी चीरहरण
नारे, रैली, भाषण, बयान
चुभते विषैले तीरों समान
आचार संहिता, आयोग का डंडा
सरकारी कवायद का बेजान फंडा
गिनती, काउंटिंग, रिजल्ट, परिणाम
धन्यवाद, थैंक्यू, आदाब, प्रणाम

-ए.जब्बार अंसारी, दरभंगा, बिहार.

सराहनीय संपादकीय

जब तोप मुकाबिल हो-(02 नवंबर-08 नवंबर, 2015) पढ़ा. क़ादर ख़ान, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव. बेहद प्रभावित किया. बाबा रामदेव के पंतजलि योगपीठ में जाने-माने कलाकार का इलाज हुआ है और वह पहले से ठीक भी हो गए हैं सुनकर काफी खुशी हुई. फिल्म होगया दिमाग का दही मैंने देखा. यह फिल्म एक साफ सुथरी कॉमेडी है. इस फिल्म में क़ादर ख़ान का छोटा रोल है, लेकिन उन्होंने अपने रोल से दिल जीत लिया. क़ादर ख़ान को दस साल बाद एक बार फिर फिल्म में देखकर बहुत खुशी हुई है. संतोष भारतीय का यह सराहनीय कदम है कि उन्होंने क़ादर ख़ान, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर संपादकीय लिखा है.

– जगदीश शर्मा, पालम, दिल्ली

लेखक संगठनों की शतरंजी बिसात

अनंत विजय

देश में पुरस्कार वापसी के माहौल में अचानक से लेखक संगठनों की सक्रियता चौकाने वाली है. साहित्य अकादमी के खिलाफ प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच के साझा बैनर के तले दिल्ली में चंद लेखकों ने मौन जुलूस निकालते हुए क्रांति का बिगुल फूंका था. लगभग सुसुप्तावस्था में पड़े इन लेखक संगठनों ने जिस तरह से आनन–फानन में विरोध किया उसके बाद उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. साहित्य जगत में मौजूद ये तीन लेखक संगठन दरअसल अपनी–अपनी राजनीतिक पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं. लिहाजा जिस तरह से राजनीतिक दलों के बौद्धिक प्रकोष्ठ काम करते हैं उसी तरह से ये भी ऑपरेट करते हैं. जैसे–जैसे इन राजनीतिक दलों में विभाजन होता गया लेखक संगठन भी बंटते चले गए. प्रगतिशील लेखक संघ सीपीआई का बौद्धिक प्रकोष्ठ है. इसी तरह से सीपीएम का जनवादी लेखक संघ और सीपीआई माले का जन संस्कृति मंच. लेखकों के नाम पर बने इन पार्टियों के बौद्धिक संगठनों ने लेखकों का कुछ भला किया हो या लेखकों की बेहतरी के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, याद नहीं पड़ता. ये अपने हर कदम के लिए पहले अजय भवन आदि की ओर देखते हैं और वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ा पाते हैं. समाज में बढ़ रही असहिष्णुता और लेखकों पर कथित सुनियोजित हमलों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले इन लेखक संगठनों को कभी भी कॉपीराइट औप रॉयल्टी जैसे अहम मसलों पर विमर्श करते हुए नहीं देखा गया है. हिंदी में तो कम से कम से कम रॉयल्टी एक अहम मुद्दा है. बहुधा लेखकों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि उनको प्रकाशकों से उचित रॉयल्टी नहीं मिलती है. लेखकों को लगता है कि प्रकाशक उनका हक मारकर मोटा मुनाफा कमाते हैं. यह बात भी बार–बार कही जाती है कि हिंदी के लेखक गरीब होते जा रहे हैं जबकि प्रकाशक लगातार अमीर होते जा रहे हैं. हिंदी के इस सबसे अहम मुद्दे पर इन तीनों लेखक संगठनों ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया. कभी कोई मौन जुलूस लेकर किसी प्रकाशक के दफ्तर पर प्रदर्शन नहीं किया. धरना प्रदर्शन आदि की बात छोड़ भी दें तो क्या इन लेखक संगठनों की तरफ से इस बारे में कोई पहल की गई? इसका जवाब अबतक तो नहीं है. उस वक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाकर सुर्खियों में आए मंगलेश डबराल ने कहा था–लेखक संगठन लेखकों के यूनियन नहीं हैं जो कॉपीराइट आदि के मुद्दों पर संघर्ष करें. ये तो वैचारिक संगठन हैं जिनका काम साहित्य की दुनिया में वैचारिक संवेदना का प्रचार करना है. यह जानना भी दिलचस्प होगा कि किस तरह की वैचारिक संवेदना को फैलाने का काम इन लेखक संगठनों ने किया. इसके अलावा इन लेखक संगठनों ने लेखकों की मदद के लिए कभी कोई पहल की, इस बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. हिंदी के कई

फोटो–*सुनील मल्होत्रा*

लेखक मुफलिसी में जिंदगी काटकर गुजर गए, कई गंभीर बीमारी और आर्थिक संकट की वजह से अपना समुचित इलाज नहीं करवा पाने की वजह से चल बसे लेकिन इन लेखक संगठनों ने उनकी कोई सुध नहीं ली. कई लेखक तो ऐसे थे जो कि इन संगठनों में बेहद सक्रिय थे लेकिन जब वो बीमार पड़े या फिर उनके सामने आर्थिक संकट आया तो लेखक संगठनों ने उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका. आज कन्नड़ के लेखक कालबुर्गी की हत्या पर साहित्य अकादमी के शोक नहीं मनाने, जो कि तथ्यहीन है, को लेकर सड़कों पर उतरे साहित्यकारों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हिंदी के वरिष्ठ लेखक अरुण प्रकाश की मौत के बाद लेखक संगठन कितने निष्क्रिय रहे थे. अरुण प्रकाश दिल्ली का निधन दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हुआ था. लेखक संगठनों से जुड़े तमाम वरिष्ठ साहित्यकार उनके फ्लैट के आधे एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं लेकिन कोई उनके घर शोक व्यक्त करने तक नहीं पहुंचा था. उनके अंतिम संस्कार में भी गिने चुने साहित्यकार थे. इस तरह की संवेदनहीनता के दर्जनों उदाहरण इन लेखक संगठनों के सर पर कलगी की तरह लगे हैं. दुखद ये कि इन लेखक संगठनों को अपनी इस संवेदनहीनता पर शर्मिंदगी भी नहीं है. इसके अलावा साहित्य अकादमी में सालों से चली आ रही गड़बड़ियों को लेकर भी लेखक संगठनों ने कभी कोई आवाज वहीं उठाई, क्योंकि इन लेखक संगठनों से जुड़े लेखकों को वहां से फायदा मिल रहा था. वो पुरस्कृत हो रहे थे, साहित्यक विदेश यात्राएं कर रहे थे. देश भर में सेमिनार आदि के नाम पर घूमना–फिरना हो रहा था. उन्नीस सौ पचहत्तर के बाद साहित्य अकादमी का इतिहास घोटालों और घपलों का रहा है. उसपर किसी तरह का स्पंदन उस वक्त साहित्य जगत में नहीं दिखा. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष गोपीचंद नारंग पर कई तरह के संगीन इल्जाम लगे थे लेकिन पंकज बिष्ट के अलावा किसी लेखक ने आवाज उठाई हो याद नहीं पड़ता, लेखक संगठन की बात तो दूर. इसी तरह से साहित्य अकादमी के सचिव को घपलों के आरोप में सस्पेंड किया गया था. उनके खिलाफ जांच बैठी थी. इस बीच उनको रिटायर कर दिया गया. उनके घपलों की जांच रिपोर्ट के नतीजे क्या आए, ये जानने की कोशिश किसी लेखक संगठन ने की या नहीं इसको देखने की आवश्यकता है. साहित्य जगत में इस बात की चर्चा लगातार रही कि उक्त सचिव ने कई वामपंथी लेखकों को उपकृत किया था लिहाजा उन सभी का अकादमी पर दबाव था कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए. वही हुआ. विश्वनाथ तिवारी उन घपलों की जांच कर रहे थे लेकिन नतीजा क्या रहा पता नहीं चल पाया. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में घुमा–फिरा कर टाल दिया गया.

अब जरा इन लेखक संगठनों के क्रियाकलापों पर नजर डालते हैं. इन लेखक संगठनों में विश्वविद्लाय के शिक्षकों के दबदबे पर राजेन्द्र यादव ने कहा था–साहित्यकारों में ज्यादातर प्राध्यापक हैं, क्या ईमानदारी से इनमें से कोई वो काम करता है जिसके लिए उनको वेतन मिलता है? ये लोग न तो अपने पाठ्यक्रम के साथ न्याय करते हैं न अपने छात्रों के साथ. साहित्य में उतरकर उनका लगभग यही उठाईगीर रवैया हम सबके सामने है. पुराने कवियों–लेखकों को छोड़कर न इनमें से किसी ने भी कोई ऐसी पुस्तक लिखी है जो वैचारिक रूप से आंदोलित करे या देश–विदेश के विचारों के परीक्षण का जोखिम उठाए. आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र की तरह सब बाहर से माल लाकर अपना ठप्पा ठोंक देते हैं. कभी–कभी मैं सोचता हूं कि हिंदी में कबीर, तुलसी और निराला न होते तो इन बेचारों की जिंदगी क्या होती? अपनी विद्वता कहां झाड़ते. समीक्षक वीरेन्द्र यादव ने भी माना था –लेखक संगठनों की निष्क्रियता के मूल में वामपंथी राजनीति की पस्त हिम्मती, सुविधा जीविता और परिपेक्ष्यविहीनता है, वहीं लेखकों के बीच पद, प्रतिष्ठा व पुरस्कार आदि को लेकर लोलुपता बढ़ी है. वैचारिक उदारतावाद का स्थान नग्न अवसरवाद ले रहा है. इन्हीं दुर्गुणों को प्रगतिशील लेखक संघ में लक्ष्य करके जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच का गठन हुआ था, लेकिन ये संगठन भी कमोबेश आज के प्रगतिशील लेखक संघ की तरह झंडा–बैनर अधिक रह गए, सक्रिय लेखक संगठन कम (कोलाहल कलह में–पृ 60). यहां वीरेन्द्र यादव, मंगलेश से इतर विचार रखते हैं जब वो कहते हैं कि लेखक संगठनों को कॉपीराइट आदि के मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. लेखक संगठनों को लेकर इनसे वैचारिक और सांगठनिक रूप से जुड़े लेखकों के बीच जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति है और यह कंफ्यूजन इनकी निष्क्रियता की वजह है.

अब जरा हम इन लेखक संगठनों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता की परख करते हैं. इन लेखक संगठनों का सालाना या द्वैवार्षिक अधिवेशन होता है. उन अधिवेशनों में क्या–क्या प्रस्ताव आदि पारित होते हैं उसका कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड कहीं मिलता नहीं है. इन लेखक संगठनों से जुड़े मठाधीशों ने अपने कितने चेले चपाटों की किताबें छपवाकर उनको प्रोफेसर बनवा दिया लेकिन अपने संगठन के क्रियाकलापों के दस्तावेज छपवाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है. हो सकता है कि उन अधिवेशनों में जो होता हो उसका रिकॉर्ड रखना संगठन के हित मे ना हो लिहाजा उसको संभालने की उचित व्यवस्था नहीं की गई. अधिवेशनों में पारित प्रस्ताव अगर मौजूद होते तो उसको कसौटी पर कस कर काल और परिस्थिति के मुताबिक इन संगठनों का मूल्यांकन हो सकता था. जो हो नहीं पा रहा है. क्या ये माना जाए कि जानबूझकर इन संगठनों के क्रियाकलापों के सबूत को छिपाकर रखा गया है ताकि उनका मूल्यांकन ना हो सके. निर्मल वर्मा ने कम्युनिस्टों के बारे में कहा था– उनका लगाव और प्रेम अपने सिवा किसी और से नहीं है. उनके शतरंजी खेल में कोई भी वर्ग, चाहे वो कितना भी उत्पीड़ित क्यों ना हो, उनके लिए बाजी जीतने की मुहर से अधिक महत्व नहीं रखता. साहित्य अकादमी के बाहर इकट्ठे लेखक संगठन के लोगों को देखकर यही सवाल मन में कौंधा था कि इस बार शतरंजी खेल में असहिष्णुता के मोहरे का इस्तेमाल हो रहा है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

नवल पुरुष की धवल कविताएं

महेंद्र अवधेश

कविता की कोई शास्त्रीय अथवा तयशुदा परिभाषा नहीं होती. वह हर पंक्ति एक कविता है, जो तरीक़े से आम आदमी के दु:ख–दर्द की बात करती है, घर–आंगन की बात करती है, समाज की बात करती है और देश–दुनिया के प्रति अपनी चिंता ज़ाहिर करती है. हालिया प्रकाशित प्रतीक्षा का रंग सांवला अशोक कुमार पांडेय का तीसरा काव्य संग्रह है, जिसमें नारी केंद्रित कविताएं हैं. इससे पहले उनके दो काव्य संग्रह–लगभग अनामंत्रित एवं प्रलय में लय जितना प्रकाशित हो चुके हैं. अशोक की कविताएं भी घर–परिवार, समाज के साथ–साथ देश–दुनिया की बात करती हैं. एक ज़िम्मेदार पुत्र, एक ज़िम्मेदार पति, एक ज़िम्मेदार पिता, एक ज़िम्मेदार इंसान एवं एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से वह अपनी कविताओं के ज़रिये कई तस्वीरें खींचते हैं, सवाल उठाते हैं, वजह बताते हैं और समाधान भी प्रस्तुत करते हैं.

काव्य संग्रह–प्रतीक्षा का रंग सांवला अड़तीस कविताओं का वह गुलदस्ता है, जिसमें जीवन के कई रंगों से साक्षात्कार होता है. अशोक की कविताएं बताती हैं कि एक कवि, एक रचनाकार, एक लेखक यानी एक संवेदनशील व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं, उसे अपने आसपास मौजूद वस्तुओं, स्थितियों एवं दृश्यों को किस तरह देखना–समझना चाहिए. न सिर्फ़ इतना, बल्कि उसके प्रति जनसामान्य, समाज एवं देश को सचेत कैसे करना चाहिए. हमारी आदि पुरातन सभ्यता–संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो हाथ हमेशा से घर–समाज को बनाते, सजाते एवं संवारते आए हैं, हम जाने–अनजाने अक्सर उन्हें बिसार देते हैं. लेकिन, अशोक के अंदर बैठा कवि समाज की यह मनमर्जी स्वीकार नहीं करता, वह घर–समाज की तरक्की–खुशहाली में महिलाओं के योगदान पर रोशनी डालते हुए कहता है:–

घर के सबसे उपेक्षित कोने में
बरसों पुराना जंग खाया बक्सा है एक
जिसमें तमाम इतिहास बन चुकी चीजों के साथ
मथढक्की की साड़ी के नीचे
पैंतीस सालों से दबा पड़ा है
मां की डिग्रियों का पुलिंदा. (मां की डिग्रियां)

व्यक्ति के जीवन में जो पहली औरत आती है, उसे पूरी दुनिया में मां के नाम से जाना जाता है. मां के त्याग की बात हो, जगन की अम्मा की याद हो, पत्नी के हक़–सम्मान का सवाल हो या फिर इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल का मामला, अशोक के शब्द कहीं भी रत्ती भर कोताही नहीं करते. बेटी द्वारा चिप्स के लिए जिद करने के बहाने वह हमें अपनी ज़मीन से जोड़ते हैं और ले जाते हैं भार और जगन की अम्मा के पास, जो बचपन में बच्चों की डलिया में मुस्कान भरने का काम करती थीं. आज भले ही कारखानों एवं चिप्स ने भार एवं भूजे का स्थान ले लिया हो, लेकिन वे उनके जैसा आकर्षण–स्वाद खुद में पैदा नहीं कर पाए. देखिए एक बानगी:–

मुट्ठियां भर–भर के फांकते हुए
हमने खेले बचपन के तमाम खेल
ऊंघती आंखों से हल किए गणित के प्रमेय
एक डलिया में बांटकर खाते बने हमारे पहले दोस्त
यही खाते–खाते पहले पहल पढ़े
डिब्बा बंद खाने और शीतल पेयों के विज्ञापन.

****

पता ही नहीं चला कब बदल गई
बांस की डलिया प्लास्टिक की प्लेटों में
और रस–भूजा चाय–नमकीन में
अब कहां होंगी जगन की अम्मा?
बुझे चूल्हे की कब्र पर तो
कबके बन गए मकान
और उस कस्बे में अब तक
नहीं खुली चिप्स की फैक्ट्री. (कहां होंगी जगन की अम्मा)

समीक्ष्य कृति : प्रतीक्षा का रंग सांवला (काव्य संग्रह)
रचनाकार : अशोक कुमार पांडेय
प्रकाशन : शब्दारंभ, नई दिल्ली
मूल्य : 150 रुपये

काव्य संग्रह की भूमिका में अनामिका जी सही कहती हैं, अशोक एक नवल पुरुष हैं, स्त्रीवाद के दूध में नहाए हुए. नव गति, नव लय, ताल–छंद नव दुनिया में भर देने का महास्वप्न इन्होंने घुट्टी में पिया है. जीवन संगिनी के साथ संवाद करते हुए अशोक ने इसे साबित भी किया.

चूड़ियों की जंजीर में
नहीं जकड़ना चाहता
तुम्हारी कलाइयों की लय
न मंगलसूत्र बन
झुका देना चाहता हूं
तुम्हारी उन्नत ग्रीवा
जिसका एक सिरा बंधा ही रहे
घर के खूंटे से.

****

बस आंखों में बीजना
चाहता हूं विश्वास
और दाखिल हो जाना चाहता हूं
खामोशी से तुम्हारी दुनिया में
जैसे आंखों में दाखिल
हो जाती है नींद. (तुम्हारी दुनिया में इस तरह)

अशोक की एक और कविता की चर्चा यहां ज़रूरी है, जो उस औरत से जुड़ी है, जो अन्याय के ख़िलाफ़ एक दशक से भी ज़्यादा समय से संघर्ष कर रही है और देश–दुनिया उसे इरोम शर्मिला के नाम से जानती है:–

कोई नहीं रह सकता भूखा बारह साल तक
पक्के तौर अफ़वाह है यह कि
एक औरत बारह साल से भूखी है
ऐसे में यह ज़्यादा विश्वसनीय है कि
वह औरत मर चुकी है कोई
ग्यारह साल और तीन सौ दिन पहले. (एक राष्ट्रभक्त का बयान)

जैसा कि मैंने पहले कहा, कविता की कोई शास्त्रीय अथवा तयशुदा परिभाषा नहीं होती, जीवन का हर रंग छ्द में एक कविता है. इस लिहाज़ से प्रतीक्षा का रंग सांवला न केवल पठनीय है, बल्कि इसने छ्द में वे संदेश छिपा रखे हैं, जिनकी हमें, आपको और सबको बहुत ज़रूरत है.■

mahendra.awdhesh@gmail.com

साफ–सुथरे आंवले लेकर पानी में तीन दिन भीगने दें, इसके बाद उन्हें पानी से निकालकर कांटों से गोद लें और चूना पानी में घोलकर उसमें आंवले को तीन दिन तक भीगने दें. चौथे दिन साफ पानी से धोकर मिश्री तथा पानी में उन्हें भाप दें. फिर कपड़े पर फैलाकर सुखा लें. अब चाशनी बनाकर उसमें आंवले छोड़ दें और पकाएं. जब आंवले अच्छी तरह गल जाएं तब उसमें काली मिर्च, केसर और इलायची मिला दें. बाद में ठंडा करके जार में भरकर रख दें. तैयार आंवले का मुरब्बा दिलोदिमाग को ताकत देने के साथ–साथ सेहत के हिसाब से अत्यंत गुणकारी है.

सैर–सपाटा

सुकून चाहिए तो पूवार आइए

पूवार केरल के तट पर तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है. इस गांव के पास एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, जो अत्यंत ही खूबसूरत है. इसके समुद्री तट पर जाने पर आप एक अलग तरह की शांति का अनुभव करेंगे, जो शहर के जीवन की सामान्य हलचल दूर का एहसास करती है और पर्यटकों की नीरसता को दूर कर उनके दिलोदिमाग में ताजगी भर देती है. अपने छोटे आकार के कारण यहां के निवासियों की संख्या कम है. इसके अलावा मन बहलाने और एकांत के लिए पूवार में यह सबसे शानदार जगह है. पूवार के सूर्यास्त, सूर्योदय और मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक परिवेश एक शानदार अनुभव देते हैं. अगर आप पूवार के बीचों पर बैठे हैं तो धूप को चूमती हुई सुनहरी रेत, दोनों तरफ हरे–भरे नारियल के ताड़ आपके लिए एक जादुई और यादगार अनुभव बनाते हैं. यहां के हाउस बोट और बीच पर्यटकों में काफी प्रचलित हैं. पूवार में एक खाड़ी और नैय्यर नदी भी है, जो समुद्र में मिलती है. यह गांव लकड़ी, मसाले, हाथीदांत, और चंदन का एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र रहा है.

कब जाएं

पूवार जाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है.

कैसे जाएं

केरल के तिरुवनंतपुरम से सड़क या रेल मार्ग द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है. ■

करियर

राइटिंग फील्ड में हैं आगे बढ़ने के अवसर

अगर आपके अंदर छुपा है राइटर और आप लिखने के शौकीन हैं तो आपके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है. वेब कंटेंट राइटर, रेज्यूमे राइटिंग, होस्ट राइटर आदि के क्षेत्र में लिखने में प्रतिभाशाली लोगों की खूब डिमांड है. आपके लिए हैं ये हैं ऑप्शंस:

वेब कंटेंट राइटर :

प्रिंट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में लिखना टफ माना जाता है. वेब पेज आकर्षक न हो, तो रीडर उसे पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते हैं. वैसे भी कम्प्यूटर स्क्रीन की तुलना में प्रिंट पेज पर पढ़ना ज्यादा आसान होता है. इसलिए वेब राइटर की लेखनी सरल, होनी चाहिए. बेव राइटर के रूप में आप वेब साइट्स कंपनियों में जॉब कर सकते हैं.

रेज्यूमे राइटिंग:

जब आप जॉब की तलाश में हैं, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि रेज्यूमे आकर्षक होना चाहिए. कंपनी भी रेज्यूमे को कैंडिडेट्स का पहला इम्प्रेशन मानती है. रेज्यूमे जानदार हो, तो नौकरी मिलने में आसानी होती है. कई बार कैंडिडेट रेज्यूमे की वजह से भी नौकरी पाने में असफल रहते हैं, लेकिन आपके रेज्यूमे को मार्केट के अनुकूल बनाने में रेज्यूमे राइटर माहिर होते हैं. रेज्यूमे राइटर के रूप में आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जैसे–नौकरी डॉट कॉम, मोनस्टर डॉट कॉम आदि में जॉब की तलाश कर सकते हैं.

होस्ट राइटर:

कई बार आपको यह सोचकर आश्चर्य होता होगा कि फेमस पर्सनैल्टी अपनी ऑटोबायोग्राफी को कैसे अच्छी तरह कागजों पर उकेर देते हैं, जबकि इनमें से सभी अच्छे राइटर भी नहीं होते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वे पेन लेकर लिखने बैठें. इस तरह के लोग होस्ट राइटर को हायर करते हैं, जो उनके विचारों के आधार पर किताब तैयार करते हैं. इसके बदले उन्हें अच्छा अमाउंट पेड किया जाता है. दरअसल, होस्ट राइटर को किताब लिखने का क्रेडिट नहीं मिलता है. फिर भी होस्ट राइटर को आज स्टोरी राइटिंग, किताब, मेमोरी, ऑटोबायोग्राफी आदि को लिखने के लिए हायर किया जाता है.

प्रिंट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में लिखना टफ माना जाता है. वेब पेज आकर्षक न हो, तो रीडर उसे पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते हैं. वैसे भी कम्प्यूटर स्क्रीन की तुलना में प्रिंट पेज पर पढ़ना ज्यादा आसान होता है. इसलिए वेब राइटर की लेखनी सरल होनी चाहिए.

योग्यता:

राइटिंग जॉब के लिए मास कम्युनिकेशन की डिग्री रखने वाले प्रोफेशनल्स को अधिक तरजीह दी जाती है. साथ ही अंग्रेजी विषय पर अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए. टेक्निकल राइटिंग के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा कम्प्यूटर की नॉलेज बेहद जरूरी है. ■

फेसबुक पर ऑटो प्ले वीडियो से ऐसे पाएं छुटकारा

श्याम सुन्दर प्रसाद
Smart7973@gmail.com

आजकल ज्यादातर इंटरनेट यूजर फेसबुक प्रयोग करते हैं, पर अभी हाल में फेसबुक ने एक नया फीचर जोड़ा है वीडियो ऑटो प्ले. इसके तहत अगर कोई वीडियो फेसबुक पर शेयर किया गया हो और आप कंप्यूटर और मोबाइल पर अपने टाइमलाइन चेक करते हैं तो जैसे ही वो वीडियो सामने आएगा, अपने आप प्ले हो जाता है. यह फीचर पब्लिशर्स और एडवटाइजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनका वीडियो या विज्ञापन उपयोगकर्ता को न चाहते हुए भी देखना पड़ता है, पर जिन यूजर्स का इंटरनेट डाटा का बजट कम होता है. यह उनका बजट बिगाड़ सकता है. अगर आप भी ऑटो प्ले वीडियो से परेशान हैं तो आप अपने फेसबुक सेटिंग में कुछ बदलाव करके इससे निजात पा सकते हैं.

लैपटॉप एंव डेस्कटॉप उपयोगकर्ता फेसबुक के अपने अकाउंट में लॉग–इन करें. फिर मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें.यहां बायीं तरफ में सबसे निचे वीडियोज ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक करते ही वीडियो सेंटिग पेज आपके सामने दिखेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा. पहला ऑप्शन वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी मिलेगा. इस ऑप्शन से आप वीडियो क्वालिटी सेट कर सकते हैं. वहीं दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑटो प्ले वीडियो का. आप इसके सामने बने बटन पर क्लिक कीजिये, यहाँ आपको डिफाल्ट, ऑन और ऑफ तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे. अगर आप फेसबुक ऑटो प्ले वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो ऑफ को सेलेक्ट करें. इसके बाद वॉल पर वीडियो ऑटो प्ले नहीं होगा और आपको अनचाहे वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा.

अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो फेसबुक ऐप में लॉग–इन कीजिये और सेटिंग्स में जाकर हेल्प एंड सेटिंग्स सेक्शन में जायें और ऐप सेटिंग्स पर टैप करें, जहां आपको वीडियो ऑटो प्ले का ऑप्शन मिलेगा उस पर टैप करें. वहां आपको तीन और ऑप्शंस मिलेंगे. पहला ऑन, दूसरा वाई–फाई ओनली और तीसरा ऑफ का. अगर आप फेसबुक ऑटो प्ले वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो ऑफ को सेलेक्ट करें. अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो मोबाइल डेटा से नहीं, लेकिन जब आप वाई–फाई नेटवर्क पर हों तब प्ले हो तो आप वाई–फाई ओनली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.

फेसबुक के ईमेल नोटिफिकेशन को कैसे बंद करें ?

फेसबुक अकाउन्ट बनाने के लिये यूजर्स या तो एक फ़ोन नंबर या एक ईमेल आईडी का प्रयोग करते हैं और फेसबुक उसी दिए हुए ईमेल पर यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजता है. इसमें यूजर को जन्मदिन की शुभकामनाओं की नोटिफिकेशन से लेकर, ऐप्स इन्वाइट, इवेंट इन्वाइट के साथ–साथ यदि आपको किसी फ्रेंड ने टैग किया या आपके फोटो पर किसी ने कमेंट किया या फोटो लाइक किया हो तो उसके भी नोटिफिकेशन फेसबुक द्वारा भेजे जाते हैं. अगर आप इतने सारे ईमेल नोटिफिकेशंस से परेशान हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से बंद कर इन ईमेल्स से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगइन कर मेन्यू ऑप्शन में जाएं. उसके बाद फिर सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन्स पर क्लिक करें. क्लिक नोटिफिकेशंस सेंटिंग्स पेज पर दिखेंगे, जिसमें कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सुविधा के अनुसार फेसबुक से जुड़े सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस को बंद और चालू कर सकते हैं. ईमेल नोटिफिकेशन बंद करने लिये ईमेल नोटिफिकेशन के सामने दिये गये एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां ऑल नोटिफिकेशंस, एक्सेप्ट द ओन्स यू अन सब्सक्राइब फ्रॉम ऑप्शन से टिक हटा कर ओनली नोटिफिकेशंस अबाउट योर अकाउंट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर लगा दें. इससे आपको केवल आपके फेसबुक अकाउंट की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में ही ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे. इसी तरह आप मोबाइल और टेक्स्ट नोटिफिकेशंस को भी अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं. ■

खाना पीना

गुणों की खान आंवला

स्वाद में लाजवाब और औषधीय गुणों से भरपूर है आंवले का मुरब्बा. इस फल का गुण कम नहीं होता. चाहे आंवला कच्चा हो या पका या धूप में सूखा हुआ. इसका मुरब्बा खाना सबको पसंद है. वैसे तो लोग इसको मीठा खाने की चाहत मिटाने के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इसके कितने फायदे हैं. आंवला का मुरब्बा बिटामिन सी, आयरन और फाइबर का सबसे अच्छा स्त्रोत होता है. साथ ही इसमें कैल्सियम, विटामिन ए और मैग्निशियम होता है, जो इसे और भी हेल्दी बनाता है. इसके नियमित सेवन से बहुत सारी समस्याओं से राहत मिलती है. आइए जानते हैं आंवला का मुरब्बा बनाने की विधि–

सामग्री

1 किलो आंवला, 10 ग्राम चूना, 25 ग्राम मिश्री, सवा किलो शक्कर, 1 चम्मच काली मिर्च, केसर के कुछ लच्छे, इलायची पावडर.

विधि :

साफ–सुथरे आंवले लेकर पानी में तीन दिन भीगने दें. इसके बाद उन्हें पानी से निकालकर कांटों से गोद लें और चूना पानी में घोलकर उसमें आंवले को तीन दिन तक भीगने दें. चौथे दिन साफ पानी से धोकर मिश्री तथा पानी में उन्हें भाप दें. फिर कपड़े पर फैलाकर सुखा लें. अब चाशनी बनाकर उसमें आंवले छोड़ दें और पकाएं. जब आंवले अच्छी तरह गल जाएं, तब उसमें काली मिर्च, केसर और इलायची मिला दें. बाद में ठंडा करके जार में भरकर रख दें. तैयार आंवले का मुरब्बा दिलोदिमाग को ताकत देने के साथ–साथ सेहत के हिसाब से अत्यंत गुणकारी है. ■

राइनोप्लास्टी सर्जरी से दे नाक को सुदर शेप

क्या आपकी नाक बहुत लंबी या छोटी है या बाक़ी चेहरे के मुताबिक़ उपयुक्त नहीं दिखती? तो घबराइएं नहीं, उसे ठीक करने का एक रास्ता दिखाता है राइनोप्लास्टी सर्जरी, जो नोज जॉब सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है. यह एक बहुत लोकप्रिय विधि है. इस सर्जरी में नाक से संबंधित हर परेशानियों का इलाज संभव है और भारत में यह सर्जरी प्रचलित भी अत्यधिक तेजी से हो रही है. आइए जानते हैं क्या है राइनोप्लास्टी (नोज जाब सर्जरी).....

राइनोप्लास्टी सर्जरी में नाक को सुंदर बनाने के लिए नाक के बाहर चीरा लगाने के साथ ही अंदर की ओर नाक और नासिका छिद्र के बीच में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है. फिर अन्य चीरों को मिलाकर नाक के अंदर छिपा दिया जाता है. सर्जरी के बाद आपको कुछ समय तक नाक की खपच्ची या पट्टी पहनने को कहा जा सकता है, ताकि आपकी नाक को सहारा मिल सके. यह खपच्ची सोने के समय आपकी नाक को सुरक्षा प्रदान करेगी और अचानक लगने वाले झटकों से भी बचाव करेगी. हालांकि सर्जरी के बाद आपका चेहरा सूज सकता है. नाक और आंखों के आसपास थकान और सूजन आ सकती है. इस सर्जरी में 3 हफ़्ते तक आपको अपनी सामान्य गतिविधियां सीमित करनी पड़ेंगी. फिर आप अपनी दिनचर्या सामान्य कर सकते हैं. इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक के सचिव डॉ अनुप धीर का कहना है कि राइनोप्लास्टी केवल उसी स्थिति में करनी चाहिए, जब नाक की वृद्धि पूरी हो जाए और वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाए. आमतौर पर ऐसा 16 या 17 साल की उम्र तक हो जाता है. अगर नाक के विकसित होने से पहले राइनोप्लास्टी कराई जाती है तो आगे उसके विकास होने से सर्जरी के नतीजों में बदलाव आ सकता है और इससे जटिलताएं पैदा होने की आशंका रहती है. कुशल सर्जन के हाथों नाक की सर्जरी होने से नतीजे संतोषजनक आते हैं. ■

जो परिणाम हम चाहते हैं वे हमें जल्दी मिलने लगेंगे. सभी चीजों के सही रास्ते में आने में अभी वक्त लगेगा. सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केवल अभी नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से. अधिकांश समय हम सरकारों की आलोचना ही करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कार्यों का क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए. हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान सरकार का भी क्योंकि उन्होंने हर जगह हमारा समर्थन और सहयोग किया है.

इंटरव्यू

खेलों के विकास के लिए व्यापक सोच की ज़रूरत

पुलेला गोपीचंद

साल 2002 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब जीतने वाले पुलेला गोपीचंद आज भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं. उनकी देखरेख में भारत में बैडमिंटन की एक नई पीढ़ी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा रही है. इन खिलाड़ियों में सायना नेहवाल, पीवी संधु, ज्वाला गुट्टा अश्विनी पोनप्पा, के श्रीकांत, पी कश्यप, अजय जयराम जैसे कई नाम शामिल हैं. गोपीचंद को अर्जुन अवॉर्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. उन्होंने भारतीय बैडमिंटन के बदलते परिदृश्य से लेकर मोदी सरकार के खेलों के विकास की एप्रोच तक, विभिन्न पहलुओं पर चौथी दुनिया संवाददाता नवीन चौहान से बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश.

■ रियो ओलंपिक मजह छह–सात महीने दूर हैं, बतौर बैंडमिंटन केराष्ट्रीय कोच आपको भारत के कैसे प्रदर्शन की आशा है?

अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में कर रहे हैं, उससे लगता है कि ओलंपिक में बड़ा भारतीय दल भाग लेगा. एक बार खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लें, उसके बाद हम खिलाड़ियों के आधार पर ओलंपिक के लिए तैयारियां कर सकेंगे.

■ ओलंपिक से पहले आईबीएल (इंडियन बैडमिंटन लीग) फिर सुपर सीरीज, ऐसे में ओलंपिक से पहले खिलाड़ी चोटों से दूर रहेंगे और बेहतर तैयारी कर पायेंगे?

बीडब्लूएफ को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस बार प्रतियोगिताओं को इस तरह रखा है कि इस साल की आख़िरी सुपर सीरीज नवंबर में है, इसके बाद अगले साल की पहली मार्च में है, इसलिए हमारे पास तीन महीने का समय है. इस दौरान खिलाड़ी आराम कर सकेंगे और आने वाले ओलंपिक क्वालीफायर्स और सुपर सीरीज की तैयारी कर सकेंगे.

■ भारतीय बैडमिंटन टीम ओलंपिक में इस बार कितने पदक जीतेगी?

इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी. लेकिन हम आशा करते हैं कि पिछली बार हमने जैसा प्रदर्शन किया था उससे बेहतर प्रदर्शन हम रियो में करेंगे.

■ आईबीएल ने खिलाड़ियों के खेल कौशल में सुधार में किस तरह योगदान किया है? दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने, उनके साथ वक्त गुजारने से उन्हें किस तरह फायदा हुआ है?

हमारे युवा खिलाड़ी जब देश–विदेश के टॉप प्लेयर्स के साथ सफर कर रहे थे, उनके साथ समय गुजार रहे थे. एक नजरिए से इससे उनके खेल में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. विश्व के टॉप प्लेयर्स के साथ रहने, उनके साथ खेलने, उनके खेल को करीब से देखने, उनसे बातचीत करने से निश्चित रूप से फायदा होता है. इस अनुभव का फायदा हमारे खिलाड़ियों को भी हुआ है और यह अब उनके प्रदर्शन में दिखाई पड़ रहा है.

■ नए खिलाड़ियों में ऐसे कौन से हैं जो सायना नेहवाल के खेल के स्तर के हैं या भविष्य में उस स्तर तक पहुंच सकते हैं?

हमारे सभी खिलाड़ियों में विश्व स्तर पर जीतने की क्षमता है. कम उम्र में भी बहुत से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें अपने प्रदर्शन को स्थिर रखना होगा और अनुभव लेना होगा. मुझे लगता है कि आगे भी वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

■ आप अपनी बेटी गायत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वह भी बैडमिंटन में अच्छा कर रही हैं, सभी आशा कर रहें हैं कि वह आपके नक्शे कदम पर चलकर देश का नाम रोशन करेंगी?

गायत्री के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. वास्तविक चुनौतियां मेरे और उसके लिए अब शुरू हुई हैं, मैं इस बात से खुश हूं कि उसने जिस तरह प्रोगरेस की है वह संतोषजनक है. आने वाले समय में वह इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगी.

■ बैडमिंटन खेलने का निर्णय उनका स्वयं का है या आपने और आपकी पत्नी ने इसके लिए उनपर दबाव बनाया?

शरुआत में मैं सुबह जल्दी उठकर एकेडमी जाता था, तब वह सोती रहती थी और जब वापस आता तब भी. मैं उसे तभी खेलता देख पाता था जब वह मेरे सामने एकेडमी में होती थी. उसी दौरान मैंने उसे शुरूआती ट्रेनिंग दी. इसके बाद उसकी खेल में रुचि बढ़ी, आज उसे बैडमिंटन पसंद है. मैंने या मेरी पत्नी ने बच्चों पर कभी बैडमिंटन खेलने के लिए दबाव नहीं डाला.

■ ऐसा कहा जा रहा है कि आपके सायना के साथ कुछ मतभेद हैं, क्या यह सही बात है?

इस मौके पर, इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा. लेकिन किसी अन्य उपयुक्त मौके पर इस बारे में बात करूंगा.

■ केंद्र सरकार खेलों के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है?

खेलों को लेकर सरकार को रुख पूरी तरह सकारात्मक है. मैंने सरकार को खेलों के लिए काम करते हुए बहुत करीब से देखा है. मेरे पास पूरी ईमानदारी से यह मानने के कारण हैं कि सरकार में पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं जो देश में खेलों की स्थिति में बदलाव और बेहतरी होता देखना चाहते हैं. हमारे देश में जहां खेलों में कॉम्पेक्स कल्चर या कहें खेलों पर नियंत्रण करने वाली विभिन्न संस्थायें हैं, यहां खेलों को लेकर समझ की कमी है मसलन, खिलाड़ियों की जरूरत क्या है. कई बार इस दौरान हमें आगे आकर कहना पड़ता है कि आप सही जगह या सही चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं. आपके पास खेलों के कई मामलों में दूरदर्शी योजनायें या नजरिया नहीं है न ही कोई दूरदर्शी सिस्टम है. खेलों के विकास का समर्थन करने वाले अच्छे लोगों के होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि जो परिणाम हम चाहते हैं वे हमें जल्दी मिलने लगेंगे. सभी चीजों के सही रास्ते में आने में अभी वक्त लगेगा. सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केवल अभी नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से. अधिकांश समय हम सरकारों की आलोचना ही करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कार्यों का क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए. हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान सरकार का भी क्योंकि उन्होंने हर जगह हमारा समर्थन और सहयोग किया है.

■ एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि खेलों का प्रशासन खिलाड़ियों के हाथों में होना चाहिए. सरकार के साथ टॉप्स जैसी योजना की निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के बाद आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

मुझे लगता है कि आज हम जो बातें कर रहे हैं वह बहुत कम हैं, मुझे लगता है कि हमें खेलों के बारे में व्यापक स्तर पर बातें करनी चाहिए. अभी खेलों का दायरा सीमित है, फंडिंग सीमित है.

स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और खेल मंत्रालय को एक साथ लाकर एक नई युनिट का गठन करना चाहिए, तब जाकर हम देश में खेलों में सुधार या प्रशासन खिलाड़ियों के हाथों में देने की बात कर सकते हैं. वर्तमान में सरकार की खेलों के विकास की सोच का दायरा सीमित है.

■ बैडमिंटन का देश में दायरा बढ़ रहा है, ग्वालियर में भी आपकी एकेडमी है और दूसरे छोटे शहरों में भी, उन जगहों के खिलाड़ियों से आपको क्या आशायें हैं?

मेरा मानना है कि भारत में लोगों के पास खेलों के लिहाज से नेचुरल एडवांटेज हैं. एक सही एप्रोच के साथ ही हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. इसके लिए खिलाड़ियों के सही प्रशिक्षण की जरूरत है, ऐसा करके हम छोटी जगहों से भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं. ■

navinonline2003@gmail.com

एक खेल ऐसा भी

चेस–बॉक्सिंग

चेस–बॉक्सिंग,यह दिमाग और शरीर दोनों की क्षमता को एक साथ परखने वाला खेल है. इसमें शामिल खिलाड़ी पहले चेस खेलते हैं, इसके बाद मुक्केबाज़ी करते हैं इसके बाद फिर से चेस खेलते हैं. इस तरह चेस के 6 राउंड के बीच मुक्केबाजी के 5 राउंड होते हैं. दो बेहद अलग तरह के इन खेलों को मिलाकर नया खेल ईजाद करने का आइडिया हॉलैंड के कलाबाज लीपे रुबनिंघ को 1992 में एक कॉमिक बुक मिला था. इस खेल में चेस और बॉक्सिंग के सभी मूल नियम शामिल हैं. हालांकि चेस के एक राउंड का अधिकतम समय 18 मिनट है. यानी एक खिलाड़ी 9 मिनट का समय ले सकता है. वहीं बॉक्सिंग में तीन–तीन मिनट के पांच राउंड होते हैं. बॉक्सिंग राउंड के बाद चेस वहीं से शुरू किया जाता है जहां उसे रोका गया था. चेस और बॉक्सिंग राउंड्स केबीच खिलाड़ी को एक मिनट का ब्रेक मिलता है. लंदन के पास एक बॉक्सिंग क्लब में इस खेल का पहला आयोजन हुआ. 2003 में बर्लिन में वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग ऑर्गेना–इजेशन का गठन हुआ. यह खेल आज अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में काफी लोकप्रिय है. हालांकि, अब भारत के साथ–साथ, चीन व ईरान में भी इसके खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है. इसकी भारत में शुरूआत हुए 4 साल हुए हैं. लेकिन इससे संबंधित कई संघ तैयार हो गए हैं. ■

आर्थर रॉबर्ट ऐश

आर्थर रॉबर्ट ऐश अंतरराष्ट्रीय टेनिस में सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी थे. पांच जुलाई 1975 को विंबलडन का एकल खिलाब जीतने वाले वह पहले अश्वेत खिलाड़ी बने थे. ऐश ने इस ख़िताबी मुक़ाबले में सर्वकालिक महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक जिमी कॉर्नर को 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 के अंतर से हराया था. विंबलडन जीतने के बाद वह साल 1975 में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए थे. टेनिस जगत में आर्थर ऐश की ये पहली उपलब्धि नहीं थी, इससे पहले वह साल 1968 में वह यूएस ओपन का खिलाब जीत चुके थे. इसके बाद 1970 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था. हृदय की दो बार तथा मस्तिष्क की एक बार शल्य चिकित्सा होने के बाद उन्होंने समय से पहले ही साल 1980 में उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया. इसके बाद उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के जरिये समाज में मानवाधिकार, जन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों में अहम योगदान दिया. ऐश को साल 1988 में यह जानकारी मिली कि वह एचआईवी संक्रमण के शिकार हैं. इलाज के दौरान संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की वजह से उन्हें यह संक्रमण हुआ था. वर्ष 1992 में उन्होंने अपनी इस बीमारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया. ऐश को विश्व टेनिस जगत के भद्र खिलाड़ियों में से एक माना जाता था. 6 फरवरी 1993 को न्यूयार्क सिटी में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. करियर में उन्होंने तीन ग्रैंड स्लैम खिताब सहित कई अन्य खिताब जीते. मृत्यु के बाद न्यूयार्क के जिस स्टेडियम में अमेरिकी ओपन का आयोजन होता है उसका नाम उनके सम्मान में ऑर्थर ऐश स्टेडियम कर दिया गया. ■

आपको जो कम भुगतान करे, उसके साथ काम न करें

सोनम

सोनम फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान के साथ दिखाई देंगी. 17वें जियो मामी मुंबई फिल्म उत्सव में मूवी मेला कार्यक्रम के दौरान सोनम ने कहा, महिलायें असमान भुगतान के बारे में शिकायत करती हैं और मैं इसे समझती हूं. अगर आप किसी चीज के लायक हैं, तो उसके लिए लड़िए और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है उस काम को न करना.

बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन सोनम कपूर ने कहा है कि असमान मेहनताना की शिकायत करने के बजाय महिलाओं को ऐसे लोगों के साथ काम करना बंद कर देना चाहिए, जो उन्हें कम भुगतान करते हैं. सोनम फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान के साथ दिखाई देंगी. वह अपने पिता अनिल कपूर को भी नारीवादी मानती हैं क्योंकि वह उनके साथ एक मजबूत-सक्षम शख्स के तौर पर व्यवहार करते हैं. 17वें जियो मामी मुंबई फिल्म उत्सव में मूवी मेला कार्यक्रम के दौरान सोनम ने कहा, महिलायें असमान भुगतान के बारे में शिकायत करती हैं और मैं इसे समझती हूं. अगर आप किसी चीज के लायक हैं तो उसके लिए लड़िए और इसका सबसे बेहतरीन तरीका इस काम को न करना. इस समारोह के एक दूसरे सत्र के दौरान दीपिका पादुकोण ने कहा कि वह उन्हें किए जाने वाले भुगतान से नाखुश नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि जब आज की पीढ़ी के सितारों की बात आती है तो इसमें कुछ समानतायें होनी चाहिए. सोनम ने कहा कि वह पूरी तरह से नारीवादी हैं और इस बारे में शर्म महसूस नहीं करती हैं.परिणीति चोपडा, कैटरीना कैफ सरीखी अभिनेत्रियों की उनकी टिप्पणी को लेकर आलोचाना की जाती है कि वे नारीवादी नहीं है लेकिन समानता में यकीन रखती हैं. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शानदार की स्टार आलिया भट्ट ने कहा कि वह आंशिक नारीवादी हैं.■

बाजीराव मस्तानी में काम न करने का मलाल

ऐसा बहुत कम हुआ है कि बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान ख़ान को किसी फिल्म को छोड़ने का मलाल हुआ हो, लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम नहीं कर पाने का उन्हें बहुत दुख है. कई सालों से बन रही इस फिल्म के लिए कई बार कलाकारों को बदला गया. शुरू में भंसाली ने घोषणा की थी कि वह इस फिल्म में सलमान और ऐश्वर्या राय को कास्ट करेंगे. लेकिन दोनों के बीच में अलगाव के बाद वे इसका हिस्सा नहीं बन सके. इसके बाद शाहरुख ख़ान और रितिक रोशन केभी इसमें काम करने की खबरें सामने आईं. आखिरकार बाजीराव की भूमिका केलिए रणवीर सिंह को चुना गया. इसके बाद एक्ट्रेस के लिए करीना कपूर के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ. आखिरकार प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को काशीबाई और मस्तानी (बाजीराव की पहली और दूसरी पत्नी) की भूमिका केलिए चुना गया.

शुरू में भंसाली ने घोषणा की थी कि वह फिल्म में सलमान और ऐश्वर्या राय को कास्ट करेंगे. लेकिन दोनों के बीच में अलगाव के बाद वे इसका हिस्सा नहीं बन सके. बाद में शाहरुख ख़ान और रितिक रोशन के भी इसमें काम करने की खबरें आईं. आखिरकार बाजीराव की भूमिका के लिए रणवीर सिंह को चुना गया.

सलमान ने एक इंटरव्यू अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशन के दौरान बताया कि, बाजीराव मस्तानी में काम नहीं करने का उन्हें मलाल है. मुझे प्रेम रतन धन पायो में काम करना था. मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी है, यह बहुत ही अच्छी है. सलमान ने बताया कि करीना और उन्होंने बाजीराव मस्तानी केलिए एक फोटोशूट किया था लेकिन वह इस फिल्म में काम नहीं कर सके. सलमान ने यह भी बताया कि अब मैं इस फिल्म का (बाजीराव मस्तानी) प्रोमो देख रहा हूं, इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया गया है. मुझे लगता है कि रणवीर, प्रियंका और दीपिका तीनों शानदार हैं. ■

अमेरिकी टॉक शो होस्ट करने का ऑफर!

प्रियंका धीरे-धीरे अमेरिका में अपने पंख पसार रही हैं. पहले उन्होंने यहां अपने म्यूजिक करियर की शुरूआत की, इसके बाद एनिमेशन फिल्म प्लेन्स में डिज्नी चरित्र को अपनी आवाज दी.

अमेरिकी टीवी सीरियल क्वांटिको में एक्टिंग के लिए सराहना पा रही बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया जा रहा है उन्हें अमेरिकी सेलिब्रिटी टॉक शो को होस्ट करने के लिए संपर्क किया गया है. प्रियंका धीरे-धीरे अमेरिका में अपने पंख पसार रही हैं. पहले उन्होंने यहां अपने म्यूजिक करियर की शुरूआत की, इसके बाद एनिमेशन फिल्म प्लेन्स में डिज्नी चरित्र को अपनी आवाज दी. इसके अलावा वह अमेरिका के मेन स्ट्रीम टेलीविजन ड्रामा एबीसी के क्वांटिको का हिस्सा बनीं. अब नई खबर आ रही है कि उन्हें एबीसी द्वारा अमेरिकी सेलिब्रिटी टॉक शो को होस्ट करने का ऑफर मिला है, हालांकि इस संबंध में प्रियंका ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है.■

अनिल कपूर नहीं थे मिस्टर इंडिया के लिए पहली पसंद

मुफलिसी के बावजूद बहुत सारे अनाथ बच्चों को पालने वाले मिस्टर इंडिया के किरदार को निभाकर अनिल कपूर ने भले ही अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हीरों के रोल के लिए वह निर्माता-निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे, इस भूमिका की सबसे पहले पेशकश अमिताभ बच्चन को की गई थी. पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने मामी मुंबई फिल्मोत्सव के दौरान इस बात का खुलासा किया कि साल 1987 में आई ब्लॉकबस्टर मिस्टर इंडिया के निर्माता इस फिल्म में बच्चन को लेने के बारे में विचार कर रहे थे. अख्तर ने लिखा है, प्रमोद चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका के साथ एक फिल्म शुरू की थी और उन्होंने टेप रिकॉर्डर में उनका एक शॉट भी रिकॉर्ड किया गया था, इसी दौरान गायब होने वाले व्यक्ति का आइडिया आया, लेकिन उनके (अमिताभ बच्चन के) साथ चीजें सिरे नहीं चढ़ सकीं. इसके बाद मिस्टर इंडिया के लीड रोल के लिए अनिल कपूर को कास्ट कर लिया गया. फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म के अन्य कलाकारों श्रीदेवी, अनिल कपूर, सतीश कौशिक, निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म के बारे में अपने अनुभव साझा किए.

इस दौरान निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि वह मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाने को लेकर उत्सुक हैं, लेकिन शेखर कपूर इसे निर्देशित नहीं करेंगे. मिस्टर इंडिया को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच बोनी ने पुष्टि की कि वह एक रोमांचक पटकथा की तलाश में हैं.■

इन्हें भुला न पाएंगे

प्रेम नाथः हीरो बनते-बनते विलेन बन गए

बॉलीवुड में प्रेम नाथ को एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने नायक के रूप में फिल्म जगत में राज करने के बावजूद खलनायकी को एक नया आयाम देकर दर्शकों के दिलों पर अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी. पचास के दशक में प्रेम नाथ ने कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई और इनमें से कई फिल्में हिट भी रहीं, लेकिन उन्हें नायिकाओं के पीछे पेड़ों केइर्द-गिर्द चक्कर लगाते हुए गीत गाना रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने नायक की भूमिका निभाने की तमाम पेशकशों को नामंजूर कर दिया. इसके बदले उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं निभाने को तरजीह दी. 21 नवंबर 1926 को पेशावर में जन्मे प्रेम नाथ को बचपन से ही अभिनय का शौक था. देश के बंटवारे केसमय उनका परिवार पेशावर से मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में आकर बस गया. पचास के दशक में उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया और पृथ्वी राज कपूर के पृथ्वी थियेटर में अभिनय करने लगे. वर्ष 1948 में उन्होंने फिल्म अजित से अपने फिल्मी जीवन की शुरूआत की, लेकिन इस फिल्म से दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके. वर्ष 1948 में राजकपूर की फिल्म आग और वर्ष 1949 में राजकपूर की रिलीज हुई फिल्म बरसात की सफलता के बाद प्रेम नाथ कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए. वर्ष 1953 में फिल्म औरत के निर्माण केदौरान प्रेम नाथ का झुकाव अभिनेत्री बीना राय की ओर हो गया. इसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली. शादी के बाद उन्होंने बीना राय के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और पीएन फिलम्स की स्थापना की. इस बैनर के तले उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई. इसके बाद प्रेम नाथ ने फिल्म निर्माण से तौबा कर ली और अपना ध्यान अभिनय की ओर लगाना शुरू कर दिया.

इस बीच प्रेम नाथ ने कुछ फिल्मों में अभिनय किया और उनकी फिल्में सफल भी हुईं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुख्य अभिनेता की बजाय खलनायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में उनका भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा. इसके बाद प्रेम नाथ ने खलनायक की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं. प्रेम नाथ के पसंदीदा किरदारों की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपना कभी नहीं भुलाया जा सकने वाला किरदार 1970 में प्रर्दशित फिल्म जॉनी मेरा नाम में निभाया. उनके भूमिका दर्शकों को बहुत पसंद आई.

वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म धर्मात्मा में प्रेम नाथ के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला. 1970 में ही प्रदर्शित राजकपूर की सुपरहिट फिल्म बॉबी में उन्होंने अभिनेत्री डिंपल कपाडिया के पिता की भूमिका निभाई. इस फिल्म में दमदार अभिनय केलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था. अस्सी के दशक में स्वास्थ्य खराब रहने के कारण प्रेम नाथ ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया. वर्ष 1985 में प्रदर्शित फिल्म हम दोनों उनके सिने करियर की आखिरी फिल्म थी. करीब तीन दशक तक अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में अपनी खास पहचान बनाने वाले प्रेम नाथ ने 3 नवंबर 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह गए.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

16 नवंबर–22 नवंबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अगड़े-पिछड़े में फंस गई भाजपा की नाव

जनता ने सभी नेताओं को सुना पर बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आठ नंवबर को आए हैं उनसे साफ हो गया कि बिहार की जनता ने सुनी तो सबकी पर भरोसा किया नीतीश और लालू प्रसाद की बातों पर. भाजपा के सारे रणनीतिकार चुनावी घोषणा के पहले तक इस बात को लेकर आशवस्त थे कि खराब से खराब हालात भी पैदा हुए तो भी सूबे में वह अपनी सरकार बना ही लेंगे. लेकिन चुनाव से ऐन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक ऐसा हथियार थमा दिया जिसकी काट एनडीए के नेताओं के पास शुरू के तीन चरणों में नहीं थी.

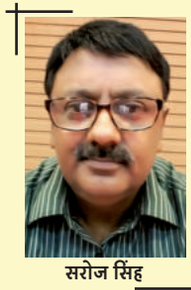

सरोज सिंह

गांधी मैदान में बम–धमाकों के बीच नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2013 को ऐलान किया था कि बिहार में विकास की नई कहानी लिखने का वक्त अब आ गया है. अब यह बिहार के हिंदू और मुसलमानों को तय करना है कि उन्हें आपस में ही लड़ना है या दोनों को मिलकर यहां की गरीबी से लड़ना है. नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार से मिले प्यार को सूद समेत लौटाउंगा यह वादा करके जा रहा हूं. फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी दौरे पर आए तो उन्होंने अपने इसी इरादे को दोहराया और बिहार की जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आपने दूसरे दलों और नेताओं को 60 साल दिया है, मुझे आप बस 60 महीने दीजिए, मेरा वादा है कि इस राज्य का कायाकल्प कर दूंगा. बिहार में अब तक के सबसे कटुता भरे चुनाव प्रचार में भूत पिशाच, शैतान, गाय, बंदर और न जाने किन–किन मुद्दों पर गरमागर्म बहस हुई और आरोपों का विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बिना देर किए जवाब भी दिया. जनता ने सभी नेताओं को सुना पर बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आठ नंवबर को आए हैं उनसे साफ हो गया कि बिहार की जनता ने सुनी तो सबकी पर भरोसा किया नीतीश और लालू प्रसाद की बातों पर. भाजपा के सारे रणनीतिकार चुनावी घोषणा के पहले तक इस बात को लेकर आशवस्त थे कि खराब से खराब हालात भी पैदा हुए तो भी सूबे में वह अपनी सरकार बना ही लेंगे. लेकिन चुनाव से ऐन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक ऐसा हथियार इन दोनों नेताओं को थमा दिया जिसकी काट एनडीए की नेताओं के पास शुरू के तीन चरणों में नहीं थी. चौथे चरण में नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी काट खोजने की कोशिश की पर तब तक काफी देर हो चुकी थी. दरअसल आरक्षण की समीक्षा की बात ने भाजपा के गेम प्लान को ही चौपट कर दिया. लोकसभा चुनाव के बाद ही भाजपा ने पिछड़ों और अतिपिछड़ों में अपनी पैठ बनाने का काम शुरू कर दिया था. जिलास्तर पर सम्मेलन और संगोष्ठियों का दौर चला. पिछड़े और अतिपिछड़े में इस बात को लेकर भाजपा की स्वीकार्यता भी बढ़ रही थी कि पार्टी उन्हें उचित सम्मान देने की बात कह रही है.

इधर रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और बाद के दिनों में मदन सहनी को साथ लेकर भाजपा ने यह सुनिष्चत कर लिया था कि पिछड़े, अतिपिछड़े और महादलित का ज्यादातर वोट एनडीए के पाले में जाऐगा. लेकिन चुनाव षुरू होने के ठीक पहले मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाली बात को महागठबंधन के नेताओं ने खासकर लालू प्रसाद ने लोक लिया और गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि यह लड़ाई अगड़े और पिछड़े की है. इसके बाद तो जमीनी स्तर पर यह संदेश चला गया कि पिछड़ों को एक होना जरूरी है नहीं तो अगर एनडीए की सरकार बन गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और बाल बच्चों को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. लालू और नीतीश की टीम इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि चुनाव के पांचवें चरण तक इन लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को जिंदा रखा और इसका असर चुनाव नतीजों पर साफ दिखा. आरक्षण के अलावा एनडीए की हार के कारणों को खोजने की अगर कोशिश की जाए तो यह बात सामने आती है कि काला धन और महंगाई के मुद्दे ने भी वोटरों को राज्य में प्रभावित किया. खासकर दाल को लेकर महिलाओं में काफी गुस्सा था और महागठबंधन के नेताओं ने इसे बखूबी भुनाया. दाल को लेकर भी एनडीए की सफाई आने में काफी देरी हुई और तब तक यह बात रसोईघरों तक पहुंच गई थी कि मोदी सरकार महंगाई पर काबू नहीं रख पा रही है. कालेधन की वापसी को जुमले के तौर पर पेश कर भी व्यंग्यबांण चलाने में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने कोई कमी नहीं की. कुछ जानकार बताते हैं कि बिहार में भाजपा के हार की एक वजह नरेंद्र मोदी की रैलियों का ओवरडोज भी रहा. आम जनता को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रहे हैं. भाजपा की यह रणनीति उल्टी पड़ गई. इसके अलावा भाजपा की स्थानीय इकाई बिहार पैकेज को राज्य में बड़ा मुद्दा नहीं बना पाई. लोग इस भ्रम में पड़ गए कि कहीं कालेधन की तरह यह भी जुमला न हो जाए. लोगों ने इस पैकेज को संदेह की नजर से देखा. भाजपा के ज्यादातर नेताओं ने गोमांस और पाकिस्तान को पैकेज से ज्यादा तवज्जो दी. नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों की जबरदस्त गोलबंदी महागठबंधन के पक्ष में हुई. गोलबंदी ऐसी थी कि लोगों ने ओवैसी की पार्टी को भी दरकिनार कर दिया. इसके उलट जो गोलबंदी एनडीए के पक्ष में होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई क्योंकि आरक्षण ने इसमें पहले से ही सेंध लगा दी थी. इसका बड़ा नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा. इन सबके अलावा भाजपा नेताओं के बीच चुनाव प्रबंधन को लेकर भी आपसी तालमेल का घोर अभाव दिखा. नेताओं के चुनावी दौरे लगाने से लेकर प्रचार वाहन और सामग्री के बंटवारे में भी समन्वय का अभाव साफ दिखाई पड़ा. उदाहरण के तौर पर देखिए तो राघोपुर में राजनाथ सिंह को छोड़कर कोई राजपूत नेता नहीं भेजा गया. यादव नेताओं के दौरे भी नहीं कराए गए. रामकृपाल यादव गए भी तो रात के अंधेरे में. राघोपुर भेजा गया रविशंकर प्रसाद और सूरजनंदन मेहता को. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा ने वीआईपी सीटों को भी कितने हल्के अंदाज में लिया. भाजपा नेताओं को लगता रहा कि केवल और केवल मोदी के नाम पर वह चुनाव जीत जाएंगे.

भाजपा नेताओं ने पूरे चुनाव में माना कि मोदी लहर में इनकी नैया पार लग जाएगी. लेकिन अगड़े और पिछड़े की खाई इतनी बढ़ गई कि इसे भरना नरेंद्र मोदी के लिए भी संभव नहीं हो पाया. इन सबके अलावा भाजपा का अति आत्मविश्वास भी एनडीए के लिए घातक साबित हुआ. भाजपा ने चुनाव के पहले ही मान लिया था कि वह भारी अंतर से यह चुनाव जीतकर बिहार में सरकार बनाने जा रही है. लेकिन चुनाव के दौरान बदली हुई राजनीतिक परिस्थतियों को वह नहीं पढ़ पाई और नतीजा सबके सामने है. अभी तो हरेक कोण से भाजपा की हार पर मंथन जारी है लेकिन लगता है यह पार्टी के लिए ऐसा झटका है जिससे संभलने में उसे काफी समय लगेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा के ज्यादातर नेताओं ने गोमांस और पाकिस्तान को पैकेज से ज्यादा तवज्जो दी. नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों की जबरदस्त गोलबंदी महागठबंधन के पक्ष में हुई. गोलबंदी ऐसी थी कि लोगों ने ओवैसी की पार्टी को भी दरकिनार कर दिया. इसके उलट जो गोलबंदी एनडीए के पक्ष में होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई क्योंकि आरक्षण ने इसमें पहले से ही सेंध लगा दी थी. इसका बड़ा नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा. इन सबके अलावा भाजपा नेताओं के बीच चुनाव प्रबंधन को लेकर भी आपसी तालमेल का घोर अभाव दिखा.

एक नज़र

जुटेंगे देश भर से पुनर्वास-कर्मी

यह भारत का एक मात्र सम्मेलन है, जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी प्रकार के विशेषज्ञों को साझा मंच प्रदान करता है, जिसमें एक साथ मिलकर विकलांगता की जटिल और गंभीर समस्याओं के निदान का मार्ग खोजा जाता है. आयोजन समिति की ओर से आयोजित एक संवाददाता-सम्मेलन को संबोधित करते हुए,समिति के संरक्षक और संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉ. अनिल सुलभ ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि, इस वर्ष के पुनर्वास-सम्मेलन में चिंतन का मुख्य-विषय बहु विकलांगता और निदान है.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, बेउर,पटना के संयुक्त तत्वावधान में विगत 2010 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा पुनर्वास-विशेषज्ञों का महाकुंभ पुनर्वास-सम्मेलन 7वां रिहैब-मीट-2016, हेल्थ इंस्टिच्यूट में आगामी 13 से 15 फरवरी को आयोजित होना है. तीन दिवसीय सम्मेलन में देश भर के एक हजार से अधिक पुनर्वास विशेषज्ञ भाग लेंगे. यह भारत का एक मात्र सम्मेलन है, जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी प्रकार के विशेषज्ञों को साझा मंच प्रदान करता है, जिसमें एक साथ मिलकर विकलांगता की जटिल और गंभीर समस्याओं के निदान का मार्ग खोजा जाता है. आयोजन समिति की ओर से आयोजित एक संवाददाता-सम्मेलन को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक और संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉ. अनिल सुलभ ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि, इस वर्ष के पुनर्वास-सम्मेलन में चिंतन का मुख्य-विषय बहु विकलांगता और निदान है. इस विषय पर कृत्रिम अंग निर्माण-विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, अकुपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीचथैरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, हड्डी-रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, शिशु-रोग विशेषज्ञ व स्त्री-रोग विशेषज्ञ समेत विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के विशेषज्ञ चर्चा में हिस्सा लेंगे और इस समस्या की रोकथाम और निदान के संबंध में एक साझा प्रतिवेदन तैयार करेंगे. आयोजन समिति के अध्यक्ष आकाश सुलभ, आयोजन सचिव डॉ. अनूप कुमार गुप्ता, डॉ. राजेश झा, डॉ. विकास कुमार सिंह, डॉ. पी कुमार, आभास कुमार, प्रो. संजीत कुमार, डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. असरार अली खान, अभिजीत पांडेय, प्रो. रणजीत कुमार, अंबिका दत्त पांडेय, कुमारी पूर्णिमा, सरिता कुमारी, विजय प्रकाश तिवारी तथा अंजू कुमारी समेत आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.■

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

मौसम परिवर्तन से परेशानी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR. MD. TANWIR HAIDER
MBBS, PGDSM (VELLORE)
EX. RES. AIIMS, NEW DELHI

कटिहार के कुशल चिकित्सक डॉ.मो. तनवीर हैदर से टेलिफोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

आजकल मौसम परिवर्तन के कारण लोगों को बुखार, सर्दी-खांसी देखने को मिल रहा है। उनका सुझाव है कि अभी ए.सी का यूज नहीं करें या करें तों कम। भींगे हुए पंखे के नीचे नहीं रहें। बॉडी टेम्परेचर को बाहर और घर के तापमान में एडजेस्ट रखें। यदि बाहर निकलें तो सुबह में पूरा बदन ढक कर निकलें। इनका कहना है कि जाड़े का मौसम आते ही लोग अलाव और हीटर का प्रयोग करते हैं लेकिन प्रयोग के वक्त सावधानी रखें। चीनी हल्दी गुड़ के सेवन पर बल दें। खाने में ठंढी चीजों से परहेज करें। बासी खाना न लें। गर्म और ताजा खाना ही लें। इस मौसम में सांस सम्बन्धी रोगी या दम्मा पेसेन्ट की परेशानी बढ़ जाती है। वे अपना ख्याल रखें। सामान्य बुखार में पारासिटामोल के साथ-साथ एन्टी एलर्जीक सीट्रीज, लीवोसिट्रीज पांच दिन तक लें। सामान्य रूप से सादी चाय अदरक, तुलसी और काली मिर्च पिस कर बना लें और प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मरीज की परिस्थिति के अनुसार अपने नजीदीकी एवं कुशल चिकित्सक से शीघ्र सम्पर्क करें। ■- भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

झारखंड

गरीबों की कमाई का जरिया बना अवैध कोयला

जिले में कोयले का प्रचुर भंडार है लेकिन स्थानीय लोगों को जलावन से लेकर अन्य कामों के लिए वैध कोयला नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय लोग चोरी के कोयले पर ही आश्रित हैं. जिसका एक मुख्य कारण यहां पर कोयले का उठाव स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाना है.स्थानीय स्तर पर कोयले के उठाव के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने अवाज भी उठाई है. कई बार अनशन तक किया गया लेकिन आज तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. जबकि एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 500 से 1000 मजदूर साइकिल से कोयला ढोते हैं जो पुलिस के भय के साए में इस कोयले का उठाव करते हैं.सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है.

दिवाकर तिवारी feedback@chauthiduniya.com

गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड स्थित ईसीएल की राजमहल परियोजना को एशिया को सबसे बड़ी खुली खदान का गौरव प्राप्त है.इस खदान का प्रति वर्ष कोयले का उत्पादन का लक्ष्य लगभग 17 मिलियन टन का है.जिस लक्ष्य को यह परियोजना प्रति वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन के साथ पूरा करती है. कंपनी प्रतिवर्ष 200 करोड़ का मुनाफा कमा रही है. जिस प्रकार इस परियोजना का रिकॉर्ड कई मामले में आगे है उसी तरह इस परियोजना से अवैध कोयले का उठाव भी रिकॉर्ड ही होता है.

झारखंड के नए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पदभार संभालते हुए ही तमाम जिले के अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया कि अगर अवैध कोयले का उठाव बड़े वाहनों से किया जाएगा तो इसके लिए जिले के तमाम आलाधिकारी नपेंगे,और साइकिल से कोयला ढोने वाले मजदूरों को कोई भी पुलिस कर्मी परेशान न करे. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तो बड़े वाहनों पर नकेल जरूर कसी गई लेकिन माफियाओं के कोयला ढोने एवं उठाव का तरीका बदल गया.सीएम ने तो घोषणा कर दी कि साइकिल से कोयला ढोने वाले मजदूरों को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन उनके लिए वैध कोयला की व्यवस्था नहीं हुई जिसके कारण आज भी कोयला ढोने वाले मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जिले में कोयले का प्रचुर भंडार है लेकिन स्थानीय लोगों को जलावन से लेकर अन्य कामों के लिए वैध कोयला नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय लोग चोरी के कोयले पर ही आश्रित हैं. जिसका एक मुख्य कारण यहां पर कोयले का उठाव स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाना है.स्थानीय स्तर पर कोयले के उठाव के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने अवाज भी उठाई है,कई बार अनशन तक किया गया लेकिन आज तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.जबकि एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 500 से 1000 मजदूर साइकिल से कोयला ढोते हैं जो पुलिस के भय के साए में इस कोयले का उठाव करते हैं.सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है. आखिर वे किस तरह फैसले को अमली जामा पहनाएं. इनका आदेश है कि किसी भी कीमत पर जिले में अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए, जिस आदेश का पालन जिले के तमाम अधिकारी करने में लगे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है और जिले में अवैध कोयला ढुलाई पर अंकुश लग चुका है.

साइकिल से कोयला ढोने वाले मजदूर कहते हैं कि उनकी जो समस्या पहले थी आज भी जस की तस बनी हुई है. कारण वैध कोयला उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो भी कोयला है वह अवैध खदान का है या कोयला अवैध तरीके से उठाया हुआ है.साइकिल से कोयला ढोने वाले के सामने कई समस्याएं हैं. परियोजना के आसपास बसे स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें नाहक परेशान किया जाता है, कोयला माफिया कि निगाहें भी इन कोयला साइकिल मजदूरों पर रहती हैं वह भी उनके कोयले को औने पौने दाम पर खरीद कर बड़े वाहनों से दूसरी जगह बेच देते हैं. जिस जिस थाना क्षेत्र से ये लोग गुजरते हैं, उन्हें उस थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा भी परेशान किया जाता है. कोयला मजदूरों के अनुसार 100 से 200 रुपये प्रति थाने देना पड़ता है. अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो पुलिस के हत्थे चढ़ने पर जेल की हवा भी खानी पड़ती है और जेल से निकलने में इन्हें हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं.इन कोयला ढोने वाले मजदूरों में कई नाबालिग बच्चे भी रहते हैं. जिनका बचपन इस कोयले की कालिख में कहीं खोता नजर आ रहा है.

सरकार भी इन मजदूरों के प्रति उदासीन है अगर सरकार को इन मजदूरों की थोड़ी भी चिंता है तो कोयले का लोकल सेल जरूर चालू करवा देना चाहिए. कोयले के लोकल सेल चालू हो जाने से परियोजना के आसपास के कई जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा.लोकल सेल होने पर जिले के लोगों को जलावन के लिए कोयला और मजदूरों को भी वैध कोयला मिलने लगेगा.वैध कोयला जब स्थानीय स्तर पर लोगों को मिलने लगेगा तब उद्योग धंधे का भी बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा.आज कोयला के अभाव में लोगों को चोरी के कोयले पर आश्रित रहना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी होती है.जबकि जिले मे ईंट भठ्ठे का धंधा जोरों पर चलता है. ईंट भठ्ठे चलाने वाले व्यापारियों का कहना है कि या तो वे कोयला साइकिल वालों से खरीदतें हैं या नहीं तो दूसरी जगह से इन्हें कोयला मंगवाना पड़ता है जो काफी मंहगा पड़ता है.कोयला दूसरे जगह से मंगवाने के कारण लागत काफी मंहगा पड़ती है और समय पर उन्हें कोयला भी मुहैया नहीं हो पाता है.राजमहल परियोजना क्षेत्र के अलावा जिले के आसपास के लोगों के लिए भी वरदान है. यहां से अवैध ही तरीके से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है. वैसे इन मजदूरों के नाम पर राजनीति भी खूब होती है लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम इन लोगों के लिए उठाया नहीं गया है.एक कोयला मजदूर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है सिर्फ वोट के वक्त ही इन्हें हमारी याद आती है.जैसे चलता है, चलने देते हैं. जब पुलिस का दबाव बढ़ जाता है तो हम लोग भी अपना काम बंद कर देते हैं.सरकार को वास्तव में अगर हमारी चिंता है तो हमारे रोजगार के लिए कोई सार्थक कदम जरूर उठाती हम गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है. कोयला वैध हो या अवैध गरीबों की कमाई का सबसे अच्छा जरिया साबित हो रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

दशरथ मांझी के परिवार को नहीं मिला न्याय

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा हुई एक मजबूत वोट बैंक भुईयां और हाल के दिनों में इसके नेता के रूप में उभरे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की. ऐसी बात नहीं है कि इस चुनाव के पूर्व भुईयां जाति के लोग वोट बैंक नहीं थे. लेकिन बिहार की राजनीति में जब लालू-राबड़ी-नीतीश का शासन काल आया तो जातीय सम्मेलन भी खूब हुए और हर जाति ने अपनी-अपनी ताकत का एहसास राजनीतिक दलों को कराया. ऐसे जातीय सम्मेलन अतिपिछड़ा एवं दलित व महादलित वर्ग से आने वाले नेताओं ने कराये और राजनीतिक लाभ भी उठाया लेकिन पिछले एक साल में बिहार में महादलित वर्ग के वोटबैंक के बीच उभरे भुईयां वोट बैंक ने सभी राजनीतिक दलों को नाक में दम कर दिया. भुईयां जाति से आने वाले जीतनराम मांझी का मुख्यमंत्री बनाना और फिर हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गया. इस बार के विधानसभा चुनाव में भुईयां वोट बैंक ने नीतीश कुमार, लालू यादव के महागठबंधन को पानी पिला कर रख दिया. लेकिन इसी बिरादरी से जुड़े हुए दशरथ मांझी के परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है. अब दशरथ मांझी के परिवार को भी न्याय दिलाने में सरकार विफल हो रही है. दशरथ मांझी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेनमैन रिलिज होने के बाद खूब चर्चा हुई, खूब राजनीति हुई. लेकिन दशरथ मांझी के परिवार के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला. आज भी दशरथ मांझी के परिवार के दो दर्जन से अधिक सदस्यों को फूस की झोपड़ी में जीवन बसर करना पढ़ रहा है. सरकारी, गैर सरकारी, राजनीति तथा फिल्म से जुड़े लोगों से मिले आश्वासन तथा वादों के बीच गरीबी रेखा से नीचे मजदूरी कर पूरा परिवार जीवन बसर करने को मजबूर है.

इंदिरा आवास की बात तो छोड़ दीजिए. परवाना में मिली एक एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर भी सरकार दशरथ मांझी के परिवार को कब्जा नहीं दिला सकी है. 2007 में दशरथ मांझी की मौत पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया था. दशरथ मांझी की मौत के बाद बिहार सरकार ने 2009 में विकलांग पुत्र भागीरथ मांझी को गया जिले के अतरी प्रखण्ड के छिबरा मौजा में एक एकड़ 52 डिसमिल भूमि बन्दोबस्ती परवाना दिया गया था. लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल सका. इससे पूर्व सन् 2000 में भी दशरथ मांझी को करजनी गांव में 50 डिसमिल तथा पुत्र भागीरथ मांझी के नाम भी 50 डिसमील जमीन छिबरा मौजा में परवाना में जमीन दी गई. लेकिन आज तक इस भूमि पर भी कब्जा नहीं मिल सका. बताया तो यह जाता है कि सरकार ने विवादित भूमि को परवाना में दशरथ मांझी तथा उनके पुत्र भागीरथ को दिया है. जिसके कारण भूमि पर कब्जा नहीं हो पा रहा है. गेहलौर घाटी के आसपास के गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि विवादित भूमि को परवाना में दशरथ मांझी तथा इनके परिवार को देकर यहां के आपसी सौहार्द्र को बिगाड़ने का प्रयास किया गया. इसकी जांच होनी चाहिए. जिससे की ग्रामीणों के बीच आपसी सौहार्द्र भी ठीक रहे और दशरथ मांझी के परिवार के लोगों को ऐसी भूमि दिया जाय परवाना के रूप में जो विवादित नहीं हो. ज्ञात हो कि दशरथ मांझी ने 1960 से लेकर 1982 तक 22 वर्षों में गया जिले के अतरी प्रखण्ड के गेहलौर में 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी तथा 25 फीट उंची पहाड़ी को छेनी-हथौड़ी से तोड़ कर रास्ता बना दिया था. जिससे गेहलौर से वजीरगंज की दूरी आधी हो गई. इस बात की चर्चा में आने के बाद दशरथ मांझी को लोग माउंटेनमैन, पर्वत पुरुष आदि-आदि नामों से पुकारने लगे.

प्रसिद्ध फिल्मकार आमिर खान ने दशरथ मांझी पर 2014 में अपने चर्चित सिरियल सत्यमेव जयते की शूटिंग गहलौर घाटी में की थी. लेकिन इसका प्रसारण नहीं हो सका था. साथ ही आमिर खान ने दशरथ मांझी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी. लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की. प्रसिद्ध फिल्मकार केतन मेहता ने जब मांझी द माउंटेनमैन नामक फिल्म बनायी तो दशरथ मांझी की पुन: पूरे देश में चर्चा हुई. फिल्मों, डाक्यूमेंट्री के सहारे अनेकों लोगों को लाखों-करोड़ो की कमाई हुई. लेकिन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी तथा बेटी लौंगिया के 26 सदस्यों के परिवार की किस्मत नही बदली. आज भी किसी उद्धारक की तलाश में है माउंटेनमैन दशरथ मांझी का परिवार.■

झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी शुरू

झारखंड अलग होने के बाद राज्य में यह दूसरा पंचायत चुनाव है. 2010 में हुए पंचायत चुनाव को अगर हम देखें तो वह चुनाव जनता और प्रत्याशियों के लिए नया था. जनता और प्रत्याशी पंचायत के अधिकार से अंजान थे लेकिन इस बार का परिदृश्य बदल चुका है. लोग अब पंचायतीराज के बारे में भली-भांति जानने लगे हैं. पंचायती राज में होने वाले कार्यों को भी जानने लगे हैं. अगर झारखंड में देखा जाए तो पिछला पंचायती राज विकास कार्यों से अधिक घोटालों के लिए प्रसिद्ध रहा कई मुखिया पंचायत समिति प्रमुख समेत कई जनप्रतिनिधियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी.मनरेगा में लूट, इंदिरा आवास में धांधली, वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी समेत कई जनोपयोगी कार्य जो पंचायत स्तर पर होते हैं, उसमें लूट खसोट हुई और कई जनप्रतिनिधियों को लाल कोठी की हवा खानी पड़ी और कई अभी तक जेल में ही हैं.

दिवाकर तिवारी feedback@chauthiduniya.com

सत्ता के विकेन्द्रीकरण का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था इसमें पंचायत का बहुत अहम रोल था. देश के प्रत्येक नागरिक का समुचित विकास की परिकल्पना राष्ट्रपिता ने पंचायत के माध्यम से देखी थी, लेकिन क्या सचमुच पंचायतीराज के बाद लोगों का विकास हो पाया है? यह पंचायती राज पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है. ग्राम स्वराज्य का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वह वास्तविकता में संविधान के 73 वें संशोधन के बाद साकार हुआ, जिसमें पंचायत को बहुत अधिकार मिले. पंचायत को जब वित्तीय अधिकार ज्यादा मिले तब से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधीयों में भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया.

चुनाव कोई भी हो छोटा या बड़ा माहौल गहमागहमी का ही होता है.बिहार चुनाव के समाप्ति के साथ ही झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परवान पर चढ़ गया है. पंचायत चुनाव चार चरणों में होगा जिसमें पहले चरण का मतदान 22 नवंबर दूसरा चरण 28 नवंबर,तीसरा चरण 5 दिसंबर,तथा चौथा चरण 12 दिसंबर एवं मतगणना 19 दिसंबर को होगी. पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं.

झारखंड अलग होने के बाद राज्य में यह दूसरा पंचायत चुनाव है. 2010 में हुए पंचायत चुनाव को अगर हम देखें तो वह चुनाव जनता और प्रत्याशियों के लिए नया था. जनता और प्रत्याशी पंचायत के अधिकार से अंजान थे लेकिन इस बार का परिदृश्य बदल चुका है. लोग अब पंचायतीराज के बारे में भली-भांति जानने लगे हैं. पंचायती राज में होने वाले कार्यों को भी जानने लगे हैं. अगर झारखंड में देखा जाय तो पिछला पंचायती राज विकास कार्यों से अधिक घोटालों के लिए प्रसिद्ध रहा कई मुखिया पंचायत समिति प्रमुख समेत कई जनप्रतिनिधियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी.मनरेगा में लूट, इंदिरा आवास में धांधली, वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी समेत कई जनोपयोगी कार्य जो पंचायत स्तर पर होते हैं, उसमें लूट खसोट हुई और कई जनप्रतिनिधियों को लाल कोठी की हवा खानी पड़ी और कई अभी तक जेल में ही हैं. झारखंड के कुल 24 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव में कुल 17247830 मतदाता हैं, जिसमें 8973277 पुरुष, 8274552 महिला एवं 1 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. 24 जिलों मे कुल 4402 मुखिया, 5423 पंचायत समिति एवं 545 जिला परिषद का चुनाव होगा. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

पंचायत चुनाव मतलब गांव की सरकार बनाने के लिए प्रत्येक गांव मोहल्ले में एक जश्न सा माहौल है,चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर वोट की अपिल कर रहे हैं, एवं नामांकन में आने की गुजारिश कर रहे हैं.कहीं न कहीं वोटरों को लोकतंत्र में अपनी ताकत का एहसास हो रहा है.भले ही चुनाव जीतने के बाद माहौल बदल जाता है. जनप्रतिनिधि सर्वेसर्वा हो जाता है और जनता एक निरीह प्राणी और छोटे से छोटे काम के लिए जनप्रतिनिधि के घर का चक्कर लगाने को मजबूर होता है. पंचायत चुनाव के चलते गांव का माहौल भी बदला बदला नजर आता है गांव कई गुटों में बंटा हुआ नजर आता है.कोई इस गुट में तो कोई दूसरे गुट में नजर आता है कई लोग तो ऐसे हैं जो सभी गुट में अपना सामंजस्य बना लेते हैं.

पंचायत चुनाव में मुखिया के अलावा जिला परिषद, पंचायत समिति वार्ड सदस्य के पद पर भी चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है. कई पुराने जनप्रतिनिधि के अपने साथी भी इनके खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. वहीं कई पंचायतों का परिसीमन के तहत आरक्षण हो गया है जहां के पूर्व प्रतिनिधि अब दूसरे पद पर अपनी निगाहें जमाए बैठे हैं.

मुखिया बनने की चाहत है सबकी

पंचायत चुनाव में अगर देखा जाय तो मुखिया का महत्व सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक ताकतवर मुखिया को माना जाता है. वित्तीय मामले में भी मुखिया को सबसे अधिक राशि आवंटित की जाती है, तथा किसी भी योजना का चेक काटने का अधिकार इन्हीं को होता है.जिसके चलते सबकी पहली चाहत मुखिया बनने की होती है.पिछले चुनाव में वार्ड सदस्य का चुनाव जीते प्रतिनिधि से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद के भी कुछ सदस्य अपनी किस्मत इस बार मुखिया के पद पर आजमाना चाह रहे हैं. पंचायत में सबसे अधिक मलाईदर पोस्ट मुखिया की होती है इसलिए सबकी निगाह मुखिया के पद पर है.

पंचायत चुनाव में मुखिया के अलावे जिला परिषद, पंचायत समिति वार्ड सदस्य के पद पर भी चुनाव लड़ने वालों कि कमी नहीं है. कई पुराने जनप्रतिनिधि के अपने साथी भी इनके खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. वहीं कई पंचायतों का परिसीमन के तहत आरक्षण हो गया है जहां के पूर्व प्रतिनिधि अब दूसरे पद पर अपनी निगाहें जमाए बैठे हैं.

झारखंड में देखा जाय तो विकास के नाम पर सिर्फ लूट तंत्र हावी रहा है.जो जिस पद पर रहा है उसने लूटने का ही कार्य किया किसी ने विकास कि बात नहीं सोची.जिस प्रकार इस राज्य का विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है.बिहार से अलग होने के बाद जब झारखंड राज्य बना तब लोगों में यह उम्मीद जगी कि अब इस राज्य का तथा यहां के लोगों का विकास होगा लेकिन हुआ इसके विपरीत विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ यहां के मंत्री और विधायकों का. गांव की सरकार बनने के बाद ग्रामीण इलाकों में विकास की रोशनी फिर से दिखाई दी लेकन यहां भी जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ लूट ही मचा रखी थी. पिछले चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों ने तो सारी हदें ही पार कर दी. मृत व्यक्ति को इंदिरा आवास,मृत व्यक्ति मनरेगा के मजदूर, इंदिरा आवास में जमकर धांधली जैसी कागजी उलटफेर की गई.

पंचायत चुनाव में राजनीति भी खूब हावी है. एक ही राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता भी चुनाव मैदान में उतरने को बेताब हैं, जिसके चलते लोगों में उहापोह की स्थिति है. कुल मिलाकर देखा जाय तो गांव की सरकार बनाने में भी खूब गर्मागर्मी है. प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. चुनावी अधिसूचना के बाद ही मतदाताओं के लिए उत्सव सा माहौल हो गया. जमकर भोज चल रहा है. कहीं पनीर की खुश्बू तो कहीं मछली तली जा रही है.खाने खिलाने के साथ ही पिलाने का दौर भी खूब चल रहा है. सबका सिर्फ एक ही मकसद है चुनाव जीतना. इसके लिए सब प्रत्याशी कोई भी हथकंडा अपनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं.

लोकतंत्र के इस पर्व में जीत या हार सब जनता जर्नादन के हाथ में है. किसे वो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और गांव में किसकी सरकार बनवाते हैं.फिर एक बार जनता के हाथों में सत्ता की चाबी है. देखना यह है कि जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है और किसको जितवा कर इस बार अपनी पंचायत का प्रतिनिधि बनाती है. इसका फैसला 19 दिसम्बर को होगा. बहरहाल झारखंड में चुनाव का माहौल है जिसके रंग में सब रंगे हुए हैं.■

धनबाद में नामांकन की गति धीमी

शैलेंद्र कुमार feedback@chauthiduniya.com

झारखण्ड पंचायत चुनाव 2015 का चुनावी बिगुल बज चुका है. चुनाव को लेकर शह और मात का खेल प्रत्याशियों में बिछ चुका है. इस बार झारखण्ड में मुखिया के बढ़े वित्तीय अधिकार एवं प्रशासनिक अधिकार के कारण लोगों में उत्सुकता तो है पर इसके बावजूद भी प्रथम चरण में होने वाले चुनाव में नामाकंन को लेकर भागीदारी कम हो रही है. ऐसा जिला पंचायत राज पदाधिकारी शेखर वर्मा के वक्तव्य से लगता है. उनका कहना है कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए कम से कम 640 उम्मीदवार होना चाहिए लेकिन 307 ने ही नामांकन किया है. हालांकि इनका ये भी कहना है तीन चरणों में चुनाव होना है. हो सकता है कि भागीदारी बढ़े इस बार पुलिस प्रशासन अधिकारी दागी लोगों पर खास नजर रखे हुए हैं. धनबाद एसपी राकेश बंसल ने उपायुक्त कार्यालय प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 1665 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है. 42 हथियार जमा कराए गए हैं. 403 वारंट का तामिला कराया गया है. हथियारों में एक पिस्टल पांच कारतूस व काफी मात्रा में शराब जब्त की गई. गया.पंचायती राज अधिनियम के तहत 85 लोगों को आयोग्य घोषित किया गया है, जो तीन साल तक चुनाव नही लड़ पाएंगे. प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है. चुनाव 22 नवम्बर को होना है जिसमे तोपचाची, टुण्डी, पूर्वी टुण्डी हैं. मतदाताओं ने इस बार खुलकर वैसे लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया है जिसमें वादा तो विकास का किया था मगर किया कुछ भी नहीं. आज भी गांव में मूलभूत समस्या जस का तस है गांव में पिने का पानी, नाली, स्वास्थ एवं जनवितरन प्रणाली की समस्या जस का तस है. गांव की सड़कों की हालत भी खास्ता है वैसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाने के लिए नए चेहरे की तलाश में जुट गए हैं. पहले दिन के नामांकन में टुण्डी एवं पुर्वी टुण्डी में मुखिया पद के लिए किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जबकि वार्ड सदस्य के लिए कुल नौ नामांकन दाखिल किया गया वही तोपचाची प्रखण्ड में चार मुखिया वा चौदह वार्ड सदस्यों ने नामांकन किया है.

दूसरे दिन टुण्डी प्रखण्ड में मुखिया पद के लिए 17 पंचायतों में 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया एवं वार्ड सदस्यों के लिए 71 लोगों ने नामांकन किया.

धनबाद एसपी राकेश बंसल ने उपायुक्त कार्यालय में हुई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 1665 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कारवाई की गई है. 42 हथियार जमा कराए गए हैं. 403 वारंट का तामिला कराया गया है. एक पिस्टल, पांच कारतूस व काफी मात्रा में शराब जब्त की गई.पंचायती राज अधिनियम के तहत 85 लोगों को आयोग्य घोषित किया गया है जो तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

वहीं तोंपचाची में 68 मुखिया वा 101 वार्ड सदस्यों नामांकन किया. पूर्वी टुण्डी में मुखिया पद के आठ एवं बीस ने वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन किया तीसरे दिन तोंपचाची में 75 मुखिया वा 180 ने वार्ड सदस्य के लिए नामांकन किया. टुण्डी में 36 मुखिया एवं 121 लोगों ने वार्ड सदस्य के लिए नामांकन किया जबकि पूर्वी टुण्डी में मुखिया पद के लिए 16 एवं वार्ड सदस्य के लिए 76 लोगों ने नामांकन किया चौथे दिन तोपचांची में मुखिया पद के लिए 93 एवं वार्ड सदस्यों के लिए 225 ने नामांकन किया वहीं पूर्वी टुण्डी में मुखिया के 36 व वार्ड सदस्य के लिए 97 ने नामांकन किया टुण्डी में 20 मुखिया एवं वार्ड सदस्य के लिए चार लोगों ने नामांकन किया. पांचवें दिन तोपचांची में मुखिया के लिए 29 व वार्ड सदस्य के लिए 719 लोगों ने नामांकन किया. टुण्डी में नामांकन के अंतिम दिन 18 लोगों ने मुखिया वा 118 ने वार्ड सदस्य के लिए नामांकन किया वहीं पूर्वी टुण्डी में मुखिया के लिए 82 वा वार्ड सदस्यों के लिए 245 ने नामांकन किया कुल मिलाकर लगभग दो हजार से उपर प्रत्याशियों विभिन्न पदों के लिए पर्चा दाखिल किया. प्रथम चरण चुनाव में मुखिया के लिए 466 वा वार्ड सदस्यों के लिए 1456 एवं पंसस के लिए 307 लोगों ने नामांकन किया है. तीनों प्रखण्डों में स्कूटनी के दौरान लगभग 1376 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं अब देखना है कि गांव की सरकार किन लोगों के हाथ लगती है.■

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलबर्गा:9343834519

सैड सैंडे को चम्पारण ने बनाया भाजपा के लिए फील गुड

चंपारण

विधानसभावार चुनावी जीत–हार को देखें तों स्थितियां स्पष्ट हो जायेंगी. रक्सौल में भाजपा के डॉ. अजय कुमार सिंह पांचवी बार चुनाव जीते हैं. उन्होंने भाजपा के सुरेश कुमार यादव को 2961 मतों से पराजित किया. गौर करें तो नरकटिया के निवर्तमान विधायक श्यामबिहारी सिंह जदयू से टिकट नहीं मिलने पर बागी बनकर रक्सौल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खडे थे. आदापुर क्षेत्र में मजबूत पकड़ के कारण उन्होंने राजद के वोट बैक में अच्छी सेंधमारी की और 21,697 मत झटक लिये. जबकि अजय कुमार सिंह को 64,731 मत और राजद के सुरेश कुमार को 61,562 मत मिले हैं. चुनावी गुरूओं की मानें तो अगर श्यामबिहारी प्रसाद बागी नहीं होते तो राजद की जीत सुनिश्चित थी. वहीं सुगौली विस में भाजपा के रामचन्द्र सहनी ने 6700 मतों से राजद के ओमप्रकाश सहनी को हराया. ज्ञात हो कि जदयू नेता ई शशि भूषण सिंह टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े थे और उन्होंने महागठबंधन के ज्यादा मतों को प्रभावित किया.

राकेश कुमार

एनडीए गठबंधन के सैड संडे को पूर्वी चम्पारण के विधान सभा चुनाव के नतीजों ने फील गुड में बदल दिया. जिले के बारह विधान सभा सीटों में से एनडीए गठबंधन ने आठ सीटों पर कब्जा जमा लिया. जबकि महागठबंधन को मात्र चार सीटों से संतोष करना पड़ा. एनडीए के आठ सीटों में सात सीट भाजपा के पक्ष में गया तो एक सीट पर लोजपा ने बाजी मारी. 2010 के विधान सभा चुनाव के मुकाबले भाजपा को एक सीट का इजाफा मिला है या यूं कहें कि भाजपा के पराजय के जख्म पर यह मरहम का काम किया है. इधर इस जीत का बडा श्रेय स्थानीय भाजपा सांसद और केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को दिया जा रहा है. चम्पारण की ये सीटें श्री सिंह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुईं थीं.

चम्पारण में भी कमोवेश बिहार के अन्य जिलों जैसी हीं स्थिति थी परन्तु बागियों ने महागठबंधन को काफी प्रभावित किया. भाजपा ने 10 रक्सौल,11 सुगौली, 16 कल्याणपूर, 17 पिपरा, 18 मधुबन, 19 मोतिहारी, 20 चिरैया सीटों पर तो राजग के घटक दल लोजपा ने 14 गोविन्दगंज सीट पर विजय पताका लहराई. महागठबंधन ने सात सीटों पर राजद और तीन सीट पर जदयू के प्रत्याशी को खड़ा किया था. इनमें राजद 12 नरकटिया,13 हरसिद्धि, 15 केशरिया और 21 ढाका सीट पर कब्जा जमाने में सफल हो सकी. जदयू एक भी सीट बचाने में सफल नहीं रही.

विधान सभावार चुनाव के जीत हार को देखें तों स्थितियां स्पष्ट हो जायेंगी. रक्सौल में भाजपा के डॉ. अजय कुमार सिंह पांचवी बार चुनाव जीते हैं. उन्होंने भाजपा के सुरेश कुमार यादव को 2961 मतों से पराजित किया. गौर करें तो नरकटिया के निवर्तमान विधायक श्यामबिहारी सिंह जदयू से टिकट नहीं मिलने पर बागी बनकर रक्सौल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े थे. आदापुर क्षेत्र में मजबूत पकड़ के कारण उन्होंने राजद के वोट बैक में अच्छी सेंधमारी की और 21,697 मत झटक लिये. जबकि अजय कुमार सिंह को 64,731 मत और राजद के सुरेश कुमार को 61,562 मत मिले हैं. चुनावी गुरुओं की मानें तो अगर श्यामबिहारी प्रसाद बागी नहीं होते तो राजद की जीत सुनिश्चित थी. वहीं सुगौली विस में भाजपा के रामचन्द्र सहनी ने 6700 मतों से राजद के ओमप्रकाश सहनी को हराया. ज्ञात हो कि जदयू नेता ई शशि भूषण सिंह टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े थे और उन्होंने महागठबंधन के ज्यादा मतों कों प्रभावित किया. नरकटिया विस सीट पर सीधी टक्कर में राजद के डॉ. शमीम अहमद ने 19,982 मतों से रालोसपा के संत सिंह कुशवाहा को हराया. डॉ. शमीम को 75,118 और श्री कुशवाहा को 55,136 मत मिले. यह सीट पूर्व से ही राजद का माना जा रहा था क्योंकि रालोसपा प्रत्याशी को काफी कमजोर माना जा रहा थी. श्री कुशवाहा रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के समधी बताये जाते हैं और इसी के कारण उन्हें टिकट दिया गया था. हरसिद्धि विस से राजद के राजेन्द्र राम ने निवर्तमान विधायक कृष्णनन्दन पासवान को 8,800 मतों से पराजित किया. श्री राम को 74,759 मत मिले जबकि श्री पासवान को 64,692 मत मिले. श्री राम को जमीनी नेता माना जाता है. आज जहां चुनाव के लिए धनबल को एक मुख्य घटक माना जाता है वहीं श्री राम बेहद गरीब परिवार से आते हैं. निवर्तमान विधायक कृष्णनन्दन पासवान के प्रति लोगों का असंतोष और श्री राम के जमीनी होने का प्रतिफल है श्री राम की जीत. गोविन्दगंज से लोजपा के राजू तिवारी ने काग्रेस के ब्रजेश कुमार पाण्डेय को पराजित किया. श्री तिवारी को 74,691 और श्री पाण्डेय को 46,765 मत मिले. केसरिया से राजद के डॉ. राजेश कुमार ने 62,902 मत लाकर भाजपा के राजेन्द्र गुप्ता को पराजित किया. श्री गुप्ता को 46,955 मत मिले. पीपरा में भाजपा के श्याम बाबू राय 65,552 मत लेकर जदयू के कृष्ण चन्द्र को हराया. कृष्णचन्द्र को 61,622 मत मिले. मधुबन में भाजपा के राणा रणधीर सिंह विजयी रहे. उन्हें 61,054 मत मिले. वहीं जदयू के निवर्तमान विधायक शिवजी राय 44,832 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे. मोतिहारी में निवर्तमान भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने 79,987 मत लेकर राजद के विनोद कुमार श्रीवास्तव को हराया. श्री श्रीवास्तव को 61,430 मत मिले. चिरैया में भाजपा के लालबाबू गुप्ता विजयी रहें. इन्हें 62,831 मत मिले. इन्होंने राजद के लक्ष्मी नारायण यादव को हराया. श्री यादव को58,457 मत मिले. वहीं ढाका में राजद के फैसल रहमान ने भाजपा के पवन जायसवाल को हराया. फैसल को 87,458 मिले जबकि लक्ष्मी नारायण यादव को 58,457 मतों से संतोष करना पड़ा.■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वी चंपारण में फिर फहराया भगवा

संजय कुमार सिंह

चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधान सभा चुनाव के सफल संचालन के बाद पश्चिम चंपारण की कुल नौ सीटों में से एनडीए गठबंधन को पांच सीट मिली. सभी पांच सीट पर भाजपा के प्रत्याशियों ने बाजी मारी. इस बार के चुनाव में कुल नौ सीट में आठ सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था. वहीं वाल्मीकि नगर की एक सीट रालोसपा के खाते में गयी थी. लेकिन वाल्मीकि नगर सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया. महागठबंधन को तीन सीटों पर संतोष करना पड़ा. यहां से कांग्रेस को चार सीटें मिली थीं. जिसमें से दो सीट पर से पार्टी को विजय नसीब हुआ. जदयू को भी चार सीट मिली थी लेकिन सिकटा छोड़ उसके सभी प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा. लौरिया की एक सीट राजद को मिला, जहां से उसके उम्मीदवार रण कौशल प्रसाद सिंह को भाजपा उम्मीदवार से पराजय मिली. हालांकि मतगणना में दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखी. भाजपा ने बगहा, रामनगर, चनपटिया, नौतन व लौरिया सीट पर कब्जा जमाया वहीं महागठबंधन से कांग्रेस ने नरकटियागंज, व जिला मुख्यालय की बेतिया सीट पर अपना परचम लहराया. जदयू ने सिकटा सीट पर अपना परचम लहराया. इस बार के चुनाव में खास बात यह रही कि भाजपा ने जदयू के कब्जे वाली नौतन व बगहा सीट पर अपना परचम लहराया. वहीं कांग्रेस ने भाजपा की बेतिया व नरकटियागंज सीट पर कब्जा जमाया. वाल्मीकि नगर सीट रालोसपा के खाते में जाने के कारण भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बाजी मारी.

इस चुनाव में मोदी मैजिक असर नहीं दिखा. जिले की सभी विधान सभा सीटों पर मोदी मैजिक बिल्कुल बेअसर नजर आया. जानकार की माने तो भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाता नेताओं के विगत पांच साल के क्रिया कलाप से संतुष्ट नजर नहीं आये. जिसका खामियाजा भी कई सीट पर नजर आया. लेकिन उम्मीदवार नाराज वोट को मनाने की बजाये लोकसभा चुनाव की तरह मोदी मैजिक के भरोसे आस लगाये रहे. जिसके कारण जिस वोट बैंक पर भाजपा को भरोसा था वह मतदाता उदासीन नजर आया. जो भाजपा को समर्थन वाले मतदाताओं के कम वोटिंग ने परिलक्षित कर दिया था. ऐसे नाराज मतदाताओं की उपेक्षा एनडीए को भारी पड़ी.

जीत के बाद मना जश्न

चुनाव परिणाम के बाद सबसे अधिक उत्साह महागठबंधन खेमे में नजर आया.

सीट	जीते	हारे
वाल्मीकि नगर	धीरेंद्र प्रताप सिंह (निर्दलीय)	सुरेंद्र कुशवाहा (रालोसपा)
बगहा	राघव शरण पांडेय (भाजपा)	भीष्म सहनी (जदयू)
रामनगर	भागरथी देवी (भाजपा)	पूर्णमासी राम (कांग्रेस)
नरकटियागंज	विनय वर्मा (कांग्रेस)	रेणु देवी (भाजपा)
चनपटिया	प्रकाश राय (भाजपा)	डा. एन. एन. शाही (जदयू)
सिकटा	फिरोज अहमद (जदयू)	दिलीप वर्मा (भाजपा)
बेतिया	मदन मोहन तिवारी (कांग्रेस)	रेणु देवी (भाजपा)
नौतन	नारायण प्रसाद (भाजपा)	बैद्यनाथ प्रसाद महतो
लौरिया	विनय बिहारी (भाजपा)	रण कौशल प्रसाद सिंह

युवा एवं महिलाओं ने दिया महागठबंधन का साथ

बिहार विधान सभा चुनाव में महिलाओं के बढ़े वोट प्रतिशत व युवा वर्ग ने एनडीए से मुंह मोड़ लिया. महिलाओं को नौकरी व अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार से मिला पचास प्रतिशत आरक्षण ने कमाल दिखाया. साथ ही केंद्रीय नौकरियों तत्काल भर्ती रोके जाने की बात ने नौकरी के लिये भागदौड़ कर रहे युवाओं को भी एनडीए से दूर कर दिया. जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा.

अकलियतों के वोट का बढ़ा प्रतिशत

बिहार चुनाव में जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की कोशिश हुई. इसके कारण एक तबके के मतदाताओं ने कम तवज्जो दी जबकि अकलियत ने इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए बंपर मतदान किया. जिसका असर चुनाव परिणाम में साफ परिलक्षित हुआ. जिसके कारण महागठबंधन की जीत नजर आयी.

भाजपा का बूथ मैनेजमेंट दिखा शिथिल

भाजपा ने वोटर को घर से निकाल कर वोट देने के लिये उत्प्रेरित करने के लिये हर बूथ पर दस लोगों की बूथ कमेटी बनायी थी. बूथ कमेटी की निगरानी व सहयोग के लिये भी भारी भरकम कमेटी का निर्माण का गठन किया गया था. जो हकीकत में नहीं बल्कि कागजों में रह गयी. उसका वजूद धरातल पर नजर नहीं आया. भाजपा नेताओं ने यह मान लिया कि वर्ष 2010 के विधान सभा चुनाव एंव वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जो बूथ कमेटी बनी थी, वह आज भी कारगर है. जबकि इसका कोई फायदा पार्टी को नहीं मिला.■

मगध में महागठबंधन की जय-जय

सुनील सौरभ

इतिहास गवाह है कि मगध में जिस गठबंधन या पार्टी की बढ़त रहती है, सत्ता पर वही काबिज भी होता है. हुआ भी ऐसा ही! इस बार मगध में एनडीए जहां छह सीट में ही सिमट गयी, तो वहीं महागठबंधन ने 20 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर इतिहास को दुहरा दिया.

मगध के पांच जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के राजद ने नौ, जदयू ने सात एवं कांग्रेस ने चार सीट पर जीत हासिल की, जबकि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने चार, हम ने एक एवं रालोसपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की. भाजपा व राजद ने अपनी परंपरागत सीट क्रमश: गया शहर एवं बेलागंज में अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि राजनीति में ऊंची पहुंच रखने वाले जगदीश शर्मा के परिवार का एकछत्र राज का दंभ भी घोसी में टूट गया. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जहां एक सीट पर जीते, तो एक से हार भी गये. जहानाबाद में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सांसद हैं, लेकिन गठबंधन का एक भी प्रत्याशी यहां से जीत नहीं पाया. यहां तो मांझी का महादलित फैक्टर भी फेल हो गया. खुद, हम के अध्यक्ष यहां से हार गये. मगध में सबसे बड़ी हार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की हुई. हम के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से वो परास्त हो गये.

एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के लिए सबसे दुखद यह रहा कि 2010 में जब जदयू के साथ गठबंधन था, तो आठ सीट पर इनके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मात्र चार पर जीत हुई, जिनमें तीन पुरानी सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी, जबकि एक वारसलीगंज से अरुणा देवी ने जदयू से सीट छीनी. महागठबंधन में सबसे अधिक फायदे में राजद व कांग्रेस पार्टी रही. राजद के नौ प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा, जबकि पिछले चुनाव में इनका मात्र एक विधायक था. कांग्रेस का तो यहां से खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार चार ने वैतरणी पार कर ली. जदयू का यहां से 16 विधायक थे, लेकिन इस बार विधायकों की संख्या गठबंधन धर्म के कारण कम हो गयी.गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में से सात पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की, जिनमें राजद के डा. सुरेन्द्र प्रसाद यादव (बेलागंज), कुमार सर्वजीत (बोधगया), कुंती देवी (अतरी) व समता देवी (बाराचट्टी), कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह (वजीरगंज) जदयू के अभय कुशवाहा (टिकारी) व डॉ. विनोद प्रसाद यादव (शेरघाटी) शामिल हैं. अभय कुशवाहा पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और जीत दर्ज की. एनडीए ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें भाजपा के डॉ. प्रेम कुमार (गया शहर), राजीव रंजन दांगी (गुरुआ) तथा हम के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (इमामगंज) शामिल हैं. गुरुआ से सीटिंग विधायक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा को बेटिकट कर भाजपा ने राजीव रंजन दांगी को मैदान में उतार कर रिस्क तो लिया, लेकिन राजीव पहली बार में ही जीत हासिल कर गये. जहानाबाद व अरवल जिले की पांच सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई है. यहां एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल सका. जहानाबाद के राजद के मुंद्रिका यादव (जहानाबाद) व सूबेदार दास (मखदुमपुर), जदयू के कृष्णनंदन वर्मा (घोसी) एवं अरवल से राजद के रवीन्द्र सिंह (अरवल) व जदयू के सत्यदेव कुशवाहा (कुर्था) शामिल हैं. नवादा जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में तीन पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की.

जीतन राम मांझी

डॉ प्रेम कुमार

सुरेंद्र यादव

राजद के प्रकाशवीर (रजौली) राजवल्लभ प्रसाद (नवादा) तथा कांग्रेस की पूर्णिमा देवी (गोविन्दपुर) ने जीत दर्ज की, जबकि गठबंधन से भाजपा की अरुणा देवी (वारसलीगंज) व अनिल सिंह (हिसुआ) ने जीत का स्वाद चखा. पिछली मर्तबा नवादा जिले के दो अलग–अलग विधानसभा क्षेत्र से पति–पत्नी विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार पति कौशल यादव को जनता ने नकार दिया, तो पत्नी पूर्णिमा देवी को सिर आंखों पर बिठाया. औरंगाबाद के छह में पांच सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की. कांग्रेस के आनंद शंकर (औरंगाबाद) व राजेश कुमार (कुटुम्बा), जदयू के वीरेन्द्र सिंह (नवीनगर), अशोक सिंह (रफीगंज) शामिल हैं, जबकि एनडीए के घटक दल रालोसपा के चन्द्रभूषण वर्मा ने ओबरा और व रणविजय कुमार (गोह) से जीत दर्ज की है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

16 नवंबर–22 नवंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

शाहजहांपुर और बाराबंकी के बाद राजधानी लखनऊ में दिखा पुलिस का खौफनाक चेहरा

वरिष्ठ पत्रकार को थाने में ही मार डाला!

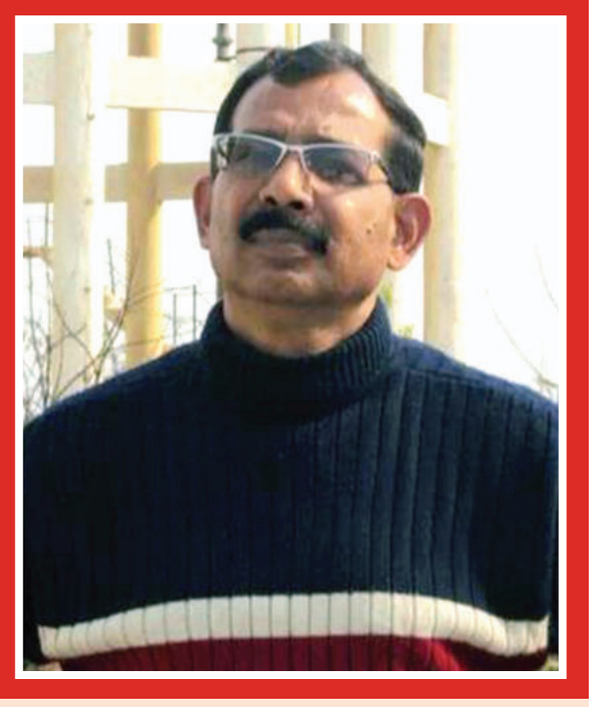

प्रभात रंजन दीन

शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह को जला कर मार डाला गया. बाराबंकी में पत्रकार संतोष त्रिवेदी की मां के साथ थाने में दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम होने पर उसे जिंदा फूंक दिया गया. अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजधानी लखनऊ में एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव चतुर्वेदी की थाने में ही हत्या कर दी. जगेंद्र की हत्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का नाम आया था. राजीव चतुर्वेदी की हत्या के षडयंत्र में भी सरकार के एक विवादास्पद मंत्री का नाम आ रहा है. मौत के सियासी एंगल को देखकर खजाना खोलने और संजीदगी का प्रहसन खेलने वाली उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों की मौत पर संदेहास्पद चुप्पी साधे है, संवेदना के एक शब्द भी बाहर नहीं आए. राजीव की मौत पर भी सरकार का यही अमानवीय रवैया रहा और तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया की खाल का भी यही हाल है. तीन नवंबर को लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में वरिष्ठ पत्रकार राजीव चतुर्वेदी को जिस तरह मारा गया और पुलिस ने जिस तरह की आपराधिक हरकतें कीं, उसने सत्ता व्यवस्था के खिलाफ आम लोगों में नफरत की भावना को और गहरा किया है. पुलिस ने पहले कहा कि पत्रकार पर किसी से पैसे वसूलने के आरोप थे इसीलिए पूछताछ के लिए उन्हें थाने बुलाया गया था. लेकिन मौत देने वाले पूछताछ के तौर-तरीके पर सवाल उठने पर पुलिस ने फौरन पैंतरा बदला और कहा कि पत्रकार राजीव चतुर्वेदी थाने के पिछवाड़े बेहोश पाए गए थे. पुलिस के कथन की निर्लज्जता देखिए कि अगर राजीव बेहोशी की हालत में भी पड़े मिले, तो उन्हें शहर के मुख्य अस्पताल न ले जाकर सरोजनी नगर के जघन्य हालत वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों ले जाया गया? पुलिस ने थाने के बाहर इंतजार कर रहे ड्राइवर सलाही यादव को इस बारे में सूचना देने की भी जरूरत नहीं समझी. देर होने पर सलाही ने राजीव के फोन पर कॉल किया, तो फोन बंद मिला. सलाही ने फिर राजीव के परिचित को फोन कर थाने बुलाया. थाने पर बताया गया कि राजीव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सरोजनी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने पर वहां राजीव की लाश पड़ी मिली. इसके बाद ही राजीव चतुर्वेदी की मौत के बारे में लोगों को पता चला. खबर मिलते ही सरोजनी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे सांसद कौशल किशोर ने राजीव चतुर्वेदी की मौत को लेकर पुलिस के संदेहास्पद आचरण पर गंभीर सवाल उठाए और इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग की. कौशल किशोर ने कहा कि राजीव चतुर्वेदी की थाने में की गई हत्या सुनियोजित साजिश के तहत हुई, जिसमें सत्ताधारी दल के कुछ खास नेताओं और पुलिस के जुड़े होने की आशंका है, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई ही कर सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं कर सकती.

एक धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने राजीव चतुर्वेदी को पूछताछ के लिए बिना किसी सम्मन के सरोजनी नगर थाने पर बुलाया था. सरोजनी नगर पुलिस के ही एक कर्मचारी ने कहा कि थाने के स्टेशन अफसर सुधीर कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों ने राजीव चतुर्वेदी को काफी मारा, बेल्ट-जूते उतरवा कर थाने में घसीटा और उसी हालत में लॉकअप में बंद कर दिया. इससे राजीव की थाने के लॉकअप में ही मौत हो गई. पुलिस को पता था कि राजीव का ड्राइवर थाने के बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए पुलिस राजीव की लाश लेकर थाने के पिछले दरवाजे से भागी और उसे सरोजनी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया, जबकि पुलिस को सिविल अस्पताल या केजीएमयू ले जाना चाहिए था. इस हरकत से राजीव की मौत में पुलिस का संदेहास्पद रोल सामने आ गया. पुलिस ने पहले कहा कि थाने में राजीव को जबरदस्त हार्ट-अटैक हुआ और जैसे ही पुलिस उन्हें अस्पताल पहुंचाती, राजीव की मौत हो गई. पुलिस थाने के पिछले दरवाजे से उन्हें क्यों लेकर गई? या ऐसी हालत में उन्हें सिविल अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? इन सवालों का जवाब पुलिस अधिकारियों के पास नहीं है. बाद में पुलिस ने फिर बयान बदला और कहा कि राजीव थाने के पीछे बेहोश पाए गए थे, जबकि राजीव के ड्राइवर सलाही ने सांसद कौशल किशोर के समक्ष भी यह बयान दिया कि वह राजीव को लेकर थाने आया था और थोड़ी देर में वापस आने की बात कह कर राजीव थाने के अंदर दाखिल हुए थे.

वरिष्ठ पत्रकार राजीव चतुर्वेदी की मौत को लेकर शासन और पुलिस की बेशर्मी का हाल यह रहा कि उनकी लाश के पोस्टमॉर्टम की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी. पुलिस बिना पोस्टमॉर्टम के ही मामला निपटाना चाहती थी, लेकिन पत्रकारों के दबाव पर चार नवंबर को दोपहर बाद पोस्टमॉर्टम की औपचारिकता निभाई गई. राजीव के गले और सिर पर पीछे से वार किए जाने के गहरे निशान पाए गए, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. इटावा के रहने वाले राजीव चतुर्वेदी जिले के ख्यातिनाम वकील धर्मप्रकाश चतुर्वेदी के पुत्र थे. उनके भाई डॉ. संजय चतुर्वेदी दिल्ली में पेशे से डॉक्टर हैं और रुचि से कवि-साहित्यकार हैं. राजीव चतुर्वेदी खुद वकील, पत्रकार, प्रखर वक्ता और व्यवसायी थे.

घटना के बारे में छानबीन करने पर पता चला कि कुछ दिन पहले राजीव चतुर्वेदी के खिलाफ बागपत निवासी बिहारी लाल गुप्ता ने शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया था. गुप्ता ने सरोजनी नगर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. तीन दिन पहले सरोजनी नगर थाने के एसओ ने राजीव को फोन कर पूछताछ के लिए थाने बुलाया था. मंगलवार तीन नवंबर की दोपहर ढाई बजे राजीव अपने ड्राइवर सलाही के साथ कार से सरोजनी नगर थाने पहुंचे, वहां उन्होंने ड्राइवर को बाहर इंतजार करने को कहा और थाने के अंदर चले गए. करीब दो घंटे बीत जाने के बाद भी जब राजीव थाने से बाहर नहीं निकले तब ड्राइवर ने उन्हें फोन किया, तो मोबाइल बंद मिला. ड्राइवर ने राजीव को जानने वाली सरिता सिंह को फोन मिलाया. सरिता ने अपने बेटे को थाने भेजा, जहां उसे बताया गया कि राजीव को सरोजनी नगर अस्पताल ले जाया गया है. यह सुनकर सबके होश उड़ गए. अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि राजीव की मौत हो चुकी थी. ड्राइवर ने बताया कि राजीव के शरीर से जूते गायब थे, बेल्ट गायब थी और मोजे में मिट्टी लगी हुई थी. डॉक्टरों का भी कहना है कि जब पुलिस ने राजीव को भर्ती कराया था, उसी समय उनकी मौत हो चुकी थी. एसओ सुधीर कुमार ने बाद में कहा कि वह राजीव को जानते तक नहीं और पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया था. इतना ही नहीं एसओ बार-बार यही कहते रहे कि सड़क पर गिरकर राजीव को चोट लगी थी. वरिष्ठ पत्रकार राजीव चतुर्वेदी की मौत पर लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय ने कहा कि राजीव चतुर्वेदी की मृत्यु के संबंध में एसपी क्राइम ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी को जांच सौंप दी गई है. मामला बहुत संगीन है. एसपी क्राइम पूरी जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे. इसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

पत्रकार की हत्या में किसका हाथ!

शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. राजीव चतुर्वेदी की हत्या में प्रदेश सरकार के धन-सम्पन्न विभाग के भ्रष्ट (आरोपित) मंत्री का नाम सुगबुगाहटों में है, लेकिन आधिकारिक तौर पर मंत्री का नाम उजागर नहीं हुआ है. पत्रकारों का भी कहना है कि सीबीआई जैसी केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जांच होगी तभी मंत्री का नाम खुल सकता है, अन्यथा प्रदेश सरकार उस मंत्री की जिस तरह लगातार हिफाजत करती आ रही है, वैसे ही करती रहेगी. जगेंद्र को जला कर मार डालने की घटना के कुछ ही दिनों बाद बाराबंकी के पत्रकार संतोष त्रिवेदी की मां के साथ कोठी थाने में थाना प्रभारी और एक अन्य दारोगा ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर महिला पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया. इस मामले में भी सरकार ने कोई मानवीय सुगबुगाहट नहीं दिखाई. फिर उत्तर प्रदेश के चंदौली के धीना क्षेत्र में टेलीविजन पत्रकार हेमंत यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई. इसी तरह बरेली जिले में एक स्थानीय दैनिक के पत्रकार संजय पाठक की हत्या कर दी गई. यूपी में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं लगातार जारी हैं, लेकिन नेता अखबारों में केवल अपना नाम और फोटो छपवाना जानते हैं, पत्रकारों की हिफाजत से उन्हें कोई लेना-देना नहीं. पत्रकारों की पिटाई, मोटर साइकिल से बांध कर घसीटे जाने, सार्वजनिक तौर पर अपमानित किए जाने जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. यहां तक कि अमेरिका का एक मीडिया निगरानी निकाय भी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्याओं पर अपना क्षोभ जाहिर कर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. अमेरिकी संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' (सीपीजे) के एशियाई कोऑर्डिनेटर बॉब डाइज ने पत्रकारों की हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी और इस बात पर क्षोभ जताया था कि पत्रकारों की हत्या के मामले बिना किसी कानूनी नतीजे के ठंडे बस्ते में चले जाते हैं. सीपीजे के वर्ष 2015-इम्प्यूनिटी इन्डेक्स में भारत का 14वां स्थान है. इस सूची में वह देश शामिल हैं जहां पत्रकारों की हत्या की जाती है और हत्यारे आजाद घूमते रहते हैं. ■

पत्रकार संगठनों में उबाल

वरिष्ठ पत्रकार राजीव चतुर्वेदी की सरोजनी नगर थाने में हुई संदेहास्पद मौत की जांच व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का प्रतिनिधिमंडल चार नवंबर को गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा से मिला. समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राजीव चतुर्वेदी की संदिग्ध मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. समिति ने राजीव चतुर्वेदी को प्रताड़ित करने वाले सरोजनी नगर थाने के प्रभारी सुधीर कुमार पर भी कार्रवाई की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल में समिति के सचिव सिद्धार्थ कलहंस, उपाध्यक्ष मो. ताहिर, कार्यकारिणी सदस्य भास्कर दुबे, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार, अनिल अवस्थी, अविनाश शुक्ला, विमल किशोर पाठक आदि शामिल थे. उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) ने भी पत्रकार, लेखक, कवि, चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता राजीव चतुर्वेदी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उपजा के प्रांतीय अध्यक्ष रतन कुमार दीक्षित व प्रांतीय महामंत्री रमेश चन्द्र जैन ने राजीव चतुर्वेदी की मौत की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. समाचार एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख प्रमोद गोस्वामी ने राजीव चतुर्वेदी की संदिग्ध मौत को असहनीय बताया. उपजा के प्रांतीय उपाध्यक्ष पत्रकार सर्वेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार दादा पीके राय, पीबी वर्मा, वीर विक्रम बहादुर मिश्र, उपजा की लखनऊ इकाई के अध्यक्ष अरविन्द शुक्ला, लखनऊ इकाई के महामंत्री केके वर्मा, उपाध्यक्ष सुशील सहाय, भरत सिंह, रत्नाकर मौर्य, कोषाध्यक्ष मंगल सिंह, मंत्री अनुराग त्रिपाठी, एसबी सिंह, विकास श्रीवास्तव, पूर्व सूचना आयुक्त वीरेन्द्र सक्सेना, प्रभाकर शुक्ल, डॉ. मत्स्येन्द्र प्रभाकर, रवीन्द्र जायसवाल, सुनील टी त्रिवेदी, तारकेश्वर मिश्र समेत कई पत्रकारों ने राजीव चतुर्वेदी की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है. ■

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

महिला सिपाही से सामूहिक दुष्कर्म पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खफा

जब पुलिस ही करे पुलिस का शिकार

सूफी यायावर

जहां थानों में पत्रकारों की हत्या की जाती हो और महिला को जिंदा फूंका जाता हो, जहां पुलिसवाले ही अपनी सहकर्मी महिला सिपाही के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हों, उस राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं. जिस राज्य में पुलिस आपराधिक आचरणों पर उतरी हो, वहां कानून व्यवस्था का जिम्मा कौन तंत्र संभाले, अब तो उत्तर प्रदेश में यह सवाल गहरा रहा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस जारी कर यह सांकेतिक सवाल उछाल दिया है कि पुलिस वाले ही दुष्कर्मी हो जाएं और पुलिसवाली ही उसकी भुक्तभोगी हो जाएं, तो इसकी सफाई में शासन तंत्र का तर्क क्या है? झांसी में ड्यूटी करने आई इटावा की सिपाही के साथ पिछले दिनों हुए बर्बर सामूहिक दुष्कर्मकांड के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अभी झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जवाब-तलब किया है, लेकिन आयोग इसके आगे की कार्रवाई में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है. इटावा की सिपाही के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म में पुलिसकर्मी ही शामिल थे. बाद में गंभीर हालत में महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

झांसी में कुछ सिपाहियों द्वारा पिछले दिनों एक महिला सिपाही के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झांसी के एसएसपी को नोटिस जारी कर इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे सबसे वीभत्स अपराध करार दिया है और कहा है कि जिस प्रदेश में पुलिस के लोग पुलिस विभाग की ही महिला कर्मचारियों के साथ ऐसा अपराध करते हों, उस प्रदेश के आम लोगों की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है.

झांसी के आगे मऊरानीपुर के जल विहार मेले में ड्यूटी करने आई इटावा की महिला सिपाही से चलती गाड़ी में दो सिपाहियों और पुलिस ड्राइवर ने गैंगरेप किया. दुष्कर्म का आरोपी एक सिपाही झांसी कोतवाली और दूसरा सिपाही औरैया में तैनात है. कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडेय के आदेश पर इटावा के महिला थाने में मुकदमा दर्ज करके पीड़ित महिला सिपाही का मेडिकल परीक्षण कराया गया था. मऊरानीपुर के मशहूर जल विहार मेले में बाहरी जिलों से खासी तादाद में फोर्स मंगाई गई थी. सामूहिक दुष्कर्म की शिकार महिला कांस्टेबिल इटावा जिले से आई थीं. ड्यूटी से लौटते समय आरोपी सिपाहियों और पुलिस ड्राइवर ने झांसा देकर उन्हें अपने पुलिस वाहन में बैठा लिया. झांसी के रास्ते पर करीब 25 किलोमीटर आने के बाद कोतवाली में तैनात आरोपी सिपाही ने चालक को गाड़ी जंगल के रास्ते में ले जाने को कहा. पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन चालक नहीं माना, उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार ली. जंगल में ले जाकर दोनों सिपाहियों और पुलिस ड्राइवर ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इस घटना की एफआईआर झांसी में दर्ज नहीं हुई, जबकि घटनास्थल झांसी है. आईजी के आदेश पर इटावा की एसएसपी मंजिल सैनी ने अपने जिले में एफआईआर दर्ज कराई. आरोपी सिपाहियों अजय यादव, राजा भैया और पुलिस ड्राइवर के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन झांसी के एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे लगातार यह कहते रहे कि उनके पास इटावा से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है. जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सूचना पहुंच गई और आयोग ने इसे संज्ञान में लेकर झांसी के एसएसपी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी भी कर दी. आयोग के सूत्रों ने कहा कि इस मामले में सीधे राज्य सरकार से जवाब-तलब किए जाने की तैयारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भटकाव के कारण मारे भी जा रहे हैं पुलिसकर्मी

नेताओं की सोहबत में पुलिसकर्मियों के भटकाव के कारण स्थिति यह हो गई है कि पुलिसवालों पर ही खतरा सवार हो गया है. पुलिस का मनोबल इतना कमजोर हो गया है कि अपराधी अब पुलिस वालों को बड़े बेखौफ तरीके से अपना निशाना बना रहे हैं. अपराधियों-माफियाओं की खुली चुनौती है कि या तो पुलिस उनके लिए काम करे या मरने के लिए तैयार रहे. अखिलेश सरकार को सत्ता में आए करीब साढ़े तीन साल हो चुके हैं. इस दरम्यान प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत यह रही कि पुलिस पर अपराधियों के हमले की साढ़े छह सौ घटनाएं घटीं, जिसमें करीब 70 पुलिसकर्मी मारे गए और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जख्मी हुए. यह आंकड़े महज बानगी भर हैं, जबकि स्थिति इससे भी खौफनाक है. ये वे आंकड़े हैं, जो सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद सामने आए हैं. सैकड़ों ऐसे भी मामले हैं, जो किसी न किसी प्रभाव के चलते दबा दिए गए. आम जनता को सुरक्षा की गारंटी देने वाले पुलिसकर्मी ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं, तो कैसे संभले कानून व्यवस्था! सहारनपुर, इटावा, बरेली, इलाहाबाद और फिरोजाबाद जैसी तमाम जगहों पर 2012 से अब तक बदमाशों और भीड़ के हमले में करीब 70 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब पुलिसवालों पर हाथ उठाते और गोलियां चलाते नहीं डरते. इसके बावजूद इन हालातों से निपटने के कोई पुख्ता उपाय नहीं किए गए. ■

शराबी, जुआरी और अपराधी हैं पुलिस वाले!

जब पुलिस वाले ही अपराध में लिप्त हों, तो कानून व्यवस्था का हाल बेहाल होगा ही. यह कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत है. आधिकारिक तथ्यों के अलावा पुलिस महकमे के मुखिया भी इस बारे में लगातार यह स्वीकार करते रहे हैं कि यूपी पुलिस अपराधियों का अड्डा बन गई है. आधिकारिक तथ्य यह है कि गंभीर अपराध में लिप्त उत्तर प्रदेश पुलिस के तकरीबन ढाई सौ पुलिसकर्मी प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद हैं. करीब सवा सौ पुलिसकर्मी तो दोषी मुजरिम हैं और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं. एक पुलिसकर्मी फांसी का सजायाफ्ता कैदी है. यह आधिकारिक आंकड़ा कुछ अर्सा पहले का है. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अपराध की बढ़ोत्तरी के साथ ही यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है.

यूपी पुलिस के डीजीपी जगमोहन यादव ने अभी पिछले ही दिनों बाकायदा मीडिया के सामने यह स्वीकार किया कि दुष्कर्म की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है. डीजीपी के हाथ खड़े कर देने से प्रदेश की हालत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है. मौजूदा डीजीपी के ठीक पहले प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे अरविन्द कुमार जैन ने तो स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही शराबी, जुआरी और अपराधी हैं. उन्होंने बैंकों की सुरक्षा में जांच के बाद ही पुलिसकर्मियों को तैनात करने की हिदायत दी थी, ताकि शराबी, जुआरी और अपराधी किस्म के पुलिसकर्मी बैंक की सुरक्षा में न लग सकें. उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ में पुलिस की संलिप्तता का बड़ा हाथ है. अपराध रोकने में नाकाम यूपी पुलिस की बेबसी का इससे अच्छा और हास्यास्पद उदाहरण और क्या होगा कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस अब हवन-पूजन का सहारा लेने लगी है. कानपुर में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए कुछ ही दिनों पहले चकेरी थाना इंचार्ज ने पंडित बुलाकर पूरे विधि विधान से थाने में हवन-पूजन कराया था और भगवान से अपराध रोकने की प्रार्थना की थी. जब पुलिस नेताओं की गायब भैंसें और मुर्गियां तलाशने में लगेंगी और ऐसे ही निम्नस्तरीय नेताओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगी, तो अपराध रोकने के लिए हवन-पूजन तो कराना ही पड़ेगा. ■

ओवरलोडेड वाहनों पर कैसे हो नियंत्रण, परिवहन विभाग के छूट रहे पसीने

सुरक्षा दो, परिणाम लो

अखिलेश्वर पांडेय

उत्तर प्रदेश की सड़कों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदहाल ही होती जा रही है. इसके लिए ओवरलोडेड वाहन ही खासतौर से जिम्मेदार हैं. अधिकारी ओवरलोडेड वाहनों के संचालन को रोकने की प्रभावी कार्रवाई करें, तभी कुछ स्थिति बदलेगी. लेकिन सुरक्षा के अभाव में कार्रवाई नहीं हो पाती. परिवहन दस्तों पर हमले या सड़क पर कुचल डालने की घटनाएं आम हैं. कुछ दिन पहले सूबे के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण करने को कहा था. मंत्री के निर्देश के बाद अब सम्भागीय परिवहन विभाग के अधिकारी असमंजस में हैं कि आखिर किया क्या जाए? ओवरलोडेड वाहनों पर किस तरह से नियंत्रण बनाया जाए. विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वाहनों पर लोडिंग का काम जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र का अंग है और इसे रोकने के लिए सक्षम अधिकारी भी वही हैं. ऐसे में लोडिंग प्वाइंट पर ओवर लोडिंग को आरटीओ भला कौन सी तकनीक अपनाकर रोक सकता है. बेहतर है कि संबन्धित जिले के जिलाधिकारी को जहां पर वाहन लोड होते हैं, वहीं पर उन्हें नियंत्रित करने का आदेश जारी करना चाहिए.

दरअसल, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गाड़ियों पर उसकी परिवहन क्षमता से ज्यादा माल लाद दिया जाता है, जो मानकों से बनी सड़कों से ज्यादा होता है. ऐसी दशा में सड़कों पर लोड ज्यादा पड़ता है और सड़कें टूटने लगती हैं. ऐसा सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलने वाली गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि मौरंग, गिट्टी और बालू की ढुलाई करने वाले ट्रकों के लिए भी लागू होती है. केंद्र सरकार के एक आदेश का हवाला देते हुए वाहन मालिकों ने ट्रकों पर ओवरलोडिंग का खेल शुरू कर दिया था. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी है कि दरअसल यह सारा खेल खनिज विभाग का है और इसमें जिलों के जिलाधिकारी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. परिवहन क्षमता से ज्यादा माल न लोड हो, ओवरलोडिंग रुक पाना तभी संभव है. इसे लोडिंग प्वाइंट से रोका जाए और इसे जिलाधिकारी ही नियंत्रित कर सकते हैं. अधिकारी ने बताया कि एक बार जब सड़क पर ओवरलोडेड वाहन आ जाता है, तो परिवहन विभाग उसे पकड़ कर जुर्माना लगाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बेहतर यही है कि वाहनों की परिवहन क्षमता से ज्यादा माल लोड ही न होने दिया जाए. एक बार जब वाहनों पर माल लोड हो जाता है, तो हजारों की संख्या में गाड़ियां सड़कों पर आती हैं. ऐसी दशा में सभी गाड़ियों को चेक करना व उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया में ज्यादा समय बर्बाद होता है. जब तक दो गाड़ियों की चेकिंग होती है, दस गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं. सभी गाड़ियों को एक साथ चेक नहीं किया जा सकता है.

चेकिंग दस्ते की कमी

ओवरलोडेड वाहनों को चेक करने में सबसे बड़ी बाधा चेकिंग दस्ते की कमी होना है. हर जिले में एक या दो चेकिंग दस्ते हैं. इन दस्तों में तीन सिपाही एक सुपरवाइजर और एक ड्राइवर होता है. कहीं-कहीं पर, तो यह संख्या मात्र एक या दो तक ही सीमित है ऐसी दशा में गाड़ियों की चेकिंग कैसे हो सकती है. इसके अलावा उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं है. उप परिवहन आयुक्त अरविन्द कुमार पांडेय ने इस बारे में बताया कि लोक निर्माण मंत्री के आदेशों पर प्रदेशभर में गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का ही असर है कि सड़कों पर ओवरलोडेड वाहन 70 फीसदी तक कम हुए हैं. लेकिन इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में स्टॉफ की कमी आड़े आ रही है.

जान का खतरा होने से चेकिंग में खलल

परिवहन विभाग का प्रवर्तन दस्ता रात में ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने में इस वजह से भी कतराता है, क्योंकि रात में अक्सर ओवरलोडेड वाहनों की स्पीड काफी तेज होती है. ऐसे में अगर प्रवर्तन दस्ता उन्हें रुकने के लिए इशारा भी करता है, तो वे दस्ते के वाहन की ओर ही गाड़ी घुमाकर टक्कर मारने की कोशिश करते हैं, जिससे जान का खतरा पैदा हो जाता है. ऐसे कई हादसे पिछले कई सालों में हो चुके हैं.

एआरटीओ पर हमला

सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन सुरेश कुमार वर्मा तकरीबन एक साल पहले शहर में ही रात में राजधानी के एक रूट पर चेकिंग अभियान चला रहे थे इस दौरान उन्होंने जायरीनों से भरी एक बस को हाथ देकर रोका. लेकिन बस चालक ने वहां से बच निकलने के लिए एआरटीओ दस्ते पर ही सीधे बस चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें एआरटीओ तो घायल हो ही गए एआरटीओ के साथ ही आरक्षी विधान चंद्र त्रिपाठी को भी गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं मौके से जान बचाकर भागे एआरटीओ सुरेश कुमार वर्मा पर आरोप लगा कि वे दस्ते को छोड़कर भाग गए थे जांच में दोषी पाते हुए उन पर निलम्बन की कार्रवाई की गई.

ट्रक रोकने पर पत्थरबाजी

सरोजनीनगर की तरफ से आ रहे रात में ओवरलोडेड ट्रक को एआरटीओ दस्ते ने कुछ महीने पहले रुकने के लिए हाथ दिया, तो चालक ने ट्रक को रफ्तार दे दी. एआरटीओ दस्ते ने कुछ दूर जाकर ट्रक को पकड़ लिया लेकिन इतनी ही देर में चालक ने फोन पर ट्रक मालिक के साथ ही कई गुंडों को बुला लिया, जिसके बाद एआरटीओ प्रवर्तन दस्ते पर पथराव कर दिया गया, जिससे वे सभी जान बचाकर वहां से भाग निकले. ■

feedback@chauthiduniya.com

धंधा बन गया है ट्रकों का ओवरलोड

ऑल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन (एकोगोआ) ने देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन आयुक्तों को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि वे ओवरलोडेड ट्रकों को कमाई का जरिया न बनाएं. ओवरलोडेड गाड़ियों को चेक करने और जुर्माना वसूल कर छोड़ देने की कार्रवाइयों से ओवरलोड की समस्या सुधरने के बजाय धंधा बन गई है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है. मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा 113 (3) में यह प्रावधान है, कोई व्यक्ति किसी मोटरयान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान में न तो चलवाएगा और न चलाने देगा, जिसका लदान सहित भार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्टयान सहित सकल भार से अधिक है.

इस प्रावधान से स्पष्ट है कि ओवरलोडेड वाहन चलाना गैरकानूनी है. इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-114 में मोटर व्हीकल विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह धारा-113 का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. इस धारा में लिखा है, वह ड्राइवर को लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह अधिक भार को अपने जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता. इसी धारा की उपधारा-2 में यह भी कहा गया है कि अधिकारी ओवरलोडिंग के बाबत मोटर वाहन परमिट पर भी इसका विवरण लिखेगा और इसके अलावा लिखित रूप में उस प्राधिकारी को भी सूचित करेगा, जिसने वह परमिट जारी किया था. इन धाराओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून मोटर व्हीकल अधिकारियों को यह निर्देश देता है कि वह ओवरलोडेड गाड़ियों का माल मौके पर ही उतरवाकर गाड़ी को आगे जाने दें. लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और इसी कारण ओवरलोडिंग नहीं रुक रही है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि ओवरलोडेड वाहनों से माल उतरवाने में पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और किसी भी हाल में कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए. लेकिन राज्य सरकार इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही. ■

सोशल-पॉलिटिक्स की जगह साइबर-पॉलिटिक्स की धूम

शिवपाल हाईटेक हुए

दीनबंधु कबीर

सोशल मीडिया की तरफ नेताओं की मची घुड़दौड़ में अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भी शरीक हो गए हैं. भतीजा पहले ही सोशल मीडिया के ट्रैक पर सरपट दौड़ रहा था, तो चाचा इसमें क्यों नहीं शामिल होते! वैसे शिवपाल आम लोगों से रूबरू होते रहते हैं और जनता में वे मुलायम की टच-पॉलिटिक्स की विरासत संभालने वाले नेता के बतौर माने जाते हैं. अखिलेश यादव ने इस भावनात्मक राजनीतिक-दीक्षा से खुद को वंचित रखा और साइबर-पॉलिटिक्स को बेहतर समझा. अखिलेश यादव को सारा समाज और सारा सामाजिक सरोकार सोशल मीडिया पर ही दिखता है. बहरहाल, स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट-पॉलिटिशियन बनने की दौड़ को सियासी अनिवार्यता समझते हुए शिवपाल सिंह यादव ने भी खुद को फेसबुक और ट्विटर से जोड़ने और अपनी वेबसाइट शुरू करने की मुनादी कर दी.

शिवपाल ने अपनी वेबसाइट की शुरुआत करने के साथ-साथ अपने फेसबुक तथा ट्विटर अकाउंट के बारे में भी पिछले दिनों औपचारिक घोषणा की. अपनी वेबसाइट शिवपालयादवडॉटकॉम' की शुरुआत करते हुए शिवपाल ने कहा कि वे अपनी वेबसाइट के अलावा फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों से जुड़े रहेंगे. लोग वेबसाइट के माध्यम से उनके विभागों, उनकी परियोजनाओं तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में जान सकेंगे. सोशल मीडिया जगत में कदम रखने वाले लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन का जिम्मा इमेज बिल्डिंग फर्म आईलीड गुरु' संभालेगी.

शिवपाल ने इस मौके पर मोबाइल नंबर 9696172737 भी जारी किया. इस नंबर पर मिस कॉल करके कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ सकेगा. उन्होंने कहा कि वेबसाइट तथा अन्य सोशल मीडिया माध्यम अपनाने का उनका मकसद प्रदेश की जनता की समस्याओं तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना है. प्रभावी संवाद में सोशल मीडिया की भूमिका का जिक्र करते हुए शिवपाल ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों से जुड़कर सरकार और उसके कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो गया है. इस मौके पर आईलीड गुरु के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विकास साहनी तथा अधिशासी निदेशक हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद थे. आईलीड गुरु कुछ ही दिनों पहले पूर्व आईआईटियन और आईआईएम के पूर्व छात्रों ने बनाई है. यह एक वेब डिजाइनिंग कंपनी है. कंपनी के अधिशासी निदेशक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि शिवपाल सिंह यादव का फेसबुक एकाउंट, ट्विटर हैंडल, वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर का संचालन उनकी कंपनी करेगी. सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सीधे शिवपाल सिंह यादव से जुड़ सकेंगे. लोग उनसे सवाल कर सकेंगे और शिवपाल सिंह यादव उनका जवाब देंगे.

शिवपाल यादव ने कहा कि नई तकनीक का लाभ किसानों और गरीबों को मिलना चाहिए. जो अच्छे काम हुए हैं, उनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है. आज के समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं इसलिए अपनी समस्याओं को लोग सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं. गांवो में रहने वाले लोग भी अब अपनी समस्याओं को चाहे वो ट्यूबवेल की खराबी हो या खेत में पानी न पहुंचने की समस्या हो, उसे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेज सकते हैं. इसके माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित करके सरकार की योजनाओं, काम और प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा. शिवपाल ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहरों और सड़कों की दिशा में बहुत काम किया है. नहर व्यवस्था को दुरुस्त करने के कारण ही किसान इस बार सूखे की समस्या से बचे रहे. बरसात कम होने के बावजूद उनके खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिला. शिवपाल बोले कि 21वीं सदी समाजवाद की सदी होगी. हम अपनी विरासत और बुजुर्गों से मिले ज्ञान और अनुभव को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को स्थानान्तरित कर सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

> **शिवपाल यादव ने कहा कि नई तकनीक का लाभ किसानों और गरीबों को मिलना चाहिए. जो अच्छे काम हुए हैं, उनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है. आज के समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं इसलिए अपनी समस्याओं को लोग सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं. गांवो में रहने वाले लोग भी अब अपनी समस्याओं को चाहे वो ट्यूबवेल की खराबी हो या खेत में पानी न पहुंचने की समस्या हो, उसे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेज सकते हैं.**

पीएम की नकल कर सीएम भी साइबर-सुरंग में

नेताओं को लग रहा है कि सोशल मीडिया राजनीति का नक्शा बदलने में सक्षम हो रहा है. नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद से होते हुए देश के प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में सोशल मीडिया का अभूतपूर्व योगदान माना जा रहा है, लिहाजा खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद सोशल मीडिया नेताओं का अनिवार्य फैशन बन गया है. नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने नौजवानों को उनकी मौज-मस्ती वाले अड्डे यानी सोशल मीडिया पर जाकर घेर लिया. अब यह चलन के रूप में तब्दील हो गया है. नरेंद्र मोदी ने इसे अभियान की शक्ल में बदल दिया. अब तो सोशल मीडिया देश की राजनीति को बदलने में भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है. नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हिंदी, उर्दू के अलावा मराठी, उड़िया, बांग्ला, तमिल, असमिया, कन्नड़, मलयालम में भी ट्वीट करते हैं. जाहिर है इसके लिए आईटी विशेषज्ञों की मुकम्मल टीम है जो यह काम करती है. सोशल मीडिया के जरिए राजनीति कैसे बदल रही है इसका अंदाजा सरकारों को भी लग रहा है. देश की ज्यादातर सरकारें अब सोशल मीडिया के जरिए तुरंत अपनी उपलब्धि या फिर अपने खिलाफ दुष्प्रचार को खारिज करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं.

इसकी नजाकत देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद तो सोशल मीडिया के सारे माध्यम व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल तो करते ही रहे, प्रदेश सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के लिए भी उन्होंने वेबसाइट और पोर्टल वगैरह लॉन्च किए. कुछ ही अर्सा पहले अखिलेश ने यूपी-360 न्यूज पोर्टल की शुरुआत की थी. उसी दिन सोशलिस्ट फैक्टर पत्रिका और समाजवादी श्रवण यात्रा की वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी. अप्रवासी भारतीयों के लिए भी मुख्यमंत्री ने यूपीएनआरआईडॉटकॉम नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट के माध्यम से एनआरआई को जानकारी देने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का इरादा प्रकट किया गया था. हालांकि इसके बाद उस विभाग के मंत्री मधुकर जेटली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मोबाइल पर अपना एप्स' भी जारी कर चुके हैं. ट्विटर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एप्स ट्रेंडिंग में नंबर एक है तथा ऑल इंडिया ट्रेंडिंग में डिजिटल सीएम नंबर भी एक है. इसमें अखिलेश यादव की उपलब्धियां और कार्यक्रम हैं. यह मोबाइल एप्स' समाजवादी अखिलेश के नाम से जारी किया गया. यह मुख्यमंत्री अखिलेश का अधिकृत एप्स है. अखिलेश यादव के इस एप्स' में समाजवादी पार्टी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. इसके साथ ही इसमें सोशल मीडिया और पार्टी नेताओं का ब्यौरा भी दिया गया है. इसे प्रमोट करने के लिए अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडिल का सहारा लिया है. इस एप्स में फीडबैक की खास व्यवस्था की गई है. स्मार्टफोन में एंड्रॉयड और विंडोज सॉफ्टवेयर प्रयोग करने वाले लोग इस एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं. दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बड़ी बुद्धिमानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट-पॉलिटिक्स की नकल कर रहे हैं. सोशल साइट्स के इस्तेमाल की बात हो या पेपरलेस ऑफिस बनाने की, स्वच्छता अभियान का मसला हो या मेक इन इंडिया का या मन की बात के लिए रेडियो के इस्तेमाल का, सबको अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी रंग देकर उतारने का प्रयास किया. 10 जून 2014 को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सचिवों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सारा काम कम्प्यूटर पर समेट कर सरकारी दफ्तरों को कागज-रहित बनाएं. ठीक तीन दिन बाद अखिलेश यादव ने भी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय को कागज-रहित बनाएं. सात नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो अखिलेश यादव ने स्वच्छ और हरित उत्तर प्रदेश का नारा देकर ऐसा ही अभियान शुरू कर दिया. तीन अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने रेडियो पर जनता से मन की बात शुरू की, तो जनवरी 2015 में सैफई के लोगों से बात करने के लिए मुख्यमंत्री ने रेडियो सैफई शुरू करा दिया. यह सब देखते हुए शिवपाल यादव ने भी स्मार्ट-पॉलिटिशियन बनने की ठानी और साइबर-पॉलिटिक्स शुरू कर दी. ■

देश में असहिष्णुता का ऐसा माहौल कभी नहीं था : प्रो. पाठक

आज जैसा असहिष्णुता का माहौल है, ऐसा कभी नहीं था. उन्होंने एमएम कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और पानसरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मात्र अपनी बात कहने पर उन लोगों को गोली मार दी गई या घरों में घुसकर गला काट दिया गया. सरकार मूक दर्शक बनी रही.

रेनू शर्मा

उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन और खनन के मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों की असफलता एक बार फिर बेपर्दा हुई है. प्रख्यात पर्यावरणविद् और इतिहासकार प्रो. शेखर पाठक ने देश में असहिष्णुता और उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन और खनन के मामलों में राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य होने से आहत होकर पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की है. नैनीताल फिल्म फेस्टिवल में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा की. पाठक ने जिस समय यह घोषणा की, उस समय उनका जल, जंगल, जमीन और खनन के मामलों में वेदना पूरी तरह से झलक उठी, जिसके लिए वे राज्य सरकार के साथ ही केन्द्र की मोदी सरकार को कम जिम्मेदार नहीं मानते. इससे पूर्व पिथौरागढ़ डिग्री कालेज के प्रो. अजय शुक्ल डॉ.अंबेडकर फेलोशिप लौटा चुके हैं. उत्तराखंड राज्य का गठन जल, जंगल, जमीन और खनन के मामले में जनांदोलन का परिणाम माना जाता है, अब तक की 15 वर्षों में बनी सभी सरकारों ने इस राज्य की जनता की मूल भावना से लगातार छल किया.

प्रो. पाठक ने कहा कि देश में आज जैसा असहिष्णुता का माहौल है, ऐसा कभी नहीं था. उन्होंने एमएम कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और पानसरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मात्र अपनी बात कहने पर उन लोगों को गोली मार दी गई या घरों में घुसकर गला काट दिया गया. सरकार मूक दर्शक बनी रही. ■

feedback@chauthiduniya.com

गैरसैंण हमारी मातृशक्ति के संघर्ष का प्रतीक है : हरीश रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारी भावना गरीब, काश्तकारों, शिल्पकारों व सभी वंचित वर्गों के साथ है. जिन क्षेत्रों में पहले प्राथमिक विद्यालय भी नहीं होते थे, वहां निजी विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं.

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं के केन्द्र बिन्दु में गैरसैंण, गांव और गंगा है. उन्होंने कहा कि हम निश्चित रोडमैप के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, महिला विकास और सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. हम कह चुके हैं कि हमारी नीतियां 'हिमालयोन्मुखी' होंगी. गंगा, हिमालय की रक्षा के साथ हम हिमालयी गांवों से हो रहे पलायन को राक कर ही दम लेंगे. हरीश रावत ने कहा कि जल्द ही यहां मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस शुरू किया जाएगा. उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है. हमारी सरकार राज्य की जनता की जनभावना के अनुसार काम कर रही है. हमारी मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के समय राजधानी गैरसैंण की आवाज बुलंद की थी. इनमें से कुछ के सकारात्मक परिणाम भी मिलने लग गए हैं. गैरसैंण विकास के मुख्य केंद्र के तौर पर उभर रहा है. गैरसैंण हमारी मातृशक्ति के संघर्ष का प्रतीक है. हम सभी को गैरसैंण भावना को समझना चाहिए. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारी भावना गरीब, काश्तकारों, शिल्पकारों व सभी वंचित वर्गों के साथ है. जिन क्षेत्रों में पहले प्राथमिक विद्यालय भी नहीं होते थे, वहां निजी विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं. हम गांवों की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं. ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके. हम अवसरहीनता को अवसरयुक्तता में बदल रहे हैं. गैरसैंण के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत उपस्थित स्थानीय जनता को संबोधित उनकी दिल जीतने की कोशिश की. उन्होंने चार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. उनमें 11 लोकार्पण व 10 शिलान्यास किए गए हैं. इस सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही. ■

feedback@chauthiduniya.com

नाकाम रही भाजपा

उत्तराखंड भाजपा इस सत्र के अवसर पर हर स्तर से हरीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा नाकाम रही. प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने हरीश पर एक बार फिर आबकारी घोटाले में सीडी कांड का कीचड़ उछाल कर हरीश रावत को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की. सदन में भाजपा विधायकों ने हंगामा भी किया. नेता प्रतिपक्ष सहित पूरी भाजपा मुख्यमंत्री पर कीचड़ उछालने में कोई को कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बावजूद इसके हरीश रावत अपने मकसद में कामयाब हुए. ■

पंचायत चुनावों में सपा पहले, बसपा दूसरे और भाजपा तीसरे स्थान पर रही

सपा की जीत सपा के लिए सीख

केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेजान और बेअसर साबित हुई. सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे कम जीत हासिल कर पाई, इससे यही साबित हुआ कि भाजपा के सांसद मोदी-हवा में जीते थे, उनकी जमीन पर कोई पकड़ नहीं है.

प्रभात रंजन दीन

पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल सीधे हिस्सा नहीं ले सकते, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव हुए, उसमें पार्टियां खुलेआम मैदान में उतरीं और पंचायत चुनाव में अपनी-अपनी प्रतिष्ठा को संलग्न किया. प्रत्याशियों को औपचारिक तौर पर पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीदवारों ने खुलेआम अपनी-अपनी पार्टियों के बैनर-पोस्टर लगाए और उनके समर्थन में पार्टी के नेता प्रचार-प्रसार में जुटे रहे. पार्टियों, खास तौर पर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार जमकर चुनाव लड़े और परिवारवाद के लोकतंत्र को और पुख्ता करने के ईंट-गारे जोड़े, लेकिन अधिकांशतः धराशाई हो गए. समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई से लेकर सत्ता शीर्ष तक काबिज होने की प्रक्रिया में हैं. मुलायम परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग पंचायत चुनाव में जीते. यह अलग बात है कि सपा के कई आला नेताओं के रिश्तेदारों को पंचायत चुनाव में सौंधी मिट्टी की गंध सुंघा दी गई. उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को संख्या के हिसाब से जीत तो सबसे अधिक मिली, लेकिन नेताओं-मंत्रियों के नजदीकी रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा-नीत हार रेखांकित की जाने वाली है. यहां तक कि मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में जीत की जगह नहीं बना पाई. बहुजन समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में खूब सीटें बटोरीं और दूसरे स्थान पर रही. बसपा की जीत को अहम माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सत्ता-शक्ति के शामियाने में बसपा का जीतना सियासत की जमीन के अंदर चल रहे कंपन को महसूस करा रहा है. इस जमीनी चुनाव में कांग्रेस ने अपना वजूद खोने का क्रम जारी रखा है. भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रही और इस स्थान ने यह घोषणा की कि घास की जड़ को पानी चाहिए, मट्ठा नहीं.

राजनीतिक समीक्षा का पतंग उड़ाने वाले स्वयंभू-समीक्षक पंचायत चुनाव के परिणाम को विधानसभा चुनाव के असर पर चस्पा करने में लगे हैं. लेकिन वे पंचायत स्तर के चुनावों में सत्ता-शक्ति के सीधे इस्तेमाल के सरल गणित को रेखांकित करने से कन्नी काट लेते हैं. सपा के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार हारे, तो उसके पीछे सत्ता-दंभ जनित अतिरिक्त-आत्मविश्वास दोषी है. पंचायत चुनाव में अधिकांशतः जिस तरह के लोग चुन कर आए हैं, उनका परम लक्ष्य लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई को मजबूत करना नहीं, बल्कि उसे खोखला करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव वाराणसी के जयापुर से भाजपा प्रत्याशी रिंकू सिंह की जगह बसपा प्रत्याशी गुड्डू तिवारी जीत गए. वाराणसी में जिला पंचायत की 48 सीटों में से भाजपा को महज आठ सीटें ही मिल पाईं. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भाजपा को 28 में से केवल चार सीटें मिलीं.

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को संख्या के हिसाब से जीत तो सबसे अधिक मिली, लेकिन नेताओं-मंत्रियों के नजदीकी रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा-नीत हार रेखांकित की जाने वाली है. यहां तक कि मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में जीत की जगह नहीं बना पाई.

दलों के दावे बेअंदाज

हर परिस्थिति में बयानों को यथानुकूल करने में माहिर नेताओं ने इन चुनावों के परिणाम पर भी बात-बहादुरी दिखाई. कांग्रेस तो इस स्थिति में ही नहीं है कि वह कोई बयान भी जारी कर पाए. तीसरे स्थान पर रही भारतीय जनता पार्टी ने हार को स्वीकार करने के बजाय कहा कि पिछली बार के मुकाबले हम 58 से 531 सीटों तक पहुंचे हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग और हिंसा से सत्ता पक्ष ने जबरन सीटें हथियाई हैं. बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 50 फीसदी सीटों पर बसपा जीती है. यह सीधा संदेश है कि सपा के गुंडाराज से जनता ऊब चुकी है. बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस चुनाव में बसपा नंबर एक पार्टी बनकर उभरी है. जीत भी काफी अंतर से हुई है. सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है.

सपा के मंत्रियों और नेताओं के रिश्तेदारों की पराजय और मुलायम के गढ़ में सपा प्रत्याशियों के धराशाई होने के यथार्थ की अनदेखी करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले कि सपा कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं के आभारी हैं. सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 80 प्रतिशत सपा प्रत्याशियों को मिली जीत और भाजपा-कांग्रेस की उनके प्रमुख गढ़ों में हुई हार से स्पष्ट है कि जनता ने सपा सरकार के काम को सराहा है. सपा 80 प्रतिशत जीत का दावा कर रही है और बसपा 50 प्रतिशत. भाजपा का दावा भी 25 प्रतिशत के आस-पास झूल रहा है. ओवैसी के जीते प्रत्याशियों समेत तमाम विजयी निर्दलियों का भी तो प्रतिशत है! यह सब प्रतिशत जोड़ दें तो उसके सौ के दायरे में रहने की अंकगणितीय-बाध्यता नेताओं की नैतिकता की तरह बांध तोड़ कर कहीं का कहीं कुलांचे मारती दिख रही है. नेताओं को सौ प्रतिशत का सामान्य गणित भी समझ में नहीं आता कि कम से कम, दावों और बयानों में गणितीय-मर्यादा बना कर रखें. ■

पंचायतें अब लोकतंत्र की जमीनी इकाई नहीं बल्कि भ्रष्टाचारतंत्र की सबसे निचली इकाई के रूप में तब्दील हो गई हैं. लिहाजा, पंचायत प्रतिनिधि दो साल में (विधानसभा चुनाव आने तक) जो गुल खिलाएंगे, उसकी सुगंध भी विधानसभा चुनाव पर असर दिखाएगी, इसे साथ-साथ समझते चलना चाहिए. सपा के कद्दावर नेताओं और मंत्रियों के रिश्तेदारों की हार, और उस हार के कारण तीव्र हुई अंदरूनी रार, परिवारवाद की होड़ की वजह से नीचे के नेताओं-कार्यकर्ताओं में बढ़ी नाराजगी और विद्रोह के भाव भी विधानसभा चुनाव में असर दिखाएंगे, इस समझदारी को भी साथ-साथ लेकर चलना चाहिए. जमीनी चुनाव में सपा नेताओं के भूमिसात होने का मतलब ही है कि आप जमीनी स्तर पर सत्ताधारी नेताओं के प्रति जनता में बढ़ते आक्रोश का तापमान मापते चलें. हालांकि अभी क्षेत्र और जिला पंचायतों के चुनाव ही हुए हैं और प्रधान और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने बाकी हैं. अभी जिला पंचायतों के 3112 पदों और ब्लॉक पंचायत के 77576 पदों के लिए चुनाव हुए हैं.

अभी तक हुए पंचायत चुनावों में दूसरे स्थान पर रही बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पंचायत चुनाव में समर्थन की रेबड़ियां बांट दी थीं. एक अराजकता का सृजन हो गया था, जिसमें कई-कई उम्मीदवार खुद को बसपा समर्थित बता कर मैदान में ताल ठोक रहे थे. कई जीते हुए उम्मीदवारों को भी विद्रोही बताया गया. लेकिन बसपा नेतृत्व ने समझदारी से बसपा के बैनर से जीते सारे प्रत्याशियों को अपना बताकर उन्हें पार्टी-सूत्र में बांध लिया और दूसरे स्थान का श्रेय लिया. केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेजान और बेअसर साबित हुई. सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे कम जीत हासिल कर पाई, इससे यही साबित हुआ कि भाजपा के सांसद मोदी-हवा में जीते थे, उनकी जमीन पर कोई पकड़ नहीं है. कांग्रेस तो राष्ट्रीय अस्मिता के साथ-साथ प्रांतीय अस्तित्व भी खोती जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं. इसलिए राहुल और सोनिया के गढ़ में कांग्रेसी प्रत्याशी पंचायत चुनाव हार गए, इसमें कोई अप्रत्याशित बात नहीं. हां, मुलायम और मोदी के गढ़ में उनकी पार्टियों के समर्थित प्रत्याशी पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाए, यह गंभीर बात है.

अब जरा पंचायत चुनाव के परिणामों का विस्तार-दर्शन भी करते चलें. सपा के वरिष्ठ नेता व पैक्सफेड के चेयरमैन तोताराम बोगस वोट करते पकड़े और फिल्माए गए थे. पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जनता ने अपनी कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई. परिणाम आया, तो पराजितों की लिस्ट में बीसवां स्थान देखकर तोताराम के तोते उड़ गए. अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद की पत्नी और बेटा दोनों ही चुनाव हार गए. मंत्री रामपाल सिंह की बेटियां बीडीसी का चुनाव हार गईं. मंत्री सुरेंद्र पटेल के भाई महेंद्र पटेल की पत्नी शकुंतला देवी बीडीसी का चुनाव हार गईं. सपा की विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा की बेटी चुनाव हार गईं. राज्य मंत्री शंखलाल मांझी की पत्नी अंजलि और राजेंद्र यादव की बेटी चुनाव हार गईं. मंत्री रामभुआल निषाद के भाई की पत्नी चुनाव हार गईं. कारागार राज्य मंत्री रामपाल सिंह की दोनों बेटियां चुनाव हार गईं. मंत्री मनोज पांडेय के भाई चुनाव हारे तो राम करन आर्य के पुत्र भी पराजितों की लिस्ट में शुमार हो गए. राज्यमंत्री हाजी रियाज अहमद के दो भाई और दामाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए. राज्यमंत्री राजीव कुमार सिंह के भतीजे चुनाव हार गए. सपा विधायक पूर्णमासी देहाती की पत्नी और बहू चुनाव हार गईं. राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह के भाई घनश्याम सिंह जिला पंचायत का चुनाव हार गए.

बहरहाल, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव वाराणसी के जयापुर से भाजपा प्रत्याशी रिंकू सिंह की जगह बसपा प्रत्याशी गुड्डू तिवारी जीत गए. वाराणसी में जिला पंचायत की 48 सीटों में से भाजपा को महज आठ सीटें ही मिल पाईं. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भाजपा को 28 में से केवल चार सीटें मिलीं. राजनाथ के गोद वाले गांव बैंती में भी भाजपा का प्रत्याशी जीत नहीं पाया. ललितपुर में उमा भारती द्वारा गोद लिए गए गांव पवा में भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीत पाया. अमेठी में कांग्रेस 36 सीटों में से केवल आठ सीटों पर जीत दर्ज कर पाई. अमेठी में सपा को 17, भाजपा को चार और बसपा को आठ सीटें मिलीं.

असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन ने पंचायत चुनाव में चार सीटें जीत कर सियासतदानों का ध्यान खींचा. ओवैसी के प्रत्याशी की जीत सपा के लिए बड़ा सबक-संकेत है. मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी कैलाश गौतम जीते. ओवैसी की पार्टी ने बलरामपुर में दो और मुजफ्फरनगर में भी एक सीट जीती. मुलायम के गोद लिए हुए गांव तमौली में भी सपा प्रत्याशी हार गया. मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव के दृष्टिकोण से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन की जीत को सपा के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com